ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

dhyeyaias.com

यूपीपीसीएस
मुख्य परीक्षा 2024
(करंट अफेयर्स संकलन)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

(मुख्य परीक्षा के लिए
पूरक अध्ययन सामग्री)

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ALIGANJ

UPSC (IAS) Foundation Batch

9th June 2025

Timing: 08:30 AM

UP - PCS Foundation Batch

11th June 2025

Timing: 09:00 AM | 06:00 PM

FOR
ONLINE COURSES

IAS- 9506256789, PCS - 7619903300

A-12 Sector-J, Aliganj, Lucknow

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे

भारत और पड़ोसी देश

पाकिस्तान

"आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्रांति: ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तकनीकी छलांग"

ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा चार दिनों तक चलाया गया एक महत्वपूर्ण सैन्य मिशन था, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) और पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों और सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन ने न केवल सैन्य कार्रवाई थी बल्कि इसने भारत की रक्षा तकनीकी क्षमताओं को भी उजागर किया। भारत ने इस दौरान सटीक, शक्तिशाली और समन्वित हमले किए।

भारतीय सेना की बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली की सफलता:

- ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था भारत की बहु-स्तरीय रक्षा प्रणाली, जिसमें शामिल थे:
  - काउंटर-मानवरहित हवाई प्रणाली (Counter-Unmanned Aerial Systems)
  - कंधे से दागे जाने वाले हथियार (Shoulder-Fired Weapons)
  - परंपरागत वायु रक्षा प्रणाली (Legacy Air Defence Weapons)
  - आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली (Modern Air Defence Weapon Systems)
- इस बहु-स्तरीय प्रणाली ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर देश के भीतर तक कई सुरक्षा घेरे बनाए, जिससे 9-10 मई, 2025 को पाकिस्तान के जवाबी हवाई हमलों से हवाई अड्डों और रसद स्थलों की सुरक्षा की जा सकी। पिछले एक दशक में सरकारी निवेश से निर्मित ये प्रणाली "फोर्स मल्टीप्लायर" की तरह काम कर रही हैं, जिससे नागरिक और सैन्य ढांचे सुरक्षित रहे।

अंतरिक्ष की रणनीतिक भूमिका: इसरो का उपग्रह नेटवर्क:

- भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इस अभियान में महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया। कम से कम 10 उपग्रह लगातार भारत की उत्तरी सीमाओं और 7,000 किलोमीटर की समुद्री सीमा की निगरानी कर रहे थे, जिससे वास्तविक समय में निगरानी और पहले से चेतावनी मिल सकी।
- ये उपग्रह ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों की संचालन क्षमता को बढ़ाते हैं क्योंकि ये निरंतर निगरानी और खुफिया जानकारी प्रदान करते हैं, जो समय पर खतरे का पता लगाने और जवाब देने में जरूरी हैं। अंतरिक्ष आधारित संसाधनों का रक्षा प्रणाली में एकीकरण भारत की समग्र सुरक्षा दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- यह असाधारण सटीकता जमीन और अंतरिक्ष आधारित तकनीकों को जोड़ने वाले उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन सिस्टम के कारण संभव हुई:
  - NavIC (नेविगेशन विद इंडियन कंस्टीलेशन): भारत की स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली, जो 10 से 20 सेंटीमीटर की सटीकता प्रदान करती है।
  - पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (Earth Observation Satellites): Cartosat, RISAT और EOS श्रृंखला के उपग्रह 25 से 30 सेंटीमीटर जितने छोटे वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम हैं।

- इन प्रणालियों के संयोजन से भारतीय हथियारों को मीटर से भी कम दूरी की सटीकता से लक्ष्य भेदन में सफलता मिलती है। उदाहरण के लिए, ब्रह्मोस (BrahMos), सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल, जो इस ऑपरेशन में उपयोग की गई, में उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली है जिसे वर्षों की स्वदेशी अनुसंधान से डीआरडीओ और इसरो ने विकसित किया है।
- मार्गदर्शन और नेविगेशन तकनीकों के महत्व को जून 2023 में DRDO के अनुसंधान चिंतन शिविर में 75 प्राथमिक तकनीकी क्षेत्रों में शामिल कर विशेष महत्व दिया गया।

The Indian drone market is projected to reach $11 billion by 2030, accounting for 12.2% of the global drone market.[9]

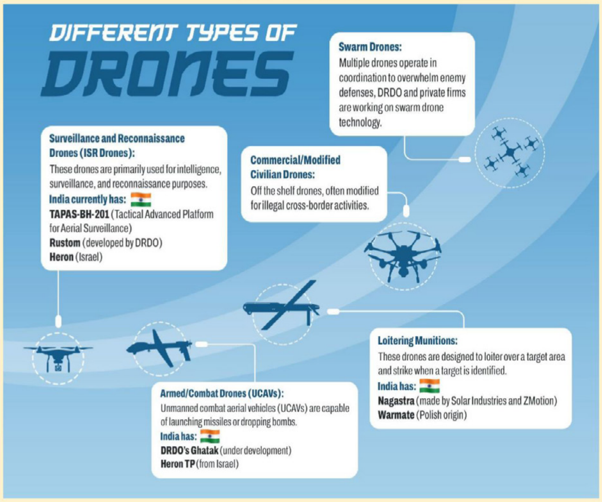

घातकता और विनाश की क्षमता:

- आतंकी ठिकानों और पाकिस्तानी वायु अड्डों की उपग्रह छवियों में देखे गए बड़े गड्ढे और लक्ष्य का पूर्ण विनाश भारतीय हथियारों की मारक क्षमता और विश्वसनीयता को प्रमाणित करते हैं। यह शक्ति भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) की देन है, जिसकी अगुवाई डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने की थी।
- इसके अलावा, भारत इस क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और नई तकनीकों का विकास कर रहा है, जैसे कि:
  - » गहराई तक भेदन करने वाले वारहेड (Deep Penetration Warheads)
  - » हरित विस्फोटक (Green Explosives)
  - » निर्देशित ऊर्जा हथियार (Directed Energy Weapons - DEWs): लेज़र आधारित प्रणालियाँ जो लक्ष्य को क्षति या निष्क्रिय करने में सक्षम हैं। इन्हें ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन को निष्क्रिय करने में संभवतः इस्तेमाल किया गया।
- वर्ष 2022 में निर्देशित ऊर्जा हथियारों (DEWs) को रक्षा मंत्रालय द्वारा उद्योग-आधारित विकास के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई थी। इस तकनीक का प्रदर्शन 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में भी किया गया।

स्वदेशी रडार और वायु रक्षा प्रणाली:

- हालांकि रूस की S-400 मिसाइल प्रणाली ने विश्व स्तर में सबका ध्यान आकर्षित किया है, भारत की वायु रक्षा प्रणाली में कई उन्नत स्वदेशी रडार और मिसाइल प्रणालियाँ शामिल हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह से समन्वित तरीके से काम कर रही थीं।
- मुख्य रडार प्रणालियाँ इस प्रकार हैं:
  - » **राजेन्द्र रडार:** एक बहु-कार्यात्मक फायर कंट्रोल रडार जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और मिसाइलों को निर्देशित कर सकता है।
  - » रोहिणी 3D मीडियम-रेंज सर्विलांस रडार
  - » 3D लो-लेवल लाइटवेट रडार
  - » लो-लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार (LLTR)
- ये रडार युद्धक्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे दुश्मन के ड्रोन और हवाई खतरों को अत्यंत सटीकता से ट्रैक किया जा सकता है। DRDO में अनुसंधान के माध्यम से रडार क्षमताओं को और बेहतर बनाने के लिए AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), सिग्नल प्रोसेसिंग, पेड़-पत्तियों के आर-पार देखने वाले रडार, और स्टेल्थ तकनीक का पता लगाने वाली तकनीकों पर काम किया जा रहा है।

आकाश मिसाइल प्रणाली:

- भारत की रक्षात्मक सफलता का एक केंद्रीय हिस्सा थी आकाश मिसाइल प्रणाली। यह प्रणाली DRDO के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के तहत विकसित की गई है। आकाश एक मोबाइल, कम से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो महत्वपूर्ण ढांचों और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करती है।
- **इसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:**
  - » एक साथ कई हवाई लक्ष्यों (विमान, मिसाइल, UAV) को भेदने की क्षमता।
  - » 96% स्वदेशी निर्माण, जिसमें 250 से अधिक भारतीय उद्योगों का योगदान है।
  - » मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म त्वरित तैनाती और पुनः तैनाती की अनुमति देता है।
  - » शक्तिशाली रैमजेट इंजन, जो मिसाइल को Mach 2.5 की गति तक ले जाता है।
  - » राजेन्द्र रडार द्वारा 80 किमी की दूरी तक 3D लक्ष्य पहचान

और ट्रैकिंग।

» 55 किलोग्राम का प्री-फ्रैगमेंटेड वारहेड, जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से सक्रिय होता है और बिना सीधे टकराए भी प्रभावी नुकसान पहुँचाता है।

» ECCM (इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटर मेजर्स) – दुश्मन की जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से सुरक्षा देता है।

- भारत वर्तमान में इसके उन्नत संस्करणों का विकास कर रहा है:
  - » **आकाश प्राइम:** उच्च ऊँचाई और कम तापमान वाले क्षेत्रों में अधिक विश्वसनीय और इसमें स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है।
  - » **आकाश-NG (न्यू जेनरेशन):** 70 किमी तक की बढ़ी हुई रेंज, हल्का और चिकना डिज़ाइन, कैनिस्टराइज्ड रूप में संग्रह और संचालन में आसान, और स्टेल्थ एवं अत्यधिक गतिशील लक्ष्यों को भेदने की क्षमता।
- विशेष रूप से, दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने आकाश मिसाइलों के निर्यात को मंज़ूरी दी, जो इसकी क्षमताओं में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है।

मानवरहित वाहनों की बढ़ती भूमिका:

- भारत के रक्षा आधुनिकीकरण में ड्रोन क्षेत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरा है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFI), जो 550 से अधिक ड्रोन कंपनियों और 5,500 से अधिक पायलटों का प्रतिनिधित्व करती है, भारत को 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।
- **उद्योग की वृद्धि और प्रमुख कंपनियाँ:**
  - » **अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ (बेंगलुरु):** इज़राइल की एल्बित सिस्टम्स (Elbit Systems) के साथ मिलकर स्काईस्ट्राइकर (SkyStriker) ड्रोन का निर्माण करती है।
  - » **टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स:** एकीकृत रक्षा और सुरक्षा समाधान प्रदान करती है।
  - » **पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़:** स्वदेशी ड्रोन विकास में विशेषज्ञता रखती है।
  - » **IG Drones:** ड्रोन सर्वेक्षण और मैपिंग जैसी सेवाओं के माध्यम से रक्षा अनुप्रयोगों पर केंद्रित है, और भारतीय सेना तथा विभिन्न सरकारों के साथ सहयोग करती है।
- भारत का ड्रोन बाजार 2030 तक 11 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है, जो वैश्विक बाजार का 12% से अधिक होगा। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना, जिसे 2021 में ₹120 करोड़ के आवंटन के साथ शुरू किया गया था, ने देश में ड्रोन और काउंटर-ड्रोन तकनीक के निर्माण और नवाचार को गति दी है।
- ऑपरेशन सिंदूर ने भारत-पाकिस्तान संघर्षों में एक बड़ा बदलाव दर्शाया, जिसमें ड्रोन और अन्य मानवरहित प्रणालियाँ मुख्य भूमिका में थीं। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य का युद्ध मानव-संचालित और मानवरहित प्रणालियों के समन्वय से लड़ा जाएगा।

नीति, नवाचार और रक्षा निर्माण:

- भारत के रक्षा निर्यात ने वित्त वर्ष 2024-25 में ₹24,000 करोड़ का रिकॉर्ड स्तर छू लिया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक ₹50,000 करोड़ और 2047 तक दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक बनना।
- "मेक इन इंडिया" पहल ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:
  - » वित्त वर्ष 2023-24 में ₹1.27 लाख करोड़ का स्वदेशी रक्षा उत्पादन हुआ।
  - » 2013-14 से निर्यात में 34 गुना की वृद्धि हुई है।
  - » निजी क्षेत्र की भागीदारी और iDEX, SRIJAN जैसे सरकारी नवाचार मंचों ने अनुसंधान और निर्माण को बढ़ावा दिया है।
  - » उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ने रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत किया है।
- प्रमुख स्वदेशी रक्षा प्लेटफ़ॉर्म में शामिल हैं:
  - » धनुष तोप
  - » ATAGS (एडवांस्ड टोअड आर्टिलरी गन सिस्टम)
  - » अर्जुन मेन बैटल टैंक

- » LCA तेजस (लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट)
- » ALH (एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर)और नौसेना के विमानवाहक पोत एवं पनडुब्बियाँ।

ज़मीन से लेकर साइबरस्पेस तक भारत की आतंकवाद के प्रति बदलती प्रतिक्रिया

संदर्भः

आतंकवाद लंबे समय से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती रहा है। पहले यह खतरा सीमापार घुसपैठ, घात लगाकर किए गए हमले और बम विस्फोट जैसे पारंपरिक तरीकों तक सीमित था। लेकिन अब यह और भी अधिक जटिल और बहुआयामी रूप ले चुका है। आज का आतंकवाद युद्धभूमि से आगे बढ़कर साइबर-स्पेस, डिजिटल भ्रामक सूचनाओं और मनोवैज्ञानिक प्रभावों तक फैल चुका है। 2025 के पहलगाम आतंकी हमले, जिसमें भारतीय सेना के चार जवान शहीद हुए, ने इस बदलाव को उजागर किया। उस हमले के बाद की सैन्य कार्रवाई महत्वपूर्ण थी, लेकिन जिस तेजी से साइबर और सूचना के क्षेत्र में जवाब दिया गया, वह एक नया मोड़ था।जैसे-जैसे आतंकवाद अब हाइब्रिड वॉरफेयर यानी "संयुक्त युद्ध तकनीक" अपना रहा है जिसमें शारीरिक हमले, साइबर हमले और प्रोपेगंडा शामिल होते हैं, भारत की रणनीतियाँ भी इन नए खतरों का मुकाबला करने के लिए बदल रही हैं।

हाइब्रिड वॉरफेयर और आतंकवाद को समझना:

- आधुनिक आतंकवाद अब केवल हथियारों से लड़ी जाने वाली हिंसा तक सीमित नहीं है। यह अब हाइब्रिड वॉरफेयर का रूप ले चुका है, जिसमें पारंपरिक युद्ध के साथ-साथ साइबर हमले, फर्जी खबरें, डीपफेक वीडियो और आर्थिक दबाव भी शामिल होते हैं।
- इस प्रकार का युद्ध भ्रम पैदा करता है और सैन्य बलों के साथ-साथ आम नागरिकों के दिमाग को भी निशाना बनाकर अस्थिरता फैलाता है। 2024 का पहलगाम हमला इसका उदाहरण है, जहाँ सीधा हमला करने के साथ-साथ साइबर तकनीकों का भी उपयोग किया गया।
- फर्जी ट्विटर अकाउंट्स ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों की पहचान छिपाकर झूठी जानकारी फैलाई, और डीपफेक ऑडियो क्लिप्स के जरिए झूठे पलटवार की खबरें प्रसारित की गईं। इन तकनीकों का उद्देश्य लोगों को भ्रमित करना और भय का माहौल पैदा करना था।
- भारत हाल के वर्षों में ऐसे कई खतरों का सामना कर चुका है जैसे 2019 का पुलवामा हमला, जम्मू के सांबा और पुंछ में घात हमले और रक्षा प्रतिष्ठानों पर साइबर जासूसी के प्रयास।
- इन खतरों की बढ़ती संख्या और जटिलता के चलते भारत ने अपनी सुरक्षा रणनीतियों को बदला है, जिसमें अब पारंपरिक और डिजिटल दोनों तरह की तैयारियाँ शामिल हैं।

भारत की सैन्य और साइबर प्रतिक्रिया:

- भारत ने परंपरागत रूप से आतंकवाद का मुकाबला सैन्य अभियानों से किया है, जैसे 2016 में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयरस्ट्राइक।
- अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत ने "ऑपरेशन सिंदूर" नामक एक तेज़ और सटीक सैन्य अभियान जम्मू-कश्मीर में चलाया।
- इस अभियान को खास बनाने वाली बात थी—रीयल टाइम खुफिया जानकारी, निगरानी तकनीक और साइबर सतर्कता का एकीकृत उपयोग, जिससे समन्वित और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सकी।
- भारत की साइबर सुरक्षा रणनीति भी अब राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बन गई है। आईबीएम एक्स-फोर्स थ्रेट इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार, भारत साइबर हमलों का चौथा सबसे अधिक निशाना बनने वाला देश है।
- सिर्फ 2023 में ही भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने 14 लाख से अधिक साइबर घटनाओं की रिपोर्ट की, जिनमें फिशिंग और मालवेयर अटैक शामिल थे। इनमें से कई हमलों की उत्पत्ति पाकिस्तान से हुई थी।
- भारत ने 2023 में 22,000 से अधिक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स को निष्क्रिय किया।
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने फर्जी सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए त्वरित कार्रवाई की, फर्जी अकाउंट हटाए और प्रेस ब्रीफिंग्स के जरिए लोगों को भरोसेमंद जानकारी दी।
- यह बदलाव दिखाता है कि अब भारत केवल नुकसान होने के बाद प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि पहले से ही सक्रिय और समग्र रणनीति

अपनाई जा रही है।

कानूनी और संस्थागत ढाँचा:

- भारत में आतंकवाद और साइबर खतरों से निपटने के लिए कई कानूनी और संस्थागत ढाँचे मौजूद हैं।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act):** हैकिंग, पहचान की चोरी, साइबर स्टॉकिंग जैसे अपराधों को संबोधित करता है।
  - **डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023:** नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ताकि उसका दुरुपयोग न हो।
- हालाँकि विशेषज्ञों का मानना है कि डीपफेक और एआई-जनित सामग्री के ज़रिए होने वाले मनोवैज्ञानिक हमलों के संदर्भ में ये कानून आधुनिक हाइब्रिड वॉरफेयर की जटिलताओं से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। भारत की प्रमुख संस्थाओं में शामिल हैं:
  - राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
  - राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO)
  - मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC)
- CERT-In, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।
- हालांकि इन संस्थाओं के बीच विभिन्न मंत्रालयों में विभाजित अधिकार क्षेत्र के कारण रीयल टाइम समन्वय में बाधा आती है। इसके अलावा, एकीकृत साइबर कमांड की अनुपस्थिति के कारण भारत तेज़ी से साइबर हमलों का मुकाबला करने में पिछड़ सकता है।
- इसके अतिरिक्त, आईटी एक्ट जैसे मौजूदा कानूनी उपकरण सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग और नवीनतम तकनीकों को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए थे।
- इस वजह से कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एआई-जनित सामग्री के माध्यम से जनमत को प्रभावित करने वाले मामलों में कार्यवाही करने में कठिनाई होती है।

रणनीतिक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति अब उसकी कूटनीतिक पहलों से भी आकार ले रही है। वैश्विक स्तर पर भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र में "अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT)" को अपनाने की मांग करता रहा है। यह प्रस्तावित संधि आतंकवाद को परिभाषित करने और किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को, चाहे उसका राजनीतिक उद्देश्य कुछ भी हो, अपराध घोषित करने का लक्ष्य रखती है।
- भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और इज़राइल जैसे देशों के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग को भी मज़बूत किया है। इन साझेदारियों का उद्देश्य साइबर खुफिया साझा करना, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना और तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना है।
- क्वाड समूह (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) के अंतर्गत भारत ने साइबर मानदंडों का निर्माण, 5G नेटवर्क की सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भी काम किया है।
- हालाँकि, क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग सीमित बना हुआ है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC), जो आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए एक मंच बन सकता था, भारत-पाकिस्तान तनाव के चलते निष्क्रिय बना हुआ है। इसके विपरीत, आसियान (ASEAN) और यूरोपीय संघ (EU) जैसे क्षेत्रीय संगठन अंतरराष्ट्रीय खतरों से निपटने के लिए अधिक प्रभावी रणनीतियाँ अपना चुके हैं।

सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव:

- आतंकवाद के गंभीर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव होते हैं। लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों के कारण विकास योजनाओं के लिए तय धन रक्षा खर्चों में चला जाता है। संवेदनशील क्षेत्र निवेश के लिए कम आकर्षक बन जाते हैं, जिससे हाशिए पर रह रहे समुदायों, खासकर युवाओं, के कट्टरपंथ की ओर आकर्षित होने का खतरा बढ़ जाता है।
- एक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखने वाले देश के लिए आंतरिक सुरक्षा सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार, आतंकवाद के कारण भारत का GDP नुकसान विश्व के शीर्ष 10 देशों में आता है।
- राजनीतिक रूप से, आतंकवाद लोकचर्चा और चुनाव परिणामों को भी प्रभावित कर सकता है। बार-बार होने वाले हमलों से अक्सर सैन्य जवाब की मांग तेज़ होती है, जिससे राष्ट्रवाद और सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलता है।
- हालाँकि संकट की घड़ी में मज़बूत नेतृत्व जरूरी होता है, लेकिन सुरक्षा उपायों और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन बनाना भी उतना ही आवश्यक है।
- भारत के सामने एक रणनीतिक दुविधा भी है:
  - एक ओर, यदि वह सैन्य रूप से कठोर प्रतिक्रिया देता है, तो अंतरराष्ट्रीय आलोचना और टकराव की आशंका रहती है।
  - दूसरी ओर, यदि प्रतिक्रिया नरम होती है, तो यह आतंकवादियों को और अधिक दुस्साहसी बना सकता है।
- इसलिए इस सूक्ष्म संतुलन को बनाना सामरिक समझ और रणनीतिक दूरदर्शिता की माँग करता है।

भारत की आतंकवाद से लड़ाई अब केवल पारंपरिक रक्षा तरीकों तक सीमित नहीं है; यह अब साइबरस्पेस, डिजिटल युद्ध, और मनोवैज्ञानिक तकनीकों तक फैल चुकी है। जैसे-जैसे हाइब्रिड वॉरफेयर एक सामान्य तरीका बनता जा रहा है, भारत की प्रतिक्रिया को भी पारंपरिक और डिजिटल दोनों खतरों से निपटने के लिए विकसित होना होगा। 2024 का अनुभव दर्शाता है कि भारत अब बहुआयामी रक्षा रणनीति को अपनाने के लिए तैयार है, जिसमें सैन्य शक्ति, तकनीकी नवाचार, कानूनी सुधार, और कूटनीतिक प्रयास शामिल हैं। आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा की जटिलता को समझना और भारत की वैश्विक जिम्मेदारियों को जानना छात्रों और भावी नीति-निर्माताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है।

ज़मीन से लेकर साइबरस्पेस तक भारत की आतंकवाद के प्रति बदलती प्रतिक्रिया

संदर्भ:

आतंकवाद लंबे समय से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती रहा है। पहले यह खतरा सीमापार घुसपैठ, घात लगाकर किए गए हमले और बम विस्फोट जैसे पारंपरिक तरीकों तक सीमित था। लेकिन अब यह और भी अधिक जटिल और बहुआयामी रूप ले चुका है। आज का आतंकवाद युद्धभूमि से आगे बढ़कर साइबर-स्पेस, डिजिटल भ्रामक सूचनाओं और मनोवैज्ञानिक प्रभावों तक फैल चुका है। 2025 के पहलगाम आतंकी हमले, जिसमें भारतीय सेना के चार जवान शहीद हुए, ने इस बदलाव को उजागर किया। उस हमले के बाद की सैन्य कार्रवाई महत्वपूर्ण थी, लेकिन जिस तेजी से साइबर और सूचना के क्षेत्र में जवाब दिया गया, वह एक नया मोड़ था।जैसे-जैसे आतंकवाद अब हाइब्रिड वॉरफेयर यानी "संयुक्त युद्ध तकनीक" अपना रहा है जिसमें शारीरिक हमले, साइबर हमले और प्रोपेगंडा शामिल होते हैं, भारत की रणनीतियाँ भी इन नए खतरों का मुकाबला करने के लिए बदल रही हैं।

हाइब्रिड वॉरफेयर और आतंकवाद को समझना:

- आधुनिक आतंकवाद अब केवल हथियारों से लड़ी जाने वाली हिंसा तक सीमित नहीं है। यह अब हाइब्रिड वॉरफेयर का रूप ले चुका है, जिसमें पारंपरिक युद्ध के साथ-साथ साइबर हमले, फर्जी खबरें, डीपफेक वीडियो और आर्थिक दबाव भी शामिल होते हैं।
- इस प्रकार का युद्ध भ्रम पैदा करता है और सैन्य बलों के साथ-साथ आम नागरिकों के दिमाग को भी निशाना बनाकर अस्थिरता फैलाता है। 2024 का पहलगाम हमला इसका उदाहरण है, जहाँ सीधा हमला करने के साथ-साथ साइबर तकनीकों का भी उपयोग किया गया।
- फर्जी ट्विटर अकाउंट्स ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों की पहचान छिपाकर झूठी जानकारी फैलाई, और डीपफेक ऑडियो क्लिप्स के जरिए झूठे पलटवार की खबरें प्रसारित की गईं। इन तकनीकों का उद्देश्य लोगों को भ्रमित करना और भय का माहौल पैदा करना था।
- भारत हाल के वर्षों में ऐसे कई खतरों का सामना कर चुका है जैसे 2019 का पुलवामा हमला, जम्मू के सांबा और पुंछ में घात हमले और रक्षा प्रतिष्ठानों पर साइबर जासूसी के प्रयास।
- इन खतरों की बढ़ती संख्या और जटिलता के चलते भारत ने अपनी सुरक्षा रणनीतियों को बदला है, जिसमें अब पारंपरिक और डिजिटल दोनों तरह की तैयारियाँ शामिल हैं।

भारत की सैन्य और साइबर प्रतिक्रिया:

- भारत ने परंपरागत रूप से आतंकवाद का मुकाबला सैन्य अभियानों से किया है, जैसे 2016 में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयरस्ट्राइक।
- अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत ने "ऑपरेशन सिंदूर" नामक एक तेज़ और सटीक सैन्य अभियान जम्मू-कश्मीर में चलाया।
- इस अभियान को खास बनाने वाली बात थी—रीयल टाइम खुफिया जानकारी, निगरानी तकनीक और साइबर सतर्कता का एकीकृत उपयोग, जिससे समन्वित और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सकी।
- भारत की साइबर सुरक्षा रणनीति भी अब राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बन गई है। आईबीएम एक्स-फोर्स थ्रेट इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार, भारत साइबर हमलों का चौथा सबसे अधिक निशाना बनने वाला देश है।
- सिर्फ 2023 में ही भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने 14 लाख से अधिक साइबर घटनाओं की रिपोर्ट की, जिनमें फिशिंग और मालवेयर अटैक शामिल थे। इनमें से कई हमलों की उत्पत्ति पाकिस्तान से हुई थी।
- भारत ने 2023 में 22,000 से अधिक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स को निष्क्रिय किया।
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने फर्जी सूचनाओं का मुकाबला

करने के लिए त्वरित कार्रवाई की, फर्जी अकाउंट हटाए और प्रेस ब्रीफिंग्स के जरिए लोगों को भरोसेमंद जानकारी दी।

- यह बदलाव दिखाता है कि अब भारत केवल नुकसान होने के बाद प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि पहले से ही सक्रिय और समग्र रणनीति अपनाई जा रही है।

कानूनी और संस्थागत ढाँचा:

- भारत में आतंकवाद और साइबर खतरों से निपटने के लिए कई कानूनी और संस्थागत ढाँचे मौजूद हैं।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act):** हैकिंग, पहचान की चोरी, साइबर स्टॉकिंग जैसे अपराधों को संबोधित करता है।
  - **डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023:** नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ताकि उसका दुरुपयोग न हो।
- हालाँकि विशेषज्ञों का मानना है कि डीपफेक और एआई-जनित सामग्री के ज़रिए होने वाले मनोवैज्ञानिक हमलों के संदर्भ में ये कानून आधुनिक हाइब्रिड वॉरफेयर की जटिलताओं से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। भारत की प्रमुख संस्थाओं में शामिल हैं:
  - राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
  - राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO)
  - मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC)
- CERT-In, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।
- हालांकि इन संस्थाओं के बीच विभिन्न मंत्रालयों में विभाजित अधिकार क्षेत्र के कारण रीयल टाइम समन्वय में बाधा आती है। इसके अलावा, एकीकृत साइबर कमांड की अनुपस्थिति के कारण भारत तेज़ी से साइबर हमलों का मुकाबला करने में पिछड़ सकता है।
- इसके अतिरिक्त, आईटी एक्ट जैसे मौजूदा कानूनी उपकरण सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग और नवीनतम तकनीकों को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए थे।
- इस वजह से कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एआई-जनित सामग्री के माध्यम से जनमत को प्रभावित करने वाले मामलों में कार्यवाही करने में कठिनाई होती है।

रणनीतिक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति अब उसकी कूटनीतिक पहलों से भी आकार ले रही है। वैश्विक स्तर पर भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र में "अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT)" को अपनाने की मांग करता रहा है। यह प्रस्तावित संधि आतंकवाद को परिभाषित करने और किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को, चाहे उसका राजनीतिक उद्देश्य कुछ भी हो, अपराध घोषित करने का लक्ष्य रखती है।
- भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और इज़राइल जैसे देशों के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग को भी मज़बूत किया है। इन साझेदारियों का उद्देश्य साइबर खुफिया साझा करना, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना और तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना है।
- क्वाड समूह (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) के अंतर्गत भारत ने साइबर मानदंडों का निर्माण, 5G नेटवर्क की सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भी काम किया है।
- हालाँकि, क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग सीमित बना हुआ है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC), जो आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए एक मंच बन सकता था, भारत-पाकिस्तान तनाव के चलते निष्क्रिय बना हुआ है। इसके विपरीत, आसियान (ASEAN) और यूरोपीय संघ (EU) जैसे क्षेत्रीय संगठन अंतरराष्ट्रीय खतरों से निपटने के लिए अधिक प्रभावी रणनीतियाँ अपना चुके हैं।

सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव:

- आतंकवाद के गंभीर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव होते हैं। लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों के कारण विकास योजनाओं के लिए तय धन रक्षा खर्चों में चला जाता है। संवेदनशील क्षेत्र निवेश के लिए कम आकर्षक बन जाते हैं, जिससे हाशिए पर रह रहे समुदायों, खासकर युवाओं, के कट्टरपंथ की ओर आकर्षित होने का खतरा बढ़ जाता है।
- एक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखने वाले देश के लिए आंतरिक सुरक्षा सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार, आतंकवाद के कारण भारत का GDP नुकसान विश्व के शीर्ष 10 देशों में आता है।
- राजनीतिक रूप से, आतंकवाद लोकचर्चा और चुनाव परिणामों को भी प्रभावित कर सकता है। बार-बार होने वाले हमलों से अक्सर सैन्य जवाब की मांग तेज़ होती है, जिससे राष्ट्रवाद और सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलता है।
- हालाँकि संकट की घड़ी में मज़बूत नेतृत्व जरूरी होता है, लेकिन सुरक्षा उपायों और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन बनाना भी उतना ही आवश्यक है।
- भारत के सामने एक रणनीतिक दुविधा भी है:
  - एक ओर, यदि वह सैन्य रूप से कठोर प्रतिक्रिया देता है, तो अंतरराष्ट्रीय आलोचना और टकराव की आशंका रहती है।
  - दूसरी ओर, यदि प्रतिक्रिया नरम होती है, तो यह आतंकवादियों

को और अधिक दुस्साहसी बना सकता है।

- इसलिए इस सूक्ष्म संतुलन को बनाना सामरिक समझ और रणनीतिक दूरदर्शिता की माँग करता है।

भारत की आतंकवाद से लड़ाई अब केवल पारंपरिक रक्षा तरीकों तक सीमित नहीं है; यह अब साइबरस्पेस, डिजिटल युद्ध, और मनोवैज्ञानिक तकनीकों तक फैल चुकी है। जैसे-जैसे हाइब्रिड वॉरफेयर एक सामान्य तरीका बनता जा रहा है, भारत की प्रतिक्रिया को भी पारंपरिक और डिजिटल दोनों खतरों से निपटने के लिए विकसित होना होगा। 2024 का अनुभव दर्शाता है कि भारत अब बहुआयामी रक्षा रणनीति को अपनाने के लिए तैयार है, जिसमें सैन्य शक्ति, तकनीकी नवाचार, कानूनी सुधार, और कूटनीतिक प्रयास शामिल हैं। आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा की जटिलता को समझना और भारत की वैश्विक जिम्मेदारियों को जानना छात्रों और भावी नीति-निर्माताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है।

सिन्धु जल संधि का निलंबन

संदर्भ:

23 अप्रैल 2025 को भारत ने पहलगाम (जम्मू और कश्मीर) में हुए एक आतंकी हमले के बाद सिन्धु जल संधि (IWT) को निलंबित कर दिया। यह हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किया गया था। यह पहला मौका है जब इस संधि को निलंबित किया गया है। भारत का यह कदम क्षेत्रीय राजनीति और जल संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

- इस फैसले के साथ उठाए गए प्रमुख कूटनीतिक कदम हैं:
  - » अटारी सीमा चौकी को बंद करना
  - » पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए वीज़ा रद्द करना
  - » भारत में कार्यरत पाकिस्तानी अधिकारियों को निष्कासित करना

सिन्धु जल संधि क्या है?

- सिन्धु जल संधि 19 सितंबर 1960 को कराची में नौ वर्षों की बातचीत के बाद हस्ताक्षरित हुई थी। इसमें कुल 12 अनुच्छेद और 8 परिशिष्ट (A से H) हैं। यह भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल का बंटवारा तय करती है:
  - » **पूर्वी नदियाँ:** सतलुज, ब्यास और रावी: इनका जल भारत को पूरी तरह इस्तेमाल करने की अनुमति है।
  - » **पश्चिमी नदियाँ:** सिंधु, झेलम और चिनाब: इनका पानी मुख्यतः पाकिस्तान को मिलता है, लेकिन भारत को सीमित रूप से जलविद्युत, नौवहन और सिंचाई के लिए उपयोग की इजाज़त है – वो भी सख्त शर्तों और तकनीकी नियमों के तहत।

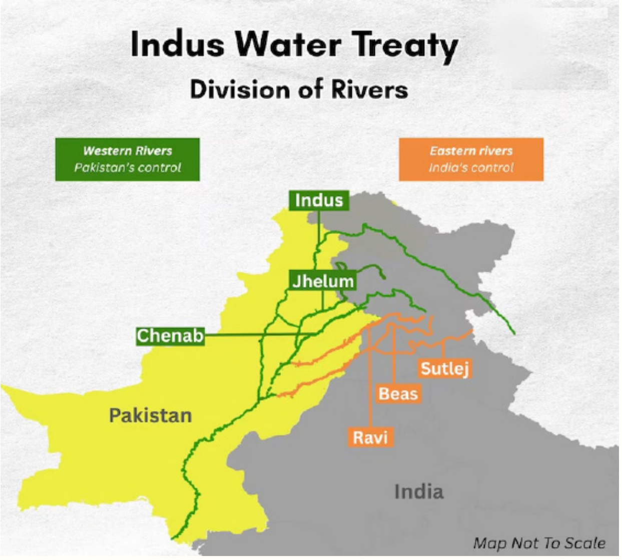

संधि निलंबन के रणनीतिक असर:

- जल प्रवाह से जुड़ा डेटा अब पाकिस्तान के साथ साझा नहीं किया जाएगा।
- पश्चिमी नदियों पर भारत अब अपने प्रोजेक्ट्स के डिजाइन और संचालन से जुड़े उन प्रतिबंधों को हटा सकता है जो उसने खुद लगाए थे।
- भारत अब झेलम और चिनाब जैसी नदियों पर जलाशय बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, जो संधि के तहत सीमित रूप से पहले से ही संभव है।
- किशनगंगा जैसे जलविद्युत प्रोजेक्ट्स में भारत जलाशय की सफाई (reservoir flushing) कर सकता है, जिससे उनकी उम्र और कार्यक्षमता बेहतर होगी।

कानूनी पहलू:

- IWT में संधि से बाहर निकलने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए भारत का एकतरफा तरीके से इसे छोड़ना कानूनी रूप से संभव नहीं है। हालांकि, अनुच्छेद IX और परिशिष्ट F व G के तहत विवाद समाधान की प्रक्रिया मौजूद है:
  - » **स्थायी सिंधु आयोग (Permanent Indus Commission – PIC):** दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत का मंच।
  - » **न्यूट्रल एक्सपर्ट:** तकनीकी विवादों में विश्व बैंक द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ।
  - » **मध्यस्थता न्यायालय (Court of Arbitration):** अधिक गंभीर और राजनीतिक विवादों के लिए।

- हालांकि, इन प्रक्रियाओं की सफलता दोनों देशों की भागीदारी पर निर्भर करती है। 2016 में कानूनी विशेषज्ञ अहमर बिलाल सूफी ने कहा था कि अगर भारत इस संधि को पूरी तरह ठुकरा देता है, तो विवाद समाधान की ये प्रक्रिया निष्क्रिय हो जाएंगी। साथ ही, भारत ने ICJ (अंतरराष्ट्रीय न्यायालय) के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताई है, इसलिए पाकिस्तान वहां मामला नहीं ले जा सकता।

सिन्धु जल संधि से जुड़े हाल के घटनाक्रम:

- जम्मू और कश्मीर में भारत की दो जलविद्युत परियोजनाएं – किशनगंगा (झेलम की सहायक नदी पर) और रैटल (चिनाब पर) – को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि इन प्रोजेक्ट्स के डिजाइन IWT के प्रावधानों के खिलाफ हैं, जबकि भारत का कहना है कि ये परियोजनाएं 'रन-ऑफ-द-रिवर' हैं और संधि के दायरे में आती हैं।
- जनवरी 2023 में भारत ने पाकिस्तान को पहला औपचारिक नोटिस भेजा, जिसमें इस्लामाबाद के अड़ियल रवैये को आधार बनाकर अनुच्छेद XII(3) के तहत संधि की समीक्षा का प्रस्ताव रखा गया। सितंबर 2024 में दूसरा नोटिस भेजा गया, जिससे यह संकेत मिला कि भारत इसे पुनः बातचीत के लिए तैयार है।
- जनवरी 2025 में विश्व बैंक द्वारा नियुक्त न्यूट्रल एक्सपर्ट मिशेल लिनो ने खुद को इन डिजाइन विवादों को सुलझाने में सक्षम बताया। भारत ने कहा कि ये विवाद परिशिष्ट F के पहले भाग के तहत आते हैं, जबकि पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई।

अटारी एकीकृत चेक पोस्ट

संदर्भ:

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद अटारी एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) को बंद करने का निर्णय लिया। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही नाजुक व्यापार संबंधों पर और असर पड़ा। इस बंदी से ₹3,886.53 करोड़ के द्विपक्षीय व्यापार पर रोक लगने की संभावना है, जिससे विशेष रूप से पंजाब में क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों और आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

अटारी एकीकृत चेक पोस्ट के माध्यम से व्यापार का विकास:

- अटारी-वाघा ज़मीनी मार्ग को 2005 में व्यापार के लिए खोला गया था और 2007 में ट्रक आवाजाही शुरू हुई थी। अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) का औपचारिक उद्घाटन 13 अप्रैल 2012 को यूपीए सरकार के दौरान हुआ था।
- 120 एकड़ में फैला यह ICP, नेशनल हाईवे 1 से सीधे जुड़ता है, जो दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक गलियारा बनाता है।
- इस गलियारे के माध्यम से व्यापार में दोनों देशों की पूरक आवश्यकताएं परिलक्षित होती थीं:
  - » **भारत का निर्यात:** सोयाबीन, पोल्ट्री फ़ीड, सब्जियां, लाल मिर्च, प्लास्टिक ग्रेन्युल्स, प्लास्टिक यार्न, और स्ट्रॉ रीपर्स।
  - » **भारत का आयात:** सूखे मेवे, खजूर, जिप्सम, सीमेंट, कांच, सेंधा नमक और जड़ी-बूटियाँ पाकिस्तान से।

व्यापार के रुझान और राजनीतिक तनाव:

अटारी चेक पोस्ट से व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, लेकिन द्विपक्षीय तनावों के चलते व्यापारिक मात्रा प्रभावित होने लगी:

वर्ष	व्यापार मूल्य (₹ करोड़)	खेपें
2018–19	4,370.78	49,102
2022–23	2,257.55	3,827
2023–24	3,886.53	डेटा निर्दिष्ट नहीं

- भारत द्वारा पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में 2019 में पाकिस्तानी वस्तुओं पर 200% शुल्क लगाने के बाद व्यापार मात्रा में उल्लेखनीय गिरावट आई।
- शुल्क वृद्धि ने कई वर्षों तक औपचारिक व्यापार को लगभग स्थिर कर दिया था। 2023–24 में आंशिक पुनरुद्धार ने सतर्क आशावाद का संकेत दिया था, लेकिन हालिया बंदी ने फिर से गतिविधियों को रोक दिया।
- डॉलर के संदर्भ में, पिछले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $2 अरब सालाना तक सीमित रहा है, जो विश्व बैंक द्वारा अनुमानित $37 अरब व्यापार क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा है।

पंजाब की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- पंजाब, विशेष रूप से अमृतसर और अटारी के आसपास के क्षेत्रों ने व्यापार बंदी का सबसे अधिक नुकसान उठाया है। अटारी ICP के चारों ओर एक मजबूत व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ था, जिसने हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया:
  - » **उत्पन्न रोजगार:** परिवहनकर्मी, कुली, कस्टम एजेंट, दुकानदार और छोटे पैमाने के औद्योगिक श्रमिक।
  - » **पंजाब का प्रमुख निर्यात:** छोटे पैमाने पर इकाइयों द्वारा निर्मित स्ट्रॉ रीपर्स।
- व्यापार प्रतिबंधों के कारण निर्यात में गिरावट ने स्थानीय निर्माताओं को भारी वित्तीय नुकसान पहुँचाया। सामान्य व्यापार स्थितियों में, 2020–21 रिकॉर्ड वर्ष बन सकता था।

पाकिस्तान का आर्थिक संकट:

- महामारी के बाद महंगाई में वृद्धि, खाद्य और ईंधन की कीमतों में उछाल।
- मई 2023 में पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) में आर्थिक कठिनाइयों के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन, जिसमें 90 से अधिक लोग घायल हुए।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने हाल ही में पाकिस्तान की विकास दर के अनुमान को 2.6% तक घटा दिया है, वैश्विक व्यापार तनाव और अमेरिकी टैरिफ में वृद्धि का हवाला देते हुए।

करतारपुर कॉरिडोर समझौता का नवीनीकरण

चर्चा में क्यों?

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया था। जवाब में भारत ने करतारपुर कॉरिडोर के अपने हिस्से को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया था, जो दोनों देशों के बीच एकमात्र सक्रिय भूमि मार्ग है।

नवीनीकरण का मुख्य विवरण:

- **अवधि:** नवीनीकृत समझौते के तहत गलियारे का संचालन अगले पांच वर्षों के लिए, अर्थात् 2029 तक बढ़ा दिया गया है।
- **तीर्थयात्री क्षमता:** इस गलियारे में प्रतिदिन 5,000 तीर्थयात्रियों के प्रवेश की व्यवस्था होगी, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ सकेंगे।
- **सेवा शुल्क:** परिचालन लागत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान प्रति तीर्थयात्री 20 डॉलर का नाममात्र सेवा शुल्क लेना जारी रखेगा।

पात्रता एवं आवश्यकताएँ:

- **कॉरिडोर का उपयोग कर सकते हैं:**
  - » भारतीय नागरिक
  - » भारतीय मूल के व्यक्ति
- **आवश्यक दस्तावेज:**
  - » सभी तीर्थयात्रियों के लिए एक वैध पासपोर्ट और एक इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ईटीए)।
  - » ओसीआई कार्ड धारकों के लिए उन्हें अपना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
- **यात्रा दिशानिर्देश:**
  - » **यात्रा कार्यक्रम:** तीर्थयात्री सुबह रवाना होंगे और उन्हें उसी दिन वापस लौटना होगा।
  - » **यात्रा प्रतिबंध:** यात्रा केवल गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब तक ही सीमित है और इस स्थल से आगे यात्रा की अनुमति नहीं है।

करतारपुर कॉरिडोर समझौते के बारे में :

- **हस्ताक्षर तिथि:** प्रारंभिक समझौते पर 24 अक्टूबर, 2019 को हस्ताक्षर किए गए।
- **उद्देश्य:** इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए गुरुद्वारा साहिब तक आसान पहुँच को सुगम बनाना है। दरबार साहिब करतारपुर, पाकिस्तान के नारोवाल में स्थित है।

- **कॉरिडोर के विषय में:** करतारपुर कॉरिडोर 4.7 किलोमीटर (2.9 मील) लंबा एक वीजा-मुक्त क्रॉसिंग है, जोकि पाकिस्तान के दरबार साहिब गुरुद्वारा को भारत के डेरा बाबा नानक से जोड़ता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- करतारपुर कॉरिडोर का विचार पहली बार वर्ष 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जब दिल्ली-लाहौर बस कूटनीति के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ चर्चा की।
- इस प्रस्ताव को वास्तविकता में बदलने के प्रयासों के तहत 2018 में, भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर के निर्माण के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंततः यह गलियारा आधिकारिक रूप से 12 नवंबर, 2019 को गुरु नानक की 550वीं जयंती के अवसर पर खोला गया, जो सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है।

महत्व:

- करतारपुर कॉरिडोर सिख श्रद्धालुओं के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें गुरु नानक की जन्मस्थली तक आसानी से पहुँचने में सहायता करता है।
- राजनीतिक दृष्टिकोण से, इस कॉरिडोर को भारत और पाकिस्तान के बीच एक पुल के रूप में देखा जाता है, जोकि शांति की दिशा में एक कदम है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने में सहायक है।

मालदीव

मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की भारत यात्रा

संदर्भ:

राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज़्ज़ू की 6 से 10 अक्टूबर, 2024 तक की राजकीय यात्रा मालदीव-भारत संबंधों में बदलाव का संकेत देती है। नवंबर 2023 में पदभार ग्रहण करने के बाद मुइज़्ज़ू ने 'इंडिया आउट' अभियान चलाया और मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की। इससे भारत मालदीव संबंधो में तनाव देखा गया था।

- ऐतिहासिक दृष्टि से, भारत मालदीव का एक प्रमुख सहयोगी और सहायता प्रदाता रहा है। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है, यद्यपि इससे पूर्व भारतीय नेतृत्व और नीतियों के प्रति मालदीव के अधिकारियों की अपमानजनक टिप्पणियों ने तनाव को बढ़ा दिया था। अपने चुनाव के बाद, मुइज़्ज़ू के कूटनीतिक प्रयासों में चीन और तुर्की की यात्राएँ शामिल थीं, जिन्हें भारत के प्रति अपमान के रूप में देखा गया था।
- मुइज़्ज़ू के हालिया दृष्टिकोण से भारत के साथ संबंधो को बेहतर करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में, मालदीव एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण ऋण अदायगी का जोखिम बढ़ गया है। ऐसे में भारत के साथ सहयोग स्थापित करना मालदीव की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

बैठक की मुख्य बातें:

- **द्विपक्षीय संबंधों का सुदृढ़ीकरण:** बैठक में भारत ने मालदीव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया, जोकि भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति और 'सागर' (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
  - » मालदीव ने आपातकालीन वित्तीय सहायता, जिसमें 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के टी-बिल का रोलओवर शामिल है, के लिए भारत का आभार प्रकट किया। इस सहायता ने मालदीव को तत्काल आर्थिक संकट से निपटने में मदद की।
  - » मालदीव ने संकट के समय भारत की भूमिका को सराहा, जिसमें 2014 के जल संकट और कोविड-19 महामारी के दौरान दी गई सहायता का उल्लेख किया गया।
- **वित्तीय सहयोग एवं समर्थन:**
  - » दोनों देशों के बीच 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 30 बिलियन भारतीय रुपये का द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौता किया गया। इस समझौते से मालदीव की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों में राहत मिलने की उम्मीद है।
  - » दोनों पक्षों ने भविष्य में वित्तीय सहयोग को गहन बनाने पर सहमति व्यक्त की।
- **व्यापक आर्थिक एवं समुद्री सुरक्षा साझेदारी:** हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाने के उद्देश्य से एक साझेदारी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:
  - » **राजनीतिक संवाद को बढ़ावा:** संसदीय सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) सहित विभिन्न स्तरों पर राजनयिक आदान-प्रदान बढ़ाया गया।
  - » **विकास सहयोग:** विकास पहलों में बंदरगाहों, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास,

ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना को पूरा करना, थिलाफुशी द्वीप पर एक वाणिज्यिक बंदरगाह विकसित करना और एटोल में कृषि और पर्यटन निवेश पर सहयोग करना शामिल था।

- **व्यापार और आर्थिक सहयोग:** द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चर्चा आरंभ करने तथा आर्थिक संबंधों को गहरा करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा लेनदेन को सक्षम करने पर सहमति बनी।
- **डिजिटल और वित्तीय सहयोग:** डिजिटल सेवाओं में विशेषज्ञता साझा करना और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) सहित मालदीव में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना करना।
- **ऊर्जा सहयोग:** सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की खोज करना तथा एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल में भागीदारी के लिए व्यवहार्यता का अध्ययन करना।
- **स्वास्थ्य सहयोग:** किफायती स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर पहुंच, भारतीय फार्मास्यूटिकल्स को मान्यता और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करना।
- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग:** हिंद महासागर में साझा चुनौतियों की स्वीकृति के साथ, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने हेतु समझौता किया गया। इसमें चल रही 'एकाथा' बंदरगाह परियोजना भी शामिल है।
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:** सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा महिला-नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न क्षमता निर्माण पहलों पर जोर दिया गया।
- **जन-जन संपर्क:** सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने, बेंगलुरु और अड्डू शहर में वाणिज्य दूतावास स्थापित करने और हवाई एवं समुद्री संपर्क में सुधार हेतु समझौतों पर सहमति बनी।
- **क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय सहयोग:** कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी) के संस्थापक सदस्यों के रूप में, समुद्री और सुरक्षा हितों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा बहुपक्षीय मंचों पर संयुक्त प्रयास जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

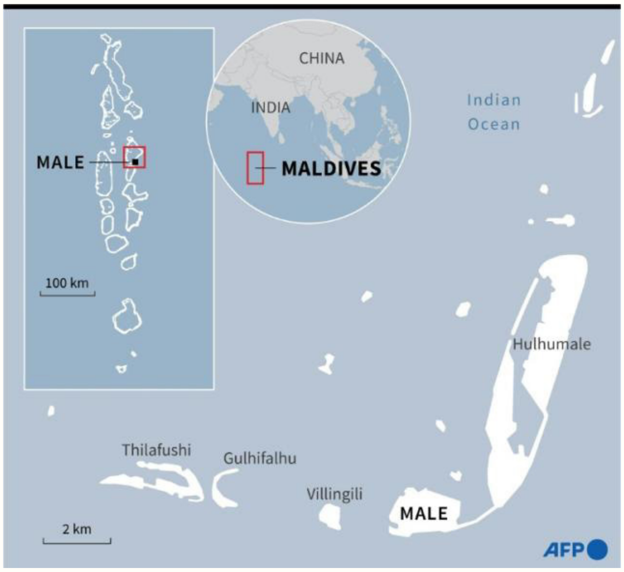

भारत के लिए मालदीव का महत्व:

- मालदीव अपनी भौगोलिक निकटता के कारण भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व रखता है, जो इसे मिनिकॉय से केवल 70 समुद्री मील और भारत के पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील की दूरी पर स्थित करता है। यह रणनीतिक स्थान मालदीव को हिंद महासागर में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थान देता है, विशेष रूप से 8° N और 1½° N चैनलों के साथ। ऐसी स्थिति भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाती है और इस क्षेत्र में अन्य देशों की नौसैनिक उपस्थिति से संभावित चुनौतियां पैदा करती है।
- मालदीव में भारत के भू-राजनीतिक हितों में समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए आवश्यक संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना, समुद्री डकैती और समुद्र आधारित आतंकवाद से निपटना और हिंद महासागर को संघर्ष-मुक्त क्षेत्र बनाए रखने का प्रयास करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, मालदीव में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था की खोज और व्यापार संबंधों को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
- मालदीव चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' पहल के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य पूरे दक्षिण एशिया में चीनी सैन्य और वाणिज्यिक सुविधाओं का एक नेटवर्क स्थापित करना है। यह भारत के लिए चिंता का विषय है, जो इस क्षेत्र में एक मजबूत उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देता है।
- आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे भू-राजनीतिक परिदृश्य को जटिल बनाते हैं, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक-आर्थिक अनिश्चितता के बीच आतंकवादी समूहों में शामिल होने वाले मालदीव के लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन कारकों से यह आशंका बढ़ जाती है कि मालदीव भारत को निशाना बनाकर आतंकवादी गतिविधियों के लिए लॉन्च पैड बन सकता है।

भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध:

- भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं। भारत 1965 में अपनी स्वतंत्रता के बाद मालदीव को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, जिसने एक मजबूत राजनयिक संबंध की शुरुआत की। संकटों के दौरान पहले प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारत की भूमिका - जैसे कि 1988 के तख्तापलट के प्रयास (ऑपरेशन कैक्टस), 2004 की सुनामी और 2014 के जल संकट - मालदीव के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य समर्थन और 2020 में खसरे के टीके की डिलीवरी इस प्रतिबद्धता को और उजागर करती है।
- सुरक्षा और रक्षा सहयोग के संदर्भ में, रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए 2016 में एक व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स (MNDF) के लिए लगभग 70% प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो मालदीव की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में एक प्रमुख भागीदार के रूप में अपनी भूमिका पर जोर देता है। वार्षिक रक्षा सहयोग वार्ता की स्थापना इस साझेदारी को और मजबूत बनाती है।
- भारत की विकास सहयोग पहलों में इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल, मालदीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और नेशनल कॉलेज फॉर पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। 34 द्वीपों में पानी और स्वच्छता में सुधार, अड्डू एटोल में सड़कों का विकास और कैंसर अस्पताल की स्थापना के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा परियोजनाएं मालदीव के विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
- आर्थिक रूप से, भारत 2022 में मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा और 2023 में सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया है, जिसके द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 की अवधि में लगभग 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इस मजबूत व्यापार संबंध को वित्तीय सहायता से बल मिला है, जिसमें 100 मिलियन डॉलर का सहायता पैकेज और दिसंबर 2022 में हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौता शामिल है।
- पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और 2023 में, भारतीयों ने 200,000 से अधिक यात्रियों के साथ द्वीपों का दौरा करने वाले पर्यटकों का सबसे बड़ा समूह बनाया। यह प्रवृत्ति न केवल मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है, बल्कि मालदीव की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में पर्यटन के महत्व पर भी जोर देती है।
- इसके अलावा, मालदीव में भारतीय समुदाय दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समूह है, जिसके लगभग 22,000 सदस्य हैं। भारतीय नागरिक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मालदीव में डॉक्टरों और शिक्षकों में लगभग 25% भारतीय नागरिक शामिल हैं।

निष्कर्ष:

मोदी और राष्ट्रपति मुइज़ू के बीच बैठक सहयोग के एक नए युग की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में साझा चुनौतियों का समाधान करने के महत्व को रेखांकित करती है। मालदीव, अपनी रणनीतिक स्थिति और भारत के साथ विकसित होती साझेदारी के साथ, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में एक प्रमुख देश बना हुआ है।

भारत-मालदीव संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्य समझौता ज्ञापन:

- **उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर समझौता ज्ञापन:** भारत और मालदीव ने भारत की अनुदान सहायता से वित्त पोषित उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDP) के चरण-III के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति मुइज़ू की यात्रा के दौरान किए गए समझौतों का अनुसरण करता है।
- **सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा:** दोनों देशो ने सीमा पार लेनदेन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नए रूपरेखा समझौते का स्वागत किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच निरंतर सहयोग पर प्रकाश डाला गया।

इस समझौता ज्ञापन के निहितार्थ:

- भारत मालदीव में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDP) को लागू करेगा, जिसका वित्तपोषण भारत की अनुदान सहायता से होगा, जिससे भारत की पड़ोस प्रथम नीति और विजन SAGAR के तहत संबंधों को मजबूती मिलेगी।
- भारत-मालदीव सहयोग में वृद्धि से क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा में योगदान मिलता है।
- नेताओं के बीच उच्च स्तरीय यात्राएं बेहतर संबंधों का संकेत देती हैं, जो ऋण राहत, आर्थिक सहयोग और शांति पर केंद्रित हैं।
- मजबूत संबंध हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने में भारत की भूमिका को मजबूत करते हैं।

भारत के लिए मालदीव का महत्व:

- **भू-राजनीतिक:** मालदीव भारत की पड़ोस प्रथम नीति (NFP) और SAGAR नीति के लिए केंद्रीय स्थान रखता है, जोकि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- **रणनीतिक महत्व:** हिंद महासागर में प्रमुख चोकपॉइंट्स पर स्थित होने के कारण यह नौवहन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्थिरता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- **भू-अर्थशास्त्र:** मालदीव प्रमुख समुद्री मार्गों पर स्थित है, जोकि भारत के व्यापार और ऊर्जा आयात के लिए महत्वपूर्ण है। भारत 2023 में मालदीव का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया।
- **सुरक्षा:** मालदीव आतंकवाद, समुद्री डकैती और हिंद महासागर में चीन के रणनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **प्रवासी और पर्यटन:** बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय कार्यबल और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल।

द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियाँ :

- **भारत विरोधी भावनाएँ:** 'इंडिया आउट कैंपेन' द्वारा भारतीय सैन्य उपस्थिति को कम करने और बुनियादी ढाँचा जैसी परियोजनाओं को रोकने की बढ़ती माँगें।
- **चीनी प्रभाव:** चीनी निवेश में वृद्धि और सिनामाले ब्रिज जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ भारत के लिए चिंताएँ बढ़ाती हैं।
- **कट्टरपंथ:** इस्लामी चरमपंथी समूहों का विकास, जो संभावित रूप से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है।
- **अविश्वास में वृद्धि:** उथुरु थिला फाल्हू हार्बर जैसी परियोजनाओं पर अटकलें अविश्वास को बढ़ावा दे रही हैं।

भूटान

भारत-भूटान संबंध

संदर्भ:

हाल ही में भारत और भूटान ने सीमा-संबंधी क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने और तकनीकी व क्षमता-निर्माण सहयोग के नए अवसरों की पहचान करने हेतु एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय बैठक में भारत सरकार और भूटान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा कार्यालय के अधिकारियों ने सीमा-संबंधी क्षेत्र कार्य से संबंधित मामलों की समीक्षा की।

बैठक के मुख्य विषय:

- **सीमा-संबंधी क्षेत्रीय मुद्दे:** दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी क्षेत्रीय सर्वेक्षण टीमों और सीमा-संबंधी कार्यों में शामिल अन्य हितधारकों द्वारा किए गए प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।
- **तकनीकी और क्षमता-निर्माण सहयोग:** दोनों देशों ने सर्वेक्षण और सीमा-प्रबंधन से जुड़े तकनीकी सहयोग तथा क्षमता-निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा की, जो उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है।
- **अगले तीन क्षेत्रीय सत्रों के लिए कार्य योजना:** बैठक में अगले तीन क्षेत्रीय सत्रों के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया, जिससे भविष्य के सहयोग के लिए एक स्पष्ट रोडमैप सुनिश्चित हुआ।

भारत-भूटान द्विपक्षीय संबंधों के बारे में:

- भारत और भूटान के बीच मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं, जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग पर आधारित हैं। यह साझेदारी कई दशकों में विकसित हुई है, जिसमें विविध समझौतों और सहयोग पहलों ने दोनों देशों को लाभान्वित किया है।
- **राजनीतिक संबंध:**
  - » भारत-भूटान संबंधों की आधारशिला 1949 की मैत्री संधि

है, जिसे 2007 में पुनः संशोधित किया गया। यह संधि दोनों देशों के मजबूत राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को रेखांकित करती है, जो आपसी सम्मान और समझ पर आधारित है।

» 1968 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद, दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में सहयोग को गहरा किया, विशेष रूप से रक्षा और सुरक्षा में।

- **जलविद्युत सहयोग:**
  - » सहयोग के सबसे प्रमुख क्षेत्रों में से क्षेत्र जलविद्युत प्रमुख है। 2006 में, भारत और भूटान ने जलविद्युत सहयोग पर एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे 2009 में एक प्रोटोकॉल द्वारा विस्तारित किया गया। भूटान के लिए, भारत वित्तपोषण और ऊर्जा बाजारों तक पहुँच प्रदान करता है, जो देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
  - » उदाहरण के लिए, भूटान के बसोचू और निकाचू जलविद्युत संयंत्र भारत के बिजली एक्सचेंजों से जुड़े हैं, जिससे भूटान को विद्युत का व्यापार करने की अनुमति मिलती है। भारत के लिए, भूटान की स्वच्छ ऊर्जा बिजली की माँग को स्थायी रूप से पूरा करने में मदद करती है, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में।

भारत से भूटान को सहायता:

भारत विभिन्न रूपों में भूटान को पर्याप्त सहायता प्रदान करता है:

- **मुक्त व्यापार व्यवस्था:** 1972 के भारत-भूटान व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौते को 2016 में संशोधित किया गया, जिससे भूटानी उत्पादों को तीसरे देशों तक शुल्क-मुक्त निर्यात की सुविधा मिलती है।
- **विकास सहायता:** भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना (2024-2029) में एक प्रमुख भागीदार है और भूटान के विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करते हुए आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम का समर्थन करता है।
- **सुरक्षा सहायता:** भारत भूटान के लिए शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह 2017 में डोकलाम गतिरोध के दौरान स्पष्ट था, जब भारत ने भूटानी क्षेत्र को चीनी अतिक्रमण से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था।
- **अवसंरचना:** 'परियोजना दंतक' के तहत, भारत के सीमा सड़क संगठन (BRO) ने भूटान में प्रमुख सड़कों और पुलों का निर्माण किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क बढ़ा।

अन्य सहायता:

- भारत भूटानी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है और भूटान के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में लगभग 50% योगदान देता है। भारत 'डिजिटल ड्रुक्युल' परियोजना के तहत भूटान को बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी विकसित करने में सहायता कर रहा है।

भारत-भूटान संबंधों में बढ़ती चिंताएँ:

हालाँकि संबंध सकारात्मक रहे हैं, लेकिन कई उभरती चिंताओं को संबोधित करने की आवश्यकता है:

- **चीन के साथ बढ़ती निकटता:** भूटान चीन के साथ अपनी कूटनीतिक वार्ताओं को बढ़ा रहा है। 2023 में भूटान के विदेश मंत्री की चीन यात्रा से यह संकेत मिलता है कि चीन अब भूटान का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन चुका है, जो इसके कुल व्यापार का 25% है।
- **चीन की क्षेत्रीय मुखरता:** चीन की 'पाँच-उँगली नीति' में भूटान को क्षेत्रीय दावों का हिस्सा माना जाता है, विशेष रूप से डोकलाम पठार को लेकर भारत की चिंता बनी हुई है।
- **उग्रवादी समूहों की गतिविधियाँ:** भूटान के सीमावर्ती क्षेत्र भारत के पूर्वोत्तर उग्रवादी समूहों, जैसे कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) के लिए आश्रय स्थल बने रहे हैं, जिससे सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होते हैं।
- **रुकी हुई परियोजनाएँ:** भूटान में पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते में देरी हुई है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क में बाधा आ रही है।
- भारत और भूटान के संबंध मैत्री, आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित हैं। हालाँकि, बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में नई चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है ताकि यह साझेदारी भविष्य में भी मजबूत बनी रहे।

अफगानिस्तान

भारत-तालिबान संबंधः अफगान भू-राजनीति में भारत

2021 में तालिबान के सत्ता में आगमन के परिणामस्वरूप दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। भारत ने इस नवीन परिदृश्य में मानवीय संकट और क्षेत्रीय हितों के मध्य संतुलन साधते हुए एक व्यावहारिक रणनीति अपनाई। यह कदम केवल तालिबान के उदय की प्रतिक्रिया नहीं था, अपितु भारत की व्यापक क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने की इच्छा का भी परिचायक था। जनवरी 2025 में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री और तालिबान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक ने भारत की विदेश नीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दिया।

पृष्ठभूमिः

- 2021 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का पुनरुत्थान दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस घटनाक्रम ने क्षेत्र के देशों, विशेषकर भारत को अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। भारत ने इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। एक ओर, उसने अफगानिस्तान में मानवीय संकट को देखते हुए सहायता प्रदान की। दूसरी ओर, उसने अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए तालिबान शासन के साथ संवाद भी बनाए रखा।
- हालांकि भारत ने औपचारिक रूप से तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी, परंतु उसने काबुल में एक तकनीकी मिशन स्थापित करके अपनी उपस्थिति बनाए रखी। यह सतर्क जुड़ाव भारत को अपने रणनीतिक हितों की सुरक्षा करते हुए अफगानिस्तान में मानवीय सहायता प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है।

भू-राजनीतिक गतिशीलता और पाकिस्तान की भूमिकाः

- अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता की वापसी से, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह बदलाव भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को गहराई से प्रभावित कर रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का मुद्दा इस तनाव का एक प्रमुख कारण है। टीटीपी, जो पाकिस्तान के आदिवासी क्षेत्रों में पश्तून राष्ट्रवाद स्थापित करना चाहता है, को तालिबान का समर्थन प्राप्त है। यह समर्थन पाकिस्तान के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन गया है। पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकानों को नष्ट करने के लिए अफगानिस्तान में हवाई हमले किए हैं, जिसके कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत ने पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की है। भारत का मानना है कि यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है।
- अफगानिस्तान की धरती से संचालित 6,000 से अधिक टीटीपी लड़ाकों की उपस्थिति के साथ-साथ टीटीपी के साथ तालिबान के संबंध, पाकिस्तान के सुरक्षा परिदृश्य को जटिल बनाते हैं। अफगानिस्तान के सोवियत कब्जे के दौरान पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन किया था। यह विडंबनापूर्ण है कि आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बन गया है। इन विद्रोही समूहों की उपस्थिति, तालिबान के अल-कायदा के साथ संबंध क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हैं।

तालिबान के प्रति भारत का रणनीतिक दृष्टिकोणः

- अफगानिस्तान के प्रति भारत का दृष्टिकोण मानवीय चिंताओं और भू-राजनीतिक हितों के एक जटिल मिश्रण से प्रभावित है। तालिबान शासन अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के प्रयास में है, जबकि भारत अपने व्यापक क्षेत्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है।
- **मानवीय सहायताः** भारत अफगानिस्तान को मानवीय सहायता का एक महत्वपूर्ण प्रदाता रहा है। इसकी सहायता में COVID-19, पोलियो और तपेदिक के लिए दवाएं और टीके, साथ ही शीतकालीन कपड़े, स्वच्छता किट और आवश्यक खाद्य आपूर्ति शामिल हैं। 2024-25 के केंद्रीय बजट में, भारत ने अफगानिस्तान की मानवीय सहायता के लिए 200 करोड़ आवंटित किए, जो अफगान लोगों का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसके अलावा,

मिश्री-मुत्ताकी वार्ता के बाद, भारत ने अफगानिस्तान के स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थी पुनर्वास के लिए अतिरिक्त समर्थन का वचन दिया है।

- **क्षेत्रीय साझेदारी का लाभ उठाना:** भारत की क्षेत्रीय रणनीति में पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी भी शामिल है। एक उल्लेखनीय सहयोग ईरान के साथ है, विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह के माध्यम से, जोकि भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान को सहायता और व्यापार पहुंचाने के लिए एक रणनीतिक मार्ग प्रदान करता है। यह साझेदारी न केवल अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को बढ़ाती है बल्कि ईरान के साथ काबुल पर महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ व्यापक क्षेत्रीय मध्यस्थता के लिए भी मार्ग खोलती है।
- **सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर:** भारत की सांस्कृतिक कूटनीति अफगानिस्तान के साथ अपने जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अफगानिस्तान में क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता ने भारत के लिए अफगान युवाओं के साथ जुड़ने के अवसर पैदा किए हैं, विशेष रूप से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के माध्यम से, जहां राशिद खान जैसे अफगान खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बनाई है। इसके अलावा, भारत ने 2021 से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के माध्यम से 3,000 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान करके अफगान छात्रों का समर्थन जारी रखा है। ये पहल लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करती हैं और क्षेत्र में भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाती हैं।

चुनौतियाँ और अवसर:

भारत का तालिबान के साथ जुड़ाव कई अवसर प्रस्तुत करता है, यह चुनौतियों से भी रहित नहीं है।

- **चुनौतियाँ:**
  - » **क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** अल-कायदा, टीटीपी और आईएसकेपी जैसे आतंकवादी समूहों की उपस्थिति एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। ये संगठन क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा पैदा करते हैं और भारत के राजनयिक प्रयासों को जटिल बनाते हैं।
  - » **पाकिस्तान का प्रभाव:** पाकिस्तान द्वारा तालिबान सहित आतंकवादी समूहों को कथित तौर पर समर्थन देने से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है, विशेषकर डूरंड लाइन के आसपास। डूरंड लाइन, जो एक औपनिवेशिक युग की सीमा है, को तालिबान द्वारा मान्यता नहीं दी गयी है।
  - » **आंतरिक तालिबान नीतियां:** तालिबान का अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार, मानवाधिकार रिकॉर्ड और इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या विवादास्पद मुद्दे हैं। इन नीतियों ने वैश्विक स्तर पर व्यापक आलोचना को आकर्षित किया है।
- **अवसर:**
  - » **पारंपरिक संबंधों को मजबूत करना:** अफगानिस्तान और भारत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध साझा करते हैं। भारत विकास परियोजनाओं और मानवीय सहायता के माध्यम से अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को पुनर्निर्माण और मजबूत करने के लिए इन कनेक्शनों का लाभ उठा सकता है।
  - » **क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना:** तालिबान के साथ रचनात्मक रूप से जुड़कर, भारत के पास क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देने और अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन के प्रभाव का प्रतिकार करने का अवसर है।
  - » **'एक्ट वेस्ट' नीति का विस्तार:** अफगानिस्तान का रणनीतिक स्थान भारत की एक्ट वेस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। इस नीति में अफगानिस्तान को एकीकृत करने से भारत की क्षेत्रीय उपस्थिति और प्रभाव बढ़ता है।

अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे में भारत का नि.वेश:

भारत ने अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जोकि देश के विकास के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं:

- **सलमा बांध:** इसे अफगान-भारत मैत्री बांध के रूप में जाना जाता है, 2016 में उद्घाटित इस परियोजना से अफगानिस्तान की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ती है और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
- **जरंज-देलाराम राजमार्ग:** भारत के सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित, यह राजमार्ग अफगानिस्तान को ईरान के चाबहार बंदरगाह से जोड़ता है, एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग प्रदान करता है। यह बुनियादी ढांचा परियोजना वैश्विक बाजारों के साथ अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

अफगानिस्तान के साथ भारत का जुड़ाव क्यों महत्वपूर्ण है

- **भू-राजनीतिक हित:** भारत क्षेत्र में पाकिस्तान की भूमिका का प्रतिकार करने और मध्य एशिया तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, जो बढ़ते हुए आर्थिक और भू-राजनीतिक महत्व का क्षेत्र है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:** भारत अफगानिस्तान में बढ़ती अस्थिरता को गंभीरता से देख रहा है, क्योंकि इससे पूरे दक्षिण एशिया में अशांति फैलने का खतरा है। तालिबान का सत्ता में आना और पाकिस्तान में जारी विद्रोह ने क्षेत्र की सुरक्षा को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है।
- **निवेशों को सुरक्षित करना:** भारत ने अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं में भारी निवेश किया है और क्षेत्र में अपने दीर्घकालिक हितों को सुरक्षित करने के लिए भारत के लिए इन निवेशों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्षः

तालिबान के साथ भारत का जुड़ाव एक जटिल भू-राजनीतिक स्थिति के लिए एक व्यावहारिक प्रतिक्रिया है। हालांकि देश ने औपचारिक रूप से तालिबान को मान्यता देने से परहेज किया है, लेकिन इसका बहुआयामी दृष्टिकोण-मानवीय सहायता, क्षेत्रीय साझेदारी और सांस्कृतिक कूटनीति पर केंद्रित-अफगानिस्तान के कल्याण और क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आतंकवादी समूहों, पाकिस्तान के प्रभाव और तालिबान की विवादास्पद आंतरिक नीतियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, भारत की सक्रिय कूटनीति तेजी से अस्थिर वातावरण में रचनात्मक जुड़ाव के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। मानवीय सहायता को भू-राजनीतिक विचारों के साथ संतुलित करके, भारत क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देना चाहता है, साथ ही अपने हितों को संरक्षित करना और अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को मजबूत करना चाहता है।

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहली उच्च-स्तरीय राजनयिक वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और तालिबान ने 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद अपनी पहली उच्च- स्तरीय राजनयिक वार्ता आयोजित की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने दुबई में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। वार्ता में सुरक्षा, मानवीय सहायता और ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई?

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएंः** भारत ने अफगानिस्तान से भारत-विरोधी आतंकवादी गतिविधियों के बारे में चिंता व्यक्त की। तालिबान ने भारत को आश्वासन दिया कि वह इन सुरक्षा खतरों का समाधान करेगा।
- **मानवीय सहायताः** भारत ने खाद्य, दवाइयाँ और टीके सहित आवश्यक सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अफगान पक्ष ने भारत द्वारा किए गए पिछले शिपमेंट्स, जिनमें गेहूं और भूकंप राहत सामग्री शामिल थी, की सराहना की।
- **विकास परियोजनाएंः** दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भविष्य की विकास परियोजनाओं में भारत की भागीदारी पर चर्चा की।
- **चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापारः** क्षेत्रीय संपर्क के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह के उपयोग को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में रेखांकित किया गया। भारत को इस बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट दी गई है, जिससे अफगानिस्तान के साथ व्यापार को सुगम बनाया जा सकता है।
- **खेल सहयोगः** चर्चा में क्रिकेट संबंधों को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया गया, जिसमें भारत द्वारा अफगान क्रिकेटरों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके समर्थन किया गया।

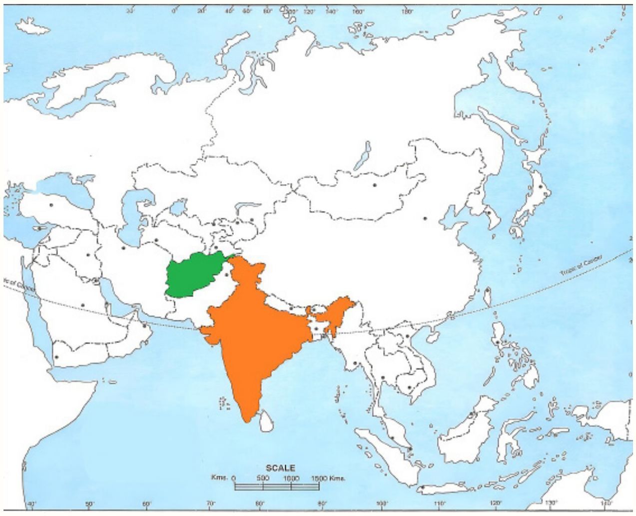

अफगानिस्तान के लिए भारत क्या कर रहा है?

भारत मानवीय सहायता और विकास पहलों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता में सक्रिय रूप से शामिल रहा हैः

- **मानवीय सहायताः** भारत ने गेहूं, दवाइयाँ और जाड़े के कपड़े जैसे आवश्यक आपूर्तियाँ भेजी हैं।
- **स्वास्थ्य क्षेत्र में समर्थनः** भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में और सहायता प्रदान करने की योजना बना रहा है, जिसमें चिकित्सा संसाधन भी शामिल हैं।
- **शरणार्थियों का पुनर्वासः** भारत विशेष रूप से पाकिस्तान से लौटने वाले अफगान शरणार्थियों के पुनर्वास में सहायता कर रहा है।
- **विकास पहलः** भारत अफगानिस्तान में दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं में शामिल होने की संभावना तलाश रहा है।

अफगानिस्तान का भारत के लिए महत्वः

अफगानिस्तान विभिन्न कारणों से भारत के लिए महत्वपूर्ण हैः

- **भू-राजनीतिक विचारः** पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया की सीमा से लगे अफगानिस्तान का स्थान भारत की सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है।
- **व्यापार और संपर्कः** चाबहार बंदरगाह का उपयोग भारत द्वारा अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाता है।
- **जन-जन संबंध (People-To-People Ties):** भारत और अफगानिस्तान के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध हैं, जो क्षेत्र में भारत के प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भारत के सामने चुनौतियाँः

तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के साथ व्यवहार करने में

भारत के सामने कई चुनौतियाँ हैं:

- **सुरक्षा जोखिम:** यह सुनिश्चित करना कि अफगानिस्तान भारत-विरोधी आतंकवादी समूहों का गढ़ न बने, भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है।
- **राजनीतिक संवेदनशीलताएं:** मानवाधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं और अल्पसंख्यकों के संबंध में चिंताओं को देखते हुए, भारत चिंतित है।
- **क्षेत्रीय गतिशीलता:** तालिबान के साथ जुड़ते हुए भारत को पाकिस्तान और ईरान जैसे पड़ोसी देशों के साथ जटिल संबंधों को नेविगेट करना होगा।
- **प्रतिबंधों का जोखिम:** हालांकि भारत को चाबहार पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट दी गई है, लेकिन बदलते अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में, भविष्य में प्रतिबंधों का जोखिम अभी भी मौजूद है।

व्यापार बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह के उपयोग की पेशकश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान प्रभाग के संयुक्त सचिव श्री जे.पी. सिंह के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने काबुल में अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब और अन्य वरिष्ठ अफगान नेताओं के साथ बैठक की।

बैठक के मुख्य विवरण:

- **चाबहार बंदरगाह का प्रस्ताव:**
  - » भारत ने अफगान व्यवसायों को चाबहार बंदरगाह तक पहुँच प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो ईरान में स्थित एक रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गहरे पानी वाला बंदरगाह है, जिसका विकास और संचालन भारत द्वारा किया जाता है।
  - » चाबहार बंदरगाह भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच व्यापार के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार है, जो पाकिस्तान को दरकिनार करता है, जिससे अफगानिस्तान की वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ती है और आयात-निर्यात की प्रक्रिया को सुगम बनाता है।
- **मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित:**
  - » तालिबान द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद, भारत की ओर से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता जारी रखी जाएगी।
  - » भारत ने लगातार अफगान लोगों को गेहूं, दवाइयाँ और चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराई है।

भारत का कूटनीतिक रुख:

- भारत तालिबान शासन को मान्यता नहीं देता है, जिसने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया था। हालांकि, भारत ने काबुल में एक कार्यात्मक राजनयिक उपस्थिति बनाए रखी है।
- भारत का दूतावास अब भी कार्यरत है और मानवीय प्रयासों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने के लिए जून 2022 से एक तकनीकी टीम वहाँ तैनात है।

चाबहार बंदरगाह का महत्व:

- सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की रणनीति का प्रमुख केंद्र है।
- 500 मिलियन डॉलर के निवेश से विकसित चाबहार, अफगानिस्तान को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए समुद्र तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।
- यह अफगानिस्तान के खनिज, कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प जैसे निर्यातों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने में सक्षम बनाता है और ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है।

Chabahar Port: Key to India's Central Asia and Europe Trade Links

Source: India today

भारत और अफगानिस्तान के बीच राजनयिक संबंध:

- **ऐतिहासिक संदर्भ:**
  - » भारत ने 1980 के दशक में सोवियत समर्थित लोकतांत्रिक गणराज्य अफगानिस्तान को मान्यता दी और उसके साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे।
  - » 1990 के दशक में अफगान गृह युद्ध और तालिबान सरकार के दौरान भारत के संबंध कमजोर हो गए थे।
- **2001 के बाद के घटनाक्रम:**
  - » अफगानिस्तान पर अमेरिकी नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद, भारत ने नवगठित लोकतांत्रिक सरकार के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और इसके बाद के वर्षों में अफगानिस्तान को सहायता और पुनर्निर्माण में मदद की

भारत–अफगानिस्तान संबंधों में हालिया घटनाक्रम:

- **दूतावास पुनः खोला गया:** 2022 में, भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोला, जिसे अगस्त 2021 में तालिबान के अधिग्रहण के बाद बंद कर दिया गया था।
- **मानवीय सहायता:** भारत ने अपने मानवीय प्रयास जारी रखे हैं और संकट के दौरान अफगानिस्तान की मदद के लिए 500,000 कोविड वैक्सीन खुराक और 2,500 मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराया है।
- **बुनियादी ढांचा विकास:** भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसमें सलमा डैम और अफगान संसद भवन जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ शामिल हैं।
- **आर्थिक सहयोग:** भारत और अफगानिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और दोनों देशों के बीच माल के सुचारू परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए दो हवाई गलियारे स्थापित किए हैं, जिससे आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा मिला है।

बांग्लादेश

गंगा जल संधि के नवीनीकरण हेतु बैठक

संदर्भ:

हाल ही में भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग ने कोलकाता में दो दिवसीय बैठक आयोजित की, जिसमें गंगा जल संधि पर विस्तार से चर्चा की गई। यह संधि 1996 से दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को नियंत्रित कर रही है और 2026 में समाप्त होने वाली है। इस पृष्ठभूमि में हुई इस बैठक का उद्देश्य संधि के नवीनीकरण तथा जल बंटवारे से संबंधित अन्य मुद्दों को संबोधित करना था।

गंगा जल संधि के बारे में:

- 1996 में हस्ताक्षरित गंगा जल संधि, गंगा नदी के जल संसाधनों के न्यायसंगत और संतुलित वितरण को सुनिश्चित करती है। यह संधि शुष्क मौसम (Dry Season) के दौरान किसी एक देश द्वारा जल के अनियंत्रित मोड़ (diversion) को रोकने के लिए एक संरचनात्मक व्यवस्था प्रदान करती है।

संयुक्त नदी आयोग (JRC) की भूमिका:

- 1972 में स्थापित संयुक्त नदी आयोग, भारत और बांग्लादेश के बीच 54 सीमा-पार नदियों के प्रबंधन की देखरेख करता है। यह आयोग गंगा जल संधि के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

चर्चा में शामिल मुख्य मुद्दे:

- **गंगा जल संधि का नवीनीकरण:** संधि के 2026 में समाप्त होने के मद्देनजर, दोनों देशों ने इसके नवीनीकरण और अद्यतन पर विचार-विमर्श किया। जल-बंटवारे से जुड़ी नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, संधि को अधिक प्रभावी और समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप बनाने पर चर्चा हुई।
- **गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियों का जल-बंटवारा:** भारत से बांग्लादेश में प्रवाहित होने वाली अन्य नदियों के जल-बंटवारे की आवश्यकता को देखते हुए, बैठक में इस विषय पर भी विचार किया गया। इन अतिरिक्त नदियों में उचित जल वितरण की सिफारिश करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया। यह हाल के वर्षों में एक प्रमुख मुद्दा बन गया है।

- **जल प्रवाह का मापन:** जल प्रवाह के सटीक मापन और डेटा साझाकरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण विषय रहा। बैठक में जल प्रवाह मापने की तकनीकी चुनौतियों को हल करने के लिए दोनों देशों के विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श किया गया।

- **न्यायसंगत जल वितरण सुनिश्चित करना:** संधि का मूल सिद्धांत जल का समान और निष्पक्ष वितरण है। दोनों देशों ने एकतरफा जल-आवंटन को रोकने और विशेष रूप से शुष्क मौसम के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की।

बैठक का महत्व:

- यह बैठक अगस्त 2024 में बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद पहली महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता थी। यह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और साझा जल संसाधनों पर सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करने में एक महत्वपूर्ण कदम था।

भारत ने बांग्लादेश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविध समाप्त की

सन्दर्भ:

भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा आधिकारिक रूप से वापस ले ली है। इसका कारण भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर अत्यधिक भीड़ बताया गया है। यह सुविधा 2020 से लागू थी, जिसके तहत बांग्लादेश अपने निर्यात को भारतीय भूमि सीमा शुल्क चौकियों (Land Customs Stations) के माध्यम से भारत के लॉजिस्टिक हब्स होते हुए अंतिम गंतव्यों तक पहुंचा सकता था। यह निर्णय 8 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुआ, जब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक अधिसूचना जारी कर बांग्लादेश के भूटान, म्यांमार और नेपाल के साथ व्यापार के लिए यह सुविधा समाप्त कर दी।

भारत द्वारा सुविधा बंद करने के कारण:

- हालांकि भारतीय अधिकारियों ने इस निर्णय को सीधे किसी राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़ने से इनकार किया हो, लेकिन यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने बीजिंग दौरे के दौरान एक विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने अपने बयान में चीन और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच व्यापार को बांग्लादेशी बंदरगाहों के माध्यम से बढ़ाने का सुझाव दिया था।

बांग्लादेश के निर्यात क्षेत्र पर असर

- यह ट्रांसशिपमेंट सुविधा बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह उद्योग भूटान, म्यांमार और नेपाल के बाजारों तक पहुंच के लिए भारत के ढांचागत संसाधनों पर निर्भर था। बांग्लादेश की सीमित समुद्री पहुंच और सीधी शिपिंग विकल्पों की कमी के कारण, उसे भारतीय मार्गों का उपयोग करना पड़ता था।
- इस फैसले की घोषणा ऐसे समय पर हुई है जब ढाका में नववर्ष की तैयारियों चल रही हैं, जिससे बांग्लादेश के व्यापारियों और उद्योगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। व्यापारी पहले से ही व्यापारिक यात्राओं के लिए भारतीय वीज़ा पाने में देरी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

विश्व व्यापार संगठन के नियम:

- विश्व व्यापार संगठन के नियमों "विशेष रूप से शुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौता1994 के अनुच्छेद 5 और व्यापार सुविधा समझौते के अनुच्छेद 11" के तहत, सदस्य देशों को स्थल से घिरे देशों (landlocked countries) के लिए वस्तुओं के आवागमन की स्वतंत्रता देनी होती है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने इस निर्णय पर चिंता जताते हुए कहा है कि भारत का यह निर्णय विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों और प्रतिबद्धताओं पर सवाल खड़े कर सकता है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों से जुड़े प्रमुख मुद्दे:

- **सीमा विवाद:** 2015 की भूमि सीमा समझौते के बावजूद कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव अब भी बना हुआ है।
- **जल बंटवारा:** तीस्ता और गंगा नदियों के जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है, जिससे बांग्लादेश की कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **नागरिकता संशोधन कानून:** बांग्लादेश ने इस कानून को पक्षपातपूर्ण बताते हुए इसे द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान पहुँचाने वाला निर्णय माना है।
- **सीमा पर तनाव:** सीमा पर हुए तनाव व कुछ घटनाओं के कारण स्थानीय नागरिकों और सरकार के बीच तनाव उत्पन्न है।
- **व्यापारिक मुद्दे:** भारत के साथ व्यापार में असंतुलन और उसकी कुछ नीतियों का बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना चिंता का विषय बना हुआ है।
- **राजनयिक तनाव:** हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और नेतृत्व परिवर्तन ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं।

भारत ने इस निर्णय को अपनी आंतरिक लॉजिस्टिक आवश्यकताओं और बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव के संदर्भ में लिया हुआ कदम बताया है। हालांकि, व्यापक परिप्रेक्ष्य में यह फैसला केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं लगता, बल्कि इसमें व्यापार, क्षेत्रीय संपर्क और कूटनीतिक समीकरणों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। यह स्थिति भारत-बांग्लादेश संबंधों में पहले से मौजूद संवेदनशीलताओं को और जटिल बना सकती है।

चीन

भारत-चीन संबंध के 75 वर्ष: प्रतिस्पर्धात्मक सह-अस्तित्व की नई संरचना

2025 में जब भारत और चीन अपने राजनयकि संबंधों के 75 साल पूरे कर रहा है, तो यह केवल एक औपचारकि अवसर नहीं होगा। यह मील का पत्थर ऐसे समय पर आ रहा है जब एशयि और पूरी दुनयि में भू-राजनीतकि परस्थितियिाँ तेज़ी से बदल रही हैं। 1950 में आपसी मान्यता और एशयिाई एकजुटता के वादे के साथ शुरू हुआ संबंध कई उतार चढ़ाव देख चूका है जहाँ एक ओर सीमा ववाद हैं, वहीं दूसरी ओर गहरी आर्थकि नर्भिरता, रणनीतकि प्रतस्पि्र्धा और कुछ हद तक सहयोग भी देखने को मलिता है। आज भारत-चीन के बीच का रश्ति "प्रतस्पि्र्धी सह-अस्ततिव" (competitive coexistence) के रूप में जाना जाता है, जो 21वीं सदी की उनकी आपसी रणनीतकिी पहचान बन गया है।

इतिहास और विकास की कहानी:

- भारत, चीन की पीपुल्स रिपब्लिक को मान्यता देने वाला पहला गैर-कम्युनिस्ट देश था। शुरुआती दिनों में दोनों देशों ने पैन-एशियाई सोच और गुटनिरपेक्षता को अपनाया। 1954 में पंचशील समझौते ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की दिशा में उम्मीद जगाई। लेकिन यह आशावाद ज़्यादा समय तक टिक नहीं सका।
- 1962 में अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश (जिसे चीन दक्षिण तिब्बत कहता है) को लेकर भारत-चीन युद्ध हुआ, जिसने आपसी भरोसे को तोड़ दिया। यह युद्ध आज भी दोनों देशों के रिश्तों की नींव पर एक स्थायी छाया की तरह मौजूद है।
- इसके बाद से ही वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) को लेकर विवाद बना रहा है, खासकर पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में। 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प, जिसमें 20 भारतीय और कम से कम 4 चीनी सैनिक मारे गए, एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। इसके बाद भारत की चीन नीति में एक स्पष्ट बदलाव आया—अब संबंध सैन्य तैयारी, क्षेत्रीय संप्रभुता और दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के आधार पर तय होते हैं।

भारतीय विदेश नीति में चीन की भूमिका:

- आज चीन भारत की विदेश और सुरक्षा नीति को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा बाहरी कारक बन चुका है। भारत का हर बड़ा फैसला चाहे वह हिमालयी इलाकों में आधारभूत ढाँचे का निर्माण हो, हिंद महासागर में नौसैनिक गतिविधियाँ हों, या क्षेत्रीय संगठनों में भागीदारी, कहीं न कहीं चीन की गतिविधियों और रणनीति से जुड़ा होता है।
- **सैन्य तैयारी:** पूर्वी लद्दाख में अब भारत के करीब 60,000 सैनिक स्थायी रूप से तैनात हैं। दोनों देशों ने सीमा पर बड़े स्तर पर बुनियादी ढाँचे का विकास किया है, चीन ने अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के ज़रिए और भारत ने रणनीतिक सड़कें, पुल और लॉजिस्टिक्स तैयार कर जवाब दिया है।
- **सीमा विवाद की स्थिति:** अब तक कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत हो चुकी है, लेकिन ज़मीनी हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। चीन अब भी प्रमुख विवादित क्षेत्रों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि भारत अप्रैल 2020 की स्थिति को बहाल किए बिना सामान्य संबंधों की बहाली को अस्वीकार करता है।
- **आर्थिक जुड़ाव और निर्भरता:** रणनीतिक तनावों के बावजूद भारत-चीन व्यापारिक संबंध मज़बूती से बने हुए हैं। इसका कारण यह है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक निर्भरता संरचनात्मक है, इसे पूरी तरह से तोड़ना आसान नहीं है।
- **व्यापार का आँकड़ा:** वित्त वर्ष 2024–25 में दोनों देशों के बीच व्यापार $115 अरब डॉलर से अधिक रहा, जिसमें भारत का व्यापार घाटा लगभग $100 अरब डॉलर था।

मुख्य क्षेत्रों में निर्भरता:

  » **फार्मा क्षेत्र:** भारत की दवाओं में इस्तेमाल होने वाले 60–70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स (APIs) चीन से आते हैं।
  » **इलेक्ट्रॉनिक्स:** स्मार्टफोन और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले लगभग 80% पुर्जे चीन से आयात होते हैं।
  » **सौर ऊर्जा:** भारत में उपयोग होने वाले 80–90% सोलर पैनल चीन से आते हैं।

- भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत कई कदम उठाए हैं, जिससे घरेलू निर्माण को बढ़ावा मिले। लेकिन निकट भविष्य में चीन से पूरी तरह आर्थिक दूरी बनाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार आपूर्ति श्रृंखला को विविध बनाने और रणनीतिक क्षेत्रों में जोखिम को कम करने की दिशा में काम कर रही है।

दक्षिण एशिया: एक नया रणनीतिक रणभूमि

- चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र को सीधी चुनौती दे रही है:
  - **श्रीलंका:** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत हंबनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए लीज़ पर लेना।
  - **नेपाल:** पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और अन्य बीआरआई-संलग्न बुनियादी ढांचे का निर्माण।
  - **मालदीव:** आवास और संपर्क परियोजनाओं में भारी चीनी निवेश।
- **भारत के जवाबी कदम:**
  - विकास सहायता और क्षमता निर्माण में वृद्धि।
  - आपातकालीन राहत में नेतृत्व (जैसे भूकंप और महामारी के दौरान सहायता)।
  - रक्षा सहयोग और रियायती ऋण की पेशकश को बढ़ाना।
- हालांकि भारत ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन चीन की "चेकबुक डिप्लोमेसी" (पैसे के बल पर प्रभाव बढ़ाना) और सूचनात्मक प्रभाव अभियानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत को अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि संस्थागत और जनता-आधारित क्षेत्रीय रणनीति अपनानी होगी।

बांग्लादेश का कारक और भू-राजनीतिक असर:

- **विवादास्पद बयान:** हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने चीन में कहा कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र "लैंडलॉक्ड" यानी चारों ओर ज़मीन से घिरा हुआ है। यह बात भले ही भूगोल के हिसाब से सही हो, लेकिन इसे चीन में कहना भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर चुभने वाली बात मानी गई।
- **रणनीतिक खतरा:** बांग्लादेश ने चीन को ललमोनिरहाट एयरबेस के पास निवेश की अनुमति दी है, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद नज़दीक है। यह कॉरिडोर भारत के मुख्य हिस्से को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है और देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम इलाका है।
- **आर्थिक प्रतिक्रिया:** इसके जवाब में भारत ने बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट (RMG) निर्यात के लिए जरूरी ट्रांज़िट सुविधा रोक दी। इससे 2024 में करीब 0.5 अरब डॉलर का व्यापार प्रभावित हुआ और लगभग 4,000 फैक्ट्रियों व 40 लाख मज़दूरों की रोज़ी-रोटी पर असर पड़ा।

- इस तनाव का असर BBIN (बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल) कॉरिडोर और BIMSTEC ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान (जिसकी लागत $124 अरब है) पर भी पड़ा है। पहले से ही दक्षिण एशिया में देशों के बीच व्यापार बहुत कम (सिर्फ 5%) होता है, और अब ये योजनाएं और ज़्यादा धीमी हो सकती हैं, जबकि ASEAN जैसे क्षेत्रीय समूहों में यह आंकड़ा 25% तक है।

जल सुरक्षा की चुनौती:

- चीन द्वारा यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्र) नदी पर, अरुणाचल सीमा के पास, बाँध बनाए जाने की योजना ने भारत में चिंता बढ़ा दी है:
  - **कोई जल-साझाकरण संधि नहीं:** पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के विपरीत, भारत और चीन के बीच जल साझा करने को लेकर कोई बाध्यकारी समझौता नहीं है।
  - **सैन्यीकरण का खतरा:** चीन द्वारा एकतरफा जल मोड़ने, डाटा न देने और पारिस्थितिक नुकसान की आशंका बनी रहती है।
  - **हालिया प्रगति:** 2025 में हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने की विशेषज्ञ स्तर की वार्ता फिर से शुरू हुई, लेकिन आपसी भरोसा अभी भी बहुत कम है।

भारत-चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ केवल भावनात्मक स्मरण का अवसर नहीं, बल्कि रणनीतिक स्पष्टता का क्षण है। इस अस्थिर भू-राजनीतिक दौर में, यह द्विपक्षीय रिश्ता एशिया की स्थिरता या अस्थिरता का निर्धारक तत्व बन गया है। चीन की चुनौती संरचनात्मक

है और यह भारत के लिए संकेत है कि उसे आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाना होगा, रणनीतिक स्वायत्तता को सुरक्षित करना होगा और क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। भारत को अब केवल एक संतुलनकर्ता नहीं, बल्कि संस्थानों, बुनियादी ढांचे और विचारों में निवेश करके एशियाई व्यवस्था का संरक्षक बनना होगा, जो महाद्वीप के भविष्य को आकार दे सकें। आने वाला समय इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत कैसे इस प्रतिस्पर्धा को बिना टकराव बढ़ाए संभालता है, संवाद करता है बिना आत्मसमर्पण किए, और कैसे टकराव को सह-अस्तित्व की रूपरेखा में बदलता है।

नेपाल

नेपाल का राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य: चुनौतियाँ और संभावनाए

नेपाल इस समय बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की लहर से गुजर रहा है, जो भ्रष्टाचार और गणतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रति गहरी जनता की असंतुष्टि को उजागर करता है। हाल के हिंसक प्रदर्शनों से लोगों की नाराज़गी स्पष्ट दिखाई देती है और बड़ी संख्या में लोग पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में जुट रहे हैं। यह आंदोलन उन आरोपों के बीच जोर पकड़ रहा है, जिनमें राजनीतिक नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और गणतंत्र व्यवस्था को सामाजिक-आर्थिक संकटों का समाधान करने में विफल माना जा रहा है। 2008 में राजशाही के उन्मूलन के बाद नेपाल की राजनीतिक रूपांतरण प्रक्रिया अस्थिरता, कमजोर गठबंधन और शासन संबंधी चुनौतियों से भरी रही है। राजनीतिक अनिश्चितता के साथ-साथ नेपाल की अर्थव्यवस्था भी संरचनात्मक कठिनाइयों से जूझ रही है, जो पर्यटन, प्रवासी आय (रेमिटेंस) और कृषि निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है। नेपाल की विदेश नीति भी रणनीतिक रूप से जटिल बनी हुई है, जहां उसे भारत, चीन और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना पड़ता है।

नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल:

- ऐतिहासिक रूप से, नेपाल में एक पूर्णरूप से राजशाही थी, जिसमें समय-समय पर एक संवैधानिक संसद के साथ सत्ता साझा की जाती थी। हालांकि, 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में देश की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई।
- 2001 में शाही हत्याकांड में तत्कालीन राजा बीरेन्द्र और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या हो गई, जिससे नेपाल में भारी राजनीतिक अस्थिरता आ गई। इसके बाद, 2005 में राजा ज्ञानेंद्र शाह द्वारा सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के प्रयासों ने संकट को और गहरा कर दिया। इस वजह से व्यापक जनप्रदर्शन हुए, जिसके चलते अंततः उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी।
- 2008 में नेपाल ने राजशाही को समाप्त कर एक संघीय गणराज्य की स्थापना की। हालांकि, अपेक्षित स्थिरता के बजाय, राजनीति में गुटबाजी और गठबंधन सरकारों का संघर्ष जारी रहा। 2006 में गृहयुद्ध समाप्त होने के बाद से नेपाल में लगातार सरकारें बदलती रहीं और पिछले 16 वर्षों में 13 अलग-अलग सरकारें सत्ता में आईं। कम्युनिस्ट गुटों और नेपाली कांग्रेस के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण कमजोर गठबंधन बनते रहे, जिससे नीति निर्माण और आर्थिक सुधारों में बाधा उत्पन्न हुई।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य:

- 2022 के संसदीय चुनावों के बाद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) के नेता पुष्प कमल दाहाल (प्रचंड) ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के साथ गठबंधन कर प्रधानमंत्री पद संभाला। हालांकि, यह गठबंधन जल्द ही टूट गया और जुलाई 2024 में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) के नेता के.पी. शर्मा ओली ने चौथी बार प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया। इस बार उन्होंने नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन किया।
- गठबंधन समझौते के अनुसार, ओली और नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा 2027 के आम चुनावों तक बारी-बारी से प्रधानमंत्री पद संभालेंगे। हालांकि, इस व्यवस्था के बावजूद नेपाल का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। बार-बार गठबंधन बनने और टूटने से सरकार अस्थिर बनी हुई है, जिससे दीर्घकालिक नीतियों को लागू करने में कठिनाई हो रही है। इसके अलावा, संक्रमणकालीन न्याय, मानवाधिकार उल्लंघन और राजनीतिक जवाबदेही से जुड़े अनसुलझे मुद्दे नेपाल के लोकतांत्रिक विकास को चुनौती दे रहे हैं।

आर्थिक चुनौतियाँ और प्रगति:

नेपाल की अर्थव्यवस्था लंबे समय से विभिन्न बाधाओं का सामना कर रही है, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाएँ और बाहरी निर्भरता शामिल हैं। कोविड-19 महामारी ने प्रमुख क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित किया, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ सुधार के संकेत मिले हैं।

- **आर्थिक वृद्धि और प्रमुख क्षेत्र:**
  - » **जीडीपी वृद्धि:** 2024 में नेपाल की अर्थव्यवस्था 4% की दर से बढ़ी, जिसमें पर्यटन राजस्व में 32% की वृद्धि और कृषि

निर्यात में पुनरुत्थान मुख्य कारक रहे।

» **हाइड्रोपावर विस्तार:** नेपाल ने 450 मेगावाट (MW) की नई जलविद्युत क्षमता जोड़ी, जिससे बिजली निर्यात की संभावना मजबूत हुई।

» **रेमिटेंस:** 2023 में प्रवासी आय (रेमिटेंस) नौ वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई, जिससे घरेलू खर्च और आमदनी को समर्थन मिला।

- हालांकि, इन सुधारों के बावजूद, नेपाल कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। विश्व बैंक ने निजी और सार्वजनिक निवेश में गिरावट की चेतावनी दी है, जिसका संकेत पूँजीगत वस्तुओं के आयात में कमी और सरकारी पूँजीगत खर्च में गिरावट से मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी नेपाल के बैंकिंग तंत्र, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में स्थिरता को लेकर चिंता जताई है।

राजकोषीय और मौद्रिक चुनौतियाँ:

» **राजकोषीय घाटा:** नेपाल का राजकोषीय घाटा सात वर्षों के निचले स्तर पर आ गया है, लेकिन राजस्व संग्रह की कमजोरी बनी हुई है।

» **मुद्रास्फीति:** 2024 में मुद्रास्फीति दर घटकर 5.4% रह गई, जो 2023 में 7.7% थी। यह मुख्य रूप से गैर-खाद्य और सेवा क्षेत्रों में कीमतों में कमी के कारण हुआ।

» **विदेशी ऋण:** 1976 से नेपाल नौ बार IMF की सहायता ले चुका है। हाल ही में 2022 में शुरू किया गया $372 मिलियन का विस्तारित ऋण सुविधा कार्यक्रम इस वर्ष समाप्त होने वाला है।

- नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख चिंता पूँजीगत परियोजनाओं का धीमा कार्यान्वयन है, जिससे बुनियादी ढाँचे का विकास और आर्थिक गति बाधित होती है। IMF ने नेपाल को पूँजीगत निवेश में तेजी लाने की सलाह दी है ताकि दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को मजबूत किया जा सके।

भारत-नेपाल संबंध:

- भारत की ऐतिहासिक रूप से नेपाल की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध हैं और नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसके नागरिकों को भारत में बिना वीजा के यात्रा करने की अनुमति है।

» **व्यापार संबंध:** भारत नेपाल के कुल बाहरी व्यापार का 64% हिस्सा रखता है, और 2023 में द्विपक्षीय व्यापार $8.85 बिलियन तक पहुँच गया।

» **हाइड्रोपावर सहयोग:** नेपाल भारत को अगले दशक में 10,000 मेगावाट विद्युत् निर्यात करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुका है।

» **विकास सहायता:** भारत नेपाल में हवाई अड्डों, पाइपलाइनों और पावर ग्रिड जैसे बुनियादी ढाँचे के विकास में प्रमुख योगदान देता है।

- हालांकि, नेपाल में कुछ राजनीतिक दलों ने भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को लेकर चिंता जताई है, जिससे कभी-कभी दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं।

नेपाल-चीन संबंध:

» **चीन के साथ व्यापार:** नेपाल और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $2 बिलियन का है, जिसमें $1.78 बिलियन का आयात चीन से होता है।

» **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI):** नेपाल 2017 में चीन की BRI योजना में शामिल हुआ, जिसमें $10 बिलियन की 35 परियोजनाएँ प्रस्तावित की गई थीं।

- हालांकि, नेपाल चीन के ऋण-आधारित निवेश मॉडल को लेकर सतर्क है, खासकर श्रीलंका के 2022 के ऋण संकट को देखते हुए।

निष्कर्ष:

नेपाल इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहाँ उसे राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना होगा। हालिया आर्थिक संकेतक धीमी लेकिन स्थिर सुधार का संकेत देते हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों और सार्वजनिक असंतोष के कारण शासन संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भारत और चीन के बीच देश की रणनीतिक स्थिति इसकी विदेश नीति को जटिल बनाती है, जिससे लाभकारी व्यापार संबंधों को बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक कूटनीति की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे नेपाल 2027 के चुनावों के करीब पहुंच रहा है, मौजूदा गठबंधन का स्थायित्व और प्रभावी आर्थिक नीतियों को लागू करने की इसकी क्षमता देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होगी।

श्रीलंका

भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय वार्ता

संदर्भ:

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा डिसानायके की हाल ही में 5 अप्रैल को कोलंबो स्थित राष्ट्रपति सचिवालय में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूती प्रदान करने वाले कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

ऐतिहासिक रक्षा समझौता और प्रमुख समझौते:

- दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत है। यह पहला ढांचा समझौता निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित है:
    - » संयुक्त सैन्य अभ्यासों को औपचारिक रूप देना, जिससे संचालन क्षमता में सुधार हो।
    - » श्रीलंकाई रक्षा कर्मियों के लिए भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार।
    - » सैन्य अधिकारियों के बीच उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
- यह समझौता भारत की शांति सेना (IPKF) की श्रीलंका में तैनाती के लगभग चार दशक बाद एक महत्वपूर्ण रणनीतिक परिवर्तन को दर्शाता है।

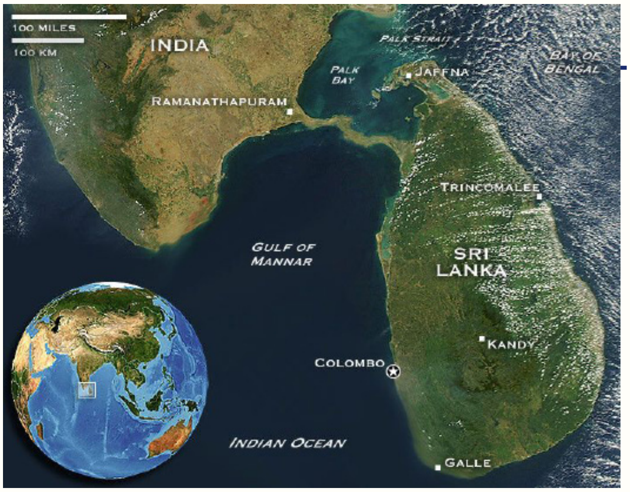

अन्य प्रमुख समझौते:

- **ऊर्जा और अवसंरचना:** संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें एक बहुउद्देश्यीय ऊर्जा पाइपलाइन भी शामिल है। संपूर सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया, साथ ही विद्युत ग्रिड संयोजन समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए जिससे श्रीलंका को विद्युत निर्यात की सुविधा मिलेगी।
- **डिजिटल परिवर्तन:** भारत की डिजिटल समाधान की सहायता से श्रीलंका के डिजिटल परिवर्तन को सुदृढ़ करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- **ऋण पुनर्गठन और आर्थिक सहायता:** भारत ने श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के आर्थिक विकास के लिए 2.4 अरब श्रीलंकाई रुपये की सहायता राशि की घोषणा की।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:** भारत ने 5,000 धार्मिक स्थलों – हिंदू, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम पूजा स्थलों – को सौर छत प्रणालियाँ उपलब्ध कराने हेतु 1.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की, जिससे 25 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा।
- **स्वास्थ्य और चिकित्सा:**
    - » भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और श्रीलंका के स्वास्थ्य एवं जनसंचार मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसका उद्देश्य चिकित्सा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।
    - » भारतीय औषधीय मानक आयोग और श्रीलंका की राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण के बीच एक समझौता हुआ, जिससे औषधीय मानकों और नियामकीय सहयोग को सुदृढ़ किया जाएगा।

श्रीलंका को भारत की विकास सहायता:

- प्रधानमंत्री मोदी ने एक समग्र क्षमता निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके अंतर्गत हर वर्ष 700 श्रीलंकाई नागरिकों को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारत ने सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिरों के पुनरुद्धार और विकास के लिए अनुदान सहायता देने का वादा किया, जिनमें शामिल हैं:
    - » त्रिंकोमाली का तिरुकोनेश्वरम मंदिर।
    - » नुवारा एलिया का सीता एलिया मंदिर।
    - » अनुराधापुरा में पवित्र नगरी परिसर।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस 2025 पर श्रीलंका में भगवान बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी भी आयोजित कराएगा।

अवसंरचना और ऊर्जा परियोजनाएं:

- » डांबुल्ला में 5000 मीट्रिक टन क्षमता का ताप-नियंत्रित गोदाम – कृषि भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सशक्त बनाना।
- » धार्मिक स्थलों के लिए 5000 सौर छत इकाइयाँ – सभी 25 जिलों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना।
- » 120 मेगावाट का संपूर सौर परियोजना – सतत ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, जिसे वर्चुअल भूमि पूजन समारोह के माध्यम से आरंभ किया गया।

▪ अन्य प्रमुख भारत समर्थित परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिनमें शामिल हैं:

- » महो-ओमानथाई रेलवे लाइन के उन्नत ट्रैक – रेलवे संपर्क और दक्षता में सुधार।
- » महो-अनुराधापुरा रेलवे लाइन के लिए सिग्नलिंग सिस्टम का निर्माण – संचालन की सुरक्षा हेतु रेलवे अवसंरचना का आधुनिकीकरण।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा ने दोनों देशों के मजबूत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों को एक बार फिर मजबूत किया। इस दौरान हुए समझौतों और शुरू की गई परियोजनाओं से यह स्पष्ट होता है कि भारत श्रीलंका के आर्थिक विकास, ऊर्जा स्थिरता और तकनीकी प्रगति में सक्रिय सहयोगी भूमिका निभा रहा है।

नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने सीमा पार बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को मजबूत करेगा और तीनों पड़ोसी देशों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा।

समझौते की मुख्य बातें:

- **बिजली निर्यात:** नेपाल अपनी अधिशेष जलविद्युत शक्ति भारत के माध्यम से बांग्लादेश को निर्यात करेगा। यह निर्यात प्रतिवर्ष 15 जून से 15 नवंबर तक किया जाएगा।
- **प्रारंभिक निर्यात मात्रा:** पहले चरण में, नेपाल बांग्लादेश को 40 मेगावाट जलविद्युत का निर्यात करेगा।
- **ट्रांसमिशन लाइन:** बिजली का निर्यात धालकेबर-मुजफ्फरपुर 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से होगा, जिसका मीटरिंग प्वाइंट भारत के मुजफ्फरपुर में स्थित है।
- **कीमत और आय:** बिजली की प्रति यूनिट कीमत 6.4 सेंट तय की गई है। इस समझौते से नेपाल को सालाना लगभग 9.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय होगी।
- **हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी:** समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) के कार्यकारी निदेशक कुलमान घीसिंग, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम के सीईओ डीनो नारन, और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान करीम ने काठमांडू में हस्ताक्षर किए।

समझौते का रणनीतिक महत्व:

- यह समझौता ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। नेपाल और भूटान जहां अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, वहीं भारत और बांग्लादेश ऊर्जा की कमी का सामना कर रहे हैं। यह त्रिपक्षीय समझौता नेपाल की अतिरिक्त जलविद्युत का उपयोग कर इन देशों की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है, जिससे क्षेत्रीय ऊर्जा संतुलन को बढ़ावा मिलता है।

क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग में भारत की भूमिका:

- भारत क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार के केंद्र के रूप में कार्य करता है और सीमा पार बिजली संचरण को सुविधाजनक बनाता है। भारत ने बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों में जलविद्युत संयंत्रों और ट्रांसमिशन लाइनों सहित ऊर्जा बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय निवेश किया है। भारत की ऊर्जा कूटनीति के तहत नेपाल के साथ एक दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौता भी शामिल है, जिसमें 2030 तक प्रति वर्ष 10,000 मेगावाट जलविद्युत की खरीद का लक्ष्य है।

सामरिक और भू-राजनीतिक महत्व:

- **ऊर्जा एकीकरण:** नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे पड़ोसी देशों की ऊर्जा प्रणालियों को जोड़ने के भारत के प्रयास क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देते हैं और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- **चीनी प्रभाव का मुकाबला:** इस समझौते को ऊर्जा अवसंरचना विकास और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाकर चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) का मुकाबला करने के रणनीतिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ऊर्जा निर्भरता को मजबूत करते हुए, भारत दक्षिण एशिया में अपनी भू-राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करता है

निष्कर्ष:

नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय बिजली व्यापार समझौता क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पढ़ाव है। अधिशेष बिजली के व्यापार को सुविधाजनक बनाकर, यह न केवल क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि आर्थिक एकीकरण और भू-राजनीतिक स्थिरता को भी बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार में भारत की प्रमुख भूमिका सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जोकि दक्षिण एशिया में दीर्घकालिक विकास और स्थिरता की नींव तैयार करती है।

कुक आइलैंड्स-चीन समझौता

सन्दर्भ:

हाल ही में कुक आइलैंड्स और चीन ने 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए कार्य योजना' पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कुक आइलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क ब्राउन और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते में व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, परिवहन और महासागर

विज्ञान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की बात की गयी है।

भू-राजनीतिक महत्वः

- कुक आइलैंड्स का चीन के साथ संबंध मजबूत करने का निर्णय ऐसे समय में आया है जब चीन प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ऐतिहासिक रूप से, यह क्षेत्र अब तक मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रभाव में रहा है।
- पैसिफिक में चीन की बढ़ती उपस्थिति को कूटनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और देशों के आपसी संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है।

आर्थिक और रणनीतिक महत्वः

- कुक आइलैंड्स की जनसंख्या लगभग 17,000 है, जो अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इसका भू-राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है। यह द्वीप समूह 13 अन्य प्रशांत द्वीप देशों के साथ मिलकर लगभग पृथ्वी की 15% समुद्री सतह पर जुरीसडिक्शन रखता है।
- **इस समझौते का प्रभावः**
  - » **चीन के रणनीतिक हितः** कुक आइलैंड्स अन्य देशों के साथ स्वतंत्र रूप से अंतरराष्ट्रीय समझौते कर सकता है, जिससे यह चीन के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक साझेदार हो सकता है।
  - » **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाः** यह समझौता उस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति को मजबूत करता है जो ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी शक्तियों के साथ संबद्ध रहा है।
  - » **आर्थिक लाभः** व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचे में बढ़ा हुआ सहयोग कुक द्वीप समूह की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है।

गहरे समुद्र में खनन और संसाधनों का दोहनः

- इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू समुद्र की गहराइयों में खनिजों की खोज और खनन (Deep-Sea Mining) से जुड़ा है। कुक आइलैंड्स में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के विशाल भंडार हैं, जिसमें निकल और कोबाल्ट जैसे मूल्यवान खनिज शामिल हैं, जो बैटरी उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों के लिए आवश्यक हैं।
- **चीन की खनिज रणनीतिः** चीन, जो वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी प्रसंस्करण में एक प्रमुख शक्ति है, सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण खनिजों के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहा है।
- **आर्थिक अवसर बनाम पर्यावरणीय खतरेः** गहरे समुद्र में खनन जहां आर्थिक अवसर प्रस्तुत करता है, वहीं यह पर्यावरणीय चिंताओं को भी बढ़ाता है, जो अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग करता है।
- **भविष्य की संभावनाएंः** इस क्षेत्र में कुक आइलैंड्स और चीन के बीच सहयोग खनिज निष्कर्षण में भविष्य के विकास को प्रभावित कर सकता है, जिसका प्रशांत क्षेत्र की संसाधन अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है।

समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरताः

- इस समझौते का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू समुद्री सुरक्षा और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (EEZs) का प्रबंधन है।
- **इसका प्रभाव**
  - » **महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर प्रभावः** यह समझौता प्रशांत क्षेत्र के समुद्री मार्गों के नियंत्रण को प्रभावित कर सकता है।
  - » **चीन की सुरक्षा नीतियांः** चीन पहले भी सोलोमन द्वीप समूह जैसे प्रशांत देशों के साथ सुरक्षा समझौते कर चुका है, जिससे दुनिया भर में क्षेत्रीय सैन्य पहुंच पर चर्चा हुई।
  - » **भविष्य की रणनीतियांः** हालाँकि समझौते में स्पष्ट रूप से सैन्य प्रावधान शामिल नहीं हैं, लेकिन भविष्य में सुरक्षा सहयोग के नाम पर विस्तार की संभावनाएँ बन सकती हैं।

निष्कर्षः

चीन के साथ कुक आइलैंड्स की रणनीतिक साझेदारी प्रशांत क्षेत्र के भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक विकास का प्रतिनिधित्व करती है। जहां यह व्यापार और संसाधन विकास में आर्थिक अवसर पैदा करता है, वहीं यह क्षेत्रीय शक्ति संबंधों, सुरक्षा सहयोग और पर्यावरणीय स्थिरता के संबंध में भी चर्चाएं बढ़ाता है। जैसे-जैसे चीन प्रशांत देशों के साथ जुड़ना जारी रखता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की प्रतिक्रियाएँ इस क्षेत्र के भविष्य के आर्थिक और रणनीतिक ढांचे को आकार देने में भूमिका निभाएंगी।

चीन और बांग्लादेश संबंध

संदर्भः

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार, मुहम्मद यूनुस, 26-29 मार्च 2025 के बीच आधिकारिक चीन दौरे पर रहे। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने बांग्लादेश की रणनीतिक स्थिति को दक्षिण एशिया के लिए समुद्र तक पहुंचने के एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने बांग्लादेश की क्षमता को एक प्रमुख समुद्री मार्ग और क्षेत्रीय आर्थिक कनेक्टिविटी के केंद्र के रूप में उजागर किया। उनकी यह टिप्पणी आगामी BIMSTEC

शिखर सम्मेलन से पहले आई है, जहां बांग्लादेश संगठन की अध्यक्षता संभालने जा रहा है।

मुहम्मद यूनुस की चीन यात्रा के प्रमुख बिंदु:

- **रणनीतिक साझेदारी:** मुहम्मद यूनुस ने चीन को बांग्लादेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि वह इसके रणनीतिक स्थान का लाभ उठाकर क्षेत्रीय और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बना सके।
- **आर्थिक सहयोग:** दोनों देशों ने नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो आर्थिक और तकनीकी सहयोग, बुनियादी ढांचे, मीडिया, संस्कृति और स्वास्थ्य से जुड़े हैं।
- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** चीन और बांग्लादेश ने एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत करने पर सहमति जताई, जिससे व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विवादास्पद संदर्भ:

- मुहम्मद यूनुस ने भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों (असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश) का उल्लेख किया, जिन्हें अक्सर "सात बहनें" कहा जाता है उन्होंने इन राज्यों को भूमिबद्ध (जमीन से घिरे हुए) क्षेत्र बताते हुए कहा कि उन्हें समुद्र तक सुगम पहुंच की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि बांग्लादेश, चीन और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग का माध्यम बन सकता है। इस वार्ता ने भारत में चिंता बढ़ा दी, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है।

भारत की चिंताएं:

- **भारत के पूर्वोत्तर की रणनीतिक संवेदनशीलता:**
  - पूर्वोत्तर राज्य भारत की सुरक्षा और संपर्क के लिए बेहद अहम हैं।
  - ये राज्य चीन से सटे हुए हैं, इसलिए चीन का कोई भी आर्थिक या बुनियादी ढांचा विकास भारत के लिए सुरक्षा चिंता का विषय बन सकता है।
- **दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव:**
  - भारत, चीन की दक्षिण एशिया में बढ़ती उपस्थिति, खासकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को लेकर सतर्क है।
  - भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश में चीन की बढ़ती भागीदारी सैन्य प्रभाव में बदल सकती है, जिससे भारत-चीन के सीमा विवाद और जटिल हो सकते हैं।
- **सिलीगुड़ी कॉरिडोर: एक कमजोर कड़ी**
  - सिलीगुड़ी कॉरिडोर (जिसे "चिकन नेक" भी कहा जाता है) जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एक संपर्क मार्ग है।
  - भारत को चिंता है कि बांग्लादेश में चीन की बढ़ती मौजूदगी इस मार्ग की सुरक्षा को कमजोर कर सकती है और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर असर डाल सकती है।
- **भारत की सीमाओं के पास चीन की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं**
  - चीन, भारत की सीमाओं (खासकर अरुणाचल प्रदेश में) के पास सड़कें, बांध और विकास की परियोजनाएं चला रहा है जिसे भारत अपना क्षेत्र मानता है।
  - ये परियोजनाएं चीन की उस क्षेत्र में पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं, जिससे भारत की सुरक्षा चिंताएं और बढ़ गई हैं।
  - अगर चीन बांग्लादेश (खासकर संवेदनशील सीमा क्षेत्रों के पास) में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाता है तो वह सैन्य और खुफिया गतिविधियों को भी बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष:

मुहम्मद यूनुस की चीन यात्रा दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह बांग्लादेश को चीनी निवेश के जरिए आर्थिक विकास के मौके तो देती है, लेकिन भारत के साथ उसके संबंधों को जटिल भी बना सकती है। खासतौर पर, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की रणनीतिक महत्व के लिए यह दौरा भारत के लिए चिंता का विषय है।

द्विपक्षीय बैठकें और समझौते

भारत-अमेरिका

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव (डिजी फ्रेमवर्क)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। इस पहल को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव (डिजी फ्रेमवर्क) नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य भारत में प्रमुख डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के संचालन को सुव्यवस्थित करना है, जिससे भारत में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा प्राप्त होगी।

डिजी फ्रेमवर्क के प्रमुख साझेदार:

- डिजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत तीन प्रमुख संगठनों का सहयोग शामिल है:
  - अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम (DFC)
  - जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (JBIC)
  - कोरिया का निर्यात-आयात बैंक (कोरिया एक्जिमबैंक)
- ये संस्थान भारत की डिजिटल अवसंरचना आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपने संसाधनों और विशेषज्ञता का योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रमुख फोकस क्षेत्र:

- इस ढांचे में विभिन्न डिजिटल तकनीकों और बुनियादी ढांचे में निवेश और विकास के कई प्राथमिक फोकस क्षेत्र तय किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - 5जी प्रौद्योगिकी
  - ओपन आरएएन (ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क)
  - पनडुब्बी केबल
  - ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क
  - दूरसंचार टावर
  - डेटा सेंटर
  - स्मार्ट शहर
  - ई-कॉमर्स
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)
  - क्वांटम प्रौद्योगिकी
- इन क्षेत्रों का विकास भारत के डिजिटल परिदृश्य को गति प्रदान करेगा और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करेगा।

डिजी फ्रेमवर्क में निजी क्षेत्र की भूमिका:

- डिजी फ्रेमवर्क का एक प्रमुख उद्देश्य भारत के निजी क्षेत्र के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करना है। इस ढांचे के तहत भारत की अवसंरचना आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रभावी नीति संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।
- यह दृष्टिकोण डिजिटल परियोजनाओं में निजी वित्तपोषण को बढ़ावा देगा, जिससे निजी क्षेत्र के हितधारकों की भागीदारी सुगम होगी।

रणनीतिक उद्देश्य:

- डिजी फ्रेमवर्क का उद्देश्य अमेरिका-जापान-कोरिया गणराज्य त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में स्थापित लक्ष्यों के अनुरूप तीनों देशों के बीच सहयोग और साझा प्राथमिकताओं को बढ़ाना है। इस पहल से भारत के डिजिटल परिदृश्य को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास में योगदान का लक्ष्य है।

भारत के प्रति प्रतिबद्धता:

- डिजी फ्रेमवर्क के तहत डीएफसी, जेबीआईसी और कोरिया एक्जिमबैंक की साझेदारी भारत की डिजिटल अवसंरचना के प्रति प्रतिबद्धता दिखाती हैं।
- इनका उद्देश्य निजी क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग कर भारत में डिजिटल अवसंरचना में उच्च गुणवत्ता वाले निवेश को बढ़ावा देना है, जिससे देश के विकास को समर्थन मिले।

डिजिटल अवसंरचना के बारे में:

- डिजिटल अवसंरचना से तात्पर्य उन प्रौद्योगिकियों से है, जो संगठन की सूचना प्रौद्योगिकी और परिचालन का आधार बनती हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत की डिजिटल अवसंरचना ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

महत्वपूर्ण पहल:

- **डिजिटल पहचान:** आधार एक 12-अंकीय बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी आधारित पहचान है, जिसमें 135.5 करोड़ से अधिक निवासियों का नामांकन है, जो एक अद्वितीय, आजीवन, ऑनलाइन और प्रामाणिक पहचान प्रदान करता है।
- **डिजिटल सेवाएं:** सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) 5.21 लाख केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा 400 से अधिक डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं।
- **डिजिटल लॉकर:** डिजिलॉकर के 13.7 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं, जिसमें 2,311 जारीकर्ता संगठनों के 562 करोड़ से अधिक दस्तावेज संग्रहीत हैं।

- **डिजिटल हस्ताक्षर:** ई-साइन सुविधा के माध्यम से 31.08 करोड़ से अधिक ऑनलाइन हस्ताक्षर किए गए हैं।
- **डिजिटल गांव:** डिजिटल गांव पायलट परियोजना 700 ग्राम पंचायतों/गांवों को कवर करती है, जोकि डिजिटल स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं और कौशल विकास प्रदान करती है।
- **ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं:** ई-डिस्ट्रिक्ट भारत के 709 जिलों में 4,671 ई-सेवाएं उपलब्ध कराता है।

भारत और अमेरिका संबंध: ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में अवसरों और जोखिमों का विश्लेषण

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के रूप में आने से भारत-अमेरिका संबंधों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण निहितार्थ प्रस्तुत हुए हैं। दोनों देशों के बीच राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग में समानताएँ उभर कर सामने आई हैं। तथापि ट्रंप प्रशासन का दृष्टिकोण व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक, लेन-देन आधारित संबंधों पर आधारित है, जिसमें आर्थिक राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद पर विशेष बल दिया गया है। इस दृष्टिकोण का भारत-अमेरिका के रक्षा, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद-विरोधी सहयोग पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान, इन साझा लक्ष्यों के माध्यम से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की दिशा और दोनों देशों की विदेश और आर्थिक नीतियाँ प्रभावित हो सकती हैं, जोकि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

भारत-अमेरिका संबंधों का महत्व:

- भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी दशकों से मजबूत हो रही है। दोनों देशों के समान लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा हितों के कारण उनके संबंध और गहरे हुए हैं। इन संबंधों का मुख्य केंद्र वैश्विक स्थिरता, आतंकवाद से लड़ाई और आर्थिक विकास है। भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और अमेरिका का वैश्विक नेतृत्व दोनों देशों को जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा खतरों और व्यापार असंतुलन जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने में एक मजबूत साझेदार बनाता है।

भारत-अमेरिका संबंधों का सामरिक आयाम:

- **साझा रणनीतिक हित:** भारत और अमेरिका के सामरिक हितों में समानताएँ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं, जिनमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
  - **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति का उद्देश्य अमेरिका की विदेशी सैन्य भागीदारी को कम करना था, जिससे भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा में अधिक प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर मिला। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियार सौदों और अमेरिकी सैन्य तकनीक तक पहुँच शामिल है।
  - **हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और आतंकवाद निरोध:** दोनों देश समान सुरक्षा खतरों का सामना कर रहे हैं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आतंकवाद निरोध, समुद्री सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने पर सहयोग बढ़ने की संभावना है।
  - **चीन पर नियंत्रण:** दोनों देश चीन के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन के सैन्य और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए गहन सहयोग के अवसर उत्पन्न होते हैं।
- **भू-राजनीतिक संतुलन:** ट्रंप की अप्रत्याशित विदेश नीति के कारण भारत को अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करना होगा, साथ ही चीन और रूस जैसी वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को भी संतुलित करना होगा। यह संतुलन भारत के रणनीतिक हितों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

ट्रम्प 2.0 नीतियों के आर्थिक आयाम:

व्यापार संबंध: अवसर और चुनौतियाँ: ट्रंप का 'अमेरिका फर्स्ट' दृष्टिकोण व्यापार असंतुलन को कम करने और अमेरिकी उद्योगों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों के प्रमुख पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **टैरिफ और व्यापार बाधाएँ:** ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाए गए थे, जिनमें स्टील, एल्युमीनियम और वस्त्र शामिल थे। यह नीति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भी जारी रह सकती है, जिससे भारतीय निर्यातकों को चुनौतियाँ आ सकती हैं। अमेरिका भारत से कृषि, बौद्धिक संपदा और सेवाओं में अधिक बाजार पहुंच की मांग कर सकता है।
- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** ट्रंप के पहले कार्यकाल में FTA वार्ताएँ रुकी हुई थीं, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में इन वार्ताओं के फिर से शुरू होने की संभावना है। हालांकि, भारत को अमेरिकी मांगों के साथ अपनी घरेलू प्राथमिकताओं को संतुलित करते हुए बाजार पहुंच और बौद्धिक संपदा सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
- **विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण:** अमेरिका में विनिर्माण को फिर से बढ़ावा देने के प्रयासों के चलते भारत के लिए कई नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। अमेरिकी कंपनियाँ चीन के विकल्प के रूप में भारत की श्रम शक्ति, कम उत्पादन लागत और बेहतर बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) का विस्तार इस प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जो इसे अमेरिकी कंपनियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना रहा है।
- **उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का प्रभाव:** भारत की पीएलआई योजना, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अमेरिकी निवेश आकर्षित

करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करती है। इन सुधारों से अमेरिकी कंपनियों को भारत में अपने परिचालन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जो अंततः रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

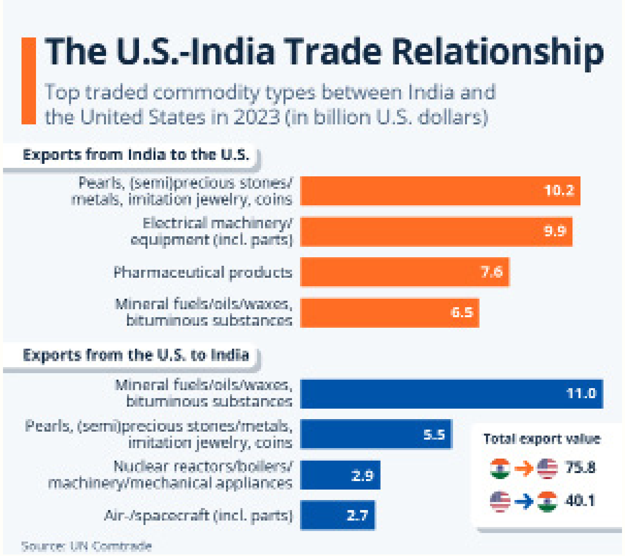

आव्रजन और कार्यबल चुनौतियां:

ट्रम्प की सख्त आव्रजन नीतियाँ भारत के आईटी क्षेत्र और ट्रम्प 2.0 के तहत अमेरिका में कार्यबल पर प्रभाव डाल सकती हैं:

- **एच-1बी वीजा प्रतिबंध:** भारतीय पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण एच-1बी वीजा कार्यक्रम को सख्त नियमों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कुशल भारतीय श्रमिकों के लिए अमेरिकी वर्क परमिट प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। इससे भारत के आईटी क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **निर्वासन और वैध प्रवासन:** अवैध आव्रजन पर ट्रम्प का सख्त रुख वैध भारतीय प्रवासियों को सीधे प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन इससे भारतीय प्रवासियों के लिए अनिश्चितता पैदा हो सकती है।

ऊर्जा और जलवायु नीति के निहितार्थ:

- **ऊर्जा आयात लाभ:** एक प्रमुख तेल आयातक के रूप में, भारत को ट्रम्प की नीतियों से लाभ हो सकता है, जोकि अमेरिकी जीवाश्म ईंधन उत्पादन के कारण वैश्विक तेल कीमतों को घटा सकती हैं। इससे भारत का आयात बिल कम हो सकता है और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार हो सकता है।
- **जलवायु परिवर्तन पहल के लिए चुनौतियाँ:** जलवायु परिवर्तन के बारे में ट्रम्प का संदेह और पेरिस समझौते से उनका हटना भारत के लिए चिंताजनक है, जोकि जलवायु प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। भारत सतत विकास लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है और ट्रम्प का रुख जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों को धीमा कर सकता है, जिससे भारत की जलवायु अनुकूलन रणनीतियों पर असर पड़ सकता है।

वैश्विक एवं क्षेत्रीय निहितार्थ

- **वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभाव**
  - **भारत के लिए अवसर:** अमेरिका-चीन के बीच चल रहे व्यापार तनाव के कारण अमेरिकी कंपनियाँ चीन से दूर आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की कोशिश कर सकती हैं। भारत, अपने बड़े उपभोक्ता बाजार और पीएलआई जैसी अनुकूल नीतियों के साथ, एशिया में विस्तार करने की इच्छुक अमेरिकी कंपनियों के लिए एक आकर्षक विकल्प के रूप में स्थित है।
  - **भारत के लिए चुनौतियाँ:** हालाँकि, वैश्विक व्यापार तनाव भारत के व्यापार संबंधों को बाधित कर सकता है, जिसके लिए अमेरिका, चीन और अन्य वैश्विक देशों के साथ अपनी साझेदारी को सावधानीपूर्वक संचालित करने की आवश्यकता होगी। व्यापार युद्ध का जोखिम भारत की आर्थिक वृद्धि और स्थिरता को जटिल बना सकता है।
- **भू-राजनीतिक विचार:** ट्रंप की विदेश नीति, जोकि अप्रत्याशित है, के कारण भारत को अमेरिका और रूस तथा चीन सहित अन्य शक्तियों के साथ अपने संबंधों को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना होगा। भारत के लिए चुनौती इन देशों के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना होगा।

भारत-अमेरिका TRUST पहल

सन्दर्भ:

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत-अमेरिका TRUST पहल की शुरुआत की गई। यह पहल विशेष रूप से फार्मास्युटिकल उत्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को सुरक्षित करने में सहायक होगी। भारत, जो चीन के बाद सक्रिय फार्मास्युटिकल संघटक (Active Pharmaceutical Ingredients - APIs) का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है, इस पहल से विशेष रूप से लाभान्वित हो सकता है।

भारत-अमेरिका TRUST पहल के बारे में:

- यह पहल भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका मुख्य फोकस लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्व (रेयर अर्थ एलिमेंट्स) और अन्य रणनीतिक संसाधनों पर है।
- यह पहल भारत की हाल ही में अमेरिका-नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क (एमएसएफएन) और खनिज सुरक्षा साझेदारी (एमएसपी) में सदस्यता के आधार पर आगे बढ़ी है।

पहल के प्रमुख उद्देश्य:

- महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना और किसी एक स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना।

- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना और निर्यात नियंत्रण से जुड़ी बाधाओं को दूर कर रणनीतिक उद्योगों में व्यापार और नवाचार को मजबूत करना।
- रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अर्धचालक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में व्यापार और सहयोग को मजबूत करना।
- फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए आवश्यक खनिजों, जैसे लिथियम और जिंक, की आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करना।
- नवाचार और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों, अनुसंधान संस्थानों और निजी उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।

खनिज सुरक्षा साझेदारी:

- यह एक वैश्विक पहल है, जिसे 2022 में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य खनिजों के निष्कर्षण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में निवेश को बढ़ावा देना है।
- **सदस्यता और वित्तीय सहायता:**
  - MSP में 14 देश और यूरोपीय आयोग शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से वैश्विक GDP का 50% से अधिक योगदान देते हैं।
  - प्रमुख वित्तीय संस्थानों में अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम (DFC), यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) और जापानी अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) शामिल हैं।
  - MSP की वित्तीय सहायता केवल सदस्य देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वैश्विक परियोजनाओं में निवेश कर विविध आपूर्ति श्रृंखलाएं (Diversified Supply Chains) बनाना है।
  - भारत 2023 में MSP का सदस्य बना और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने में योगदान दे रहा है।

महत्वपूर्ण खनिज और उनका महत्व:

- महत्वपूर्ण खनिज आधुनिक तकनीक का अभिन्न अंग हैं, लेकिन सीमित उत्पादन स्रोतों और भू-राजनीतिक कारकों के कारण इनकी आपूर्ति श्रृंखला अस्थिर बनी रहती है।
  - **उदाहरण:** लिथियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा और दुर्लभ पृथ्वी तत्व।
- **भारत में महत्वपूर्ण खनिज:** भारत ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है, जिनमें एंटिमनी, ग्रेफाइट, गैलियम और मोलिब्डेनम शामिल हैं। ये खनिज दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा उद्योगों के लिए आवश्यक हैं।
- **महत्व:**
  - **आर्थिक:** इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और दूरसंचार उद्योग के लिए अनिवार्य।
  - **पर्यावरणीय:** सौर पैनल, पवन टरबाइन और अर्धचालकों जैसी नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के लिए आवश्यक।
  - **सुरक्षा:** रक्षा क्षेत्र में विमानों और मिसाइल प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका।

संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय प्रवासियों का निर्वासन: निहितार्थों का विश्लेषण

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय प्रवासियों के बड़े पैमाने पर निर्वासन ने वैश्विक स्तर पर व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। विशेष रूप से, अमेरिकी सैन्य विमान के माध्यम से भारतीय नागरिकों का निष्कासन, अमेरिकी आव्रजन नीति में कठोर प्रवर्तन उपायों को रेखांकित करता है। यह घटना अमेरिका की प्रवासन नियंत्रण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाती है। निर्वासित प्रवासियों में से अधिकांश गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों से संबंधित हैं, जो ऐतिहासिक रूप से उच्च प्रवासन दर के लिए जाने जाते हैं। बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के बड़े पैमाने पर निष्कासन का भारत-अमेरिका राजनयिक संबंधों, सामाजिक-आर्थिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अवैध प्रवासन को बढ़ावा देने वाले कारकों, इसे नियंत्रित करने वाले कानूनी तंत्रों और निर्वासन के परिणामों की समझ, उन नीतियों को आकार देने में आवश्यक भूमिका निभाती है जो सीमा सुरक्षा और मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित कर सकें।

प्रवासन:

- प्रवासन का तात्पर्य आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या पर्यावरणीय कारणों से लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से है। इसे दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - वैध प्रवासी वे लोग होते हैं जो अधिकृत माध्यमों से वीजा, कार्य परमिट या स्थायी निवास प्राप्त करके किसी देश में स्थानांतरित होते हैं।
  - अवैध प्रवासी वे होते हैं जो बिना अनुमति के किसी देश में प्रवेश करते हैं या अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वहां रहते हैं। भारत के नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, अवैध प्रवासी वह विदेशी व्यक्ति है जो या तो बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करता है या अनुमत अवधि से अधिक समय तक वहां निवास करता है।

अमेरिका में भारतीय प्रवास का सांख्यिकीय अवलोकन:

- 20-24 नवंबर 2024 तक, अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) ने बताया कि 20,407 भारतीय नागरिक या तो हिरासत में थे या निष्कासन आदेशों का सामना कर रहे थे। इनमें से 17,940 के पास अंतिम निष्कासन आदेश थे, लेकिन वे हिरासत में नहीं थे, जबकि 2,467 प्रवर्तन और निष्कासन संचालन (ERO) के तहत हिरासत में थे। ICE

हिरासत में भारतीयों का स्थान चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीयता समूह है और एशियाई लोगों में सबसे ऊपर है।

- पिछले वर्ष, लगभग 1,100 भारतीय नागरिकों को विशेष चार्टर उड़ानों के माध्यम से निर्वासित किया गया था। नवंबर 2023 और अक्टूबर 2024 के बीच, 519 भारतीयों को भारत वापस भेजा गया। सबसे हालिया निर्वासन उड़ान, जिसे अमेरिकी सैन्य सी-17 विमान द्वारा संचालित किया गया था, सैन एंटोनियो, टेक्सास से रवाना हुई। निर्वासन की लागत काफी अधिक है; उदाहरण के लिए, ग्वाटेमाला के लिए एक सैन्य निर्वासन उड़ान की लागत प्रति प्रवासी लगभग $4,675 है।

प्रवासन के आकर्षित और मजबूर करने वाले कारक:

- कारकों के संयोजन के कारण प्रवास होता है, जिसमें पुश कारक व्यक्ति को स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं और पुल कारक उसे नए स्थान की ओर आकर्षित करते हैं।
- **भारत से पलायन को मजबूर करने वाले कारक:**
  - » उच्च बेरोजगारी दर और नौकरी के अवसरों की कमी के कारण आर्थिक संकट।
  - » राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और शासन-संबंधी असंतोष।
  - » सामाजिक भेदभाव, वंचित समुदायों द्वारा विदेशों में बेहतर संभावनाएं तलाशना।
  - » मानव तस्करी नेटवर्क, जहां अनधिकृत एजेंट झूठे वादों के साथ प्रवासियों को लुभाते हैं।
- **आकर्षण कारक (अमेरिका में प्रवासियों को आकर्षित करना):**
  - » उच्च वेतन और बेहतर आर्थिक अवसर।
  - » कैलिफोर्निया, टेक्सास और न्यू जर्सी जैसे राज्यों में भारतीय अप्रवासी समुदायों का सुदृढ़ नेटवर्क।
  - » गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सहित सामाजिक गतिशीलता की संभावनाएं।
  - » पारिवारिक पुनर्मिलन, जहां रिश्तेदार वीजा प्रायोजित करते हैं या अवैध प्रवास में सहायता करते हैं।
- **भारतीय प्रवासियों के समक्ष चुनौतियां, जो अवैध आव्रजन को बढ़ावा देती हैं:**
  - » कानूनी प्रवेश प्राप्त करने में बाधाओं के कारण कई भारतीय अवैध प्रवास का सहारा लेते हैं। उच्च लागत, लंबी प्रक्रिया अवधि और प्रतिबंधात्मक वीजा नीतियाँ व्यक्तियों को अनधिकृत मार्गों की ओर धकेलती हैं। भारत में रोजगार की चुनौतियाँ और वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए सामाजिक दबाव मिलकर व्यक्तियों को जोखिम भरी यात्राएँ करने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ लोग बेईमानी करने वाले एजेंटों पर भरोसा करते हैं जो अत्यधिक शुल्क लेते हैं, लेकिन अमेरिका में प्रवेश के असुरक्षित या भ्रामक तरीके प्रदान करते हैं।

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव:

- भारतीय नागरिकों के बड़े पैमाने पर निर्वासन के कूटनीतिक और आर्थिक निहितार्थ हैं। जबकि भारत ने सत्यापन के बाद निर्वासित प्रवासियों को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है किन्तु रसद का प्रबंधन अब भी एक चुनौती बनी हुई है। यह मुद्दा मानव तस्करी नेटवर्क और अवैध प्रवास चैनलों के बारे में भी चिंताएँ उत्पन्न करता है।
- आर्थिक दृष्टिकोण से, निर्वासन उन परिवारों को प्रभावित करता है जो धन प्रेषण पर निर्भर हैं, विशेषकर पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में। कई वापस लौटने वाले व्यक्तियों को वित्तीय अस्थिरता और कलंक के कारण भारतीय समाज में फिर से समायोजित होने में कठिनाइयाँ होती हैं।

कानूनी और मानवाधिकार संबंधी विचार:

- प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्वासन नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के अनुरूप होना चाहिए।
- वापसी का सिद्धांत व्यक्तियों को उन देशों में निर्वासित करने से रोकता है, जहां उन्हें उत्पीड़न का सामना हो सकता है।
- उचित प्रक्रिया और कानूनी उपाय उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रवासियों को निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी प्रतिनिधित्व मिल सके।
- सैन्य संसाधनों के उपयोग पर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सैन्य नेतृत्व वाले निर्वासन से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नैतिक और कानूनी समस्याएँ उठ सकती हैं।

अवैध प्रवासन के विरूद्ध पहल:

- भारत भी अवैध प्रवास की चुनौतियों का सामना कर रहा है, विशेषकर इसकी पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर। पूर्वोत्तर, विशेष रूप से असम, में बांग्लादेशी प्रवासियों की लंबी अवधि से लगातार आवागमन ने इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदल दिया है। हाल ही में, म्यांमार से उत्पीड़ित रोहिंग्याओं ने भारत में शरण मांगी है।
- उत्तर से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के कारण पलायन हो रहा है। ये आंदोलनों से

उत्पन्न सुरक्षा जोखिम, खासकर कश्मीर में, बढ़ गए हैं, जहां आतंकवादी नियंत्रण रेखा के माध्यम से घुसपैठ करने के लिए छिद्रपूर्ण सीमाओं का फायदा उठाते हैं।

- इन चुनौतियों से निपटने के लिए, भारत सरकार ने अवैध प्रवासन को रोकने के लिए विभिन्न उपाय लागू किए हैं।
- 'सुरक्षित जयेन, प्रशिक्षित जयेन' विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जो सुरक्षित और कानूनी प्रवासन मार्गों को बढ़ावा देता है।
- प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते, अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस भेजते हुए वैध प्रवासन सुनिश्चित करते हैं।
- सीमा प्रबंधन उपाय, जिनमें शामिल हैं:
  - » भौतिक अवसंरचना जैसे सीमा पर बाड़ लगाना और तेज रोशनी व्यवस्था।
  - » सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस)।
  - » अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ और असम राइफल्स जैसे सुरक्षा बलों द्वारा नियमित गश्त और सुरंग-रोधी अभियान चलाए जाते हैं।

वैश्विक पहल:

- प्रवासन को विनियमित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - » अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) के तहत सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौता, जो जिम्मेदार प्रवासन नीतियों को बढ़ावा देता है।
  - » भूमि, समुद्र और वायु मार्गों के माध्यम से प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनटीओसी) के तहत, जिसका उद्देश्य मानव तस्करी को रोकना है।
  - » अवैध प्रवास को सुविधाजनक बनाने वाले आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने में इंटरपोल का समर्थन।

डंकी रूट्स: अनधिकृत प्रवास मार्ग

- "डुंकी रूट" का मतलब है भारतीय प्रवासियों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले अनधिकृत प्रवासन मार्ग। शुरू में यह मार्ग पंजाब और हरियाणा से जुड़े थे, लेकिन अब ये गुजरात तक फैल गए हैं। प्रवासी आमतौर पर लैटिन अमेरिका के रास्ते अमेरिका में प्रवेश करते हैं और खतरनाक मार्गों से गुजरने के लिए मानव तस्करों पर निर्भर रहते हैं।
- **प्रवास यात्रा के चरण:**
  - » **लैटिन अमेरिका में प्रवेश:** प्रवासी पहले उदार वीजा नीतियों के कारण इक्वाडोर, बोलीविया या गुयाना के लिए उड़ान भरते हैं। अन्य दुबई के माध्यम से वीजा प्राप्त करने के बाद मैक्सिको के माध्यम से यात्रा करते हैं।
  - » **डेरियन गैप को पार करना:** कोलंबिया और पनामा के बीच का यह घना जंगल सबसे खतरनाक प्रवास मार्गों में से एक है। प्रवासियों को खराब मौसम, जंगली जानवरों और डकैती, अपहरण और हिंसा में लिप्त आपराधिक गिरोहों का सामना करना पड़ता है
  - » **मध्य अमेरिका की यात्रा:** प्रवासी कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास और ग्वाटेमाला से यात्रा करते समय अधिकारियों को रिश्वत देते हैं।
  - » **अमेरिका में प्रवेश:** अंतिम बाधा रियो ग्रांडे के माध्यम से अमेरिका में प्रवेश करना या सीमा बाड़ को पार करना है, जिसमें अक्सर गिरफ्तारी का खतरा रहता है।

तस्करों द्वारा उच्च लागत और शोषण:

- डंकी मार्गों के माध्यम से अनधिकृत प्रवास की लागत बहुत अधिक है। तस्कर प्रति प्रवासी 30-40 लाख से लेकर 1 करोड़ तक वसूलते हैं। कई प्रवासी अपनी यात्रा के लिए कर्ज लेते हैं या संपत्ति बेचते हैं, जिससे वे और अधिक शोषण का शिकार हो जाते हैं। तस्करी के नेटवर्क एन्क्रिप्टेड संचार चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं, जो निराश व्यक्तियों को झूठे वादों के साथ लुभाते हैं।

ट्रम्प 2.0 के तहत भारत-अमेरिका संबंध

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कर चुके हैं, ऐसे में 'सामान्य ज्ञान की क्रांति' (Revolution Of Common Sense) की उनकी साहसिक दृष्टि अमेरिका की घरेलू और विदेश नीतियों को नया आकार देने का वादा करती है। 'उदारवादी उग्रवाद' (Liberal Extremism) का मुकाबला करने और अमेरिकी संप्रभुता को मजबूत करने के उद्देश्य से इस परिवर्तनकारी एजेंडे का भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी सहित वैश्विक संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। भारत, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सहयोगी और एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार के रूप में, ट्रंप की नीतियों से उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों को सावधानीपूर्वक समझना चाहिए।

भारत-अमेरिका संबंधों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

- भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय बदलाव आए हैं। दोनों देशों ने ऐतिहासिक मतभेदों को पार करते हुए, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और रणनीतिक हितों के आधार पर एक मजबूत साझेदारी स्थापित की है।
  - » **अटल बिहारी वाजपेयी:** भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत और अमेरिका को 'स्वाभाविक सहयोगी' घोषित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान और साझा भू-राजनीतिक लक्ष्यों

पर जोर दिया।

- » **बराक ओबामा:** अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत-अमेरिका संबंधों को '21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता' बताया और इसके वैश्विक महत्व पर प्रकाश डाला।
- » **नरेंद्र मोदी:** भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दोनों देशों के संबंधों में और अधिक मजबूती आई है। 2016 में, उन्होंने ऐतिहासिक हिचकिचाहट से गतिशील और स्थायी गठबंधन में परिवर्तन का जश्न मनाया।

- ये उपलब्धियां दोनों देशों के बीच लगातार मजबूत होते संबंधों को दर्शाती हैं। व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और वैश्विक शासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देश सहयोग कर रहे हैं।

भारत-अमेरिका संबंध: ट्रम्प के पहले कार्यकाल में मजबूत नींव

ट्रम्प के पहले कार्यकाल (2017-2021) के दौरान, भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण पहलों के माध्यम से अपने संबंधों को गहरा किया:

- **भू-राजनीतिक सहयोग:**
  - » क्वाड पहल को पुनर्जीवित किया तथा स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर जोर दिया।
  - » अमेरिकी प्रशांत कमान का नाम बदलकर अमेरिकी हिंद-प्रशांत कमान कर दिया गया, जो भारत की रणनीतिक भूमिका को दर्शाता है।
- **व्यक्तिगत कूटनीति:** ट्रम्प और मोदी के बीच घनिष्ठ संबंध, जो 'हाउडी मोदी' और 'नमस्ते ट्रम्प' जैसे आयोजनों से उजागर हुआ, ने आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया।
- **रक्षा एवं सुरक्षा :**
  - » भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में नामित किया गया, जिससे रक्षा सहयोग और हथियार व्यापार को बढ़ावा मिला।
  - » आतंकवाद-रोधी सहयोग और खुफिया-साझाकरण तंत्र को मजबूत किया गया।

आर्थिक और व्यापार सहयोग: साझेदारी का एक स्तंभ

आर्थिक संबंध भारत-अमेरिका संबंधों की आधारशिला बने हुए हैं:

- **व्यापार:** अमेरिका वस्तुओं और सेवाओं के लिए भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जो मजबूत आर्थिक अंतरनिर्भरता को बढ़ावा देता है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई):** भारत में अमेरिकी एफडीआई 2022 में कुल 51.6 बिलियन डॉलर रहा, जो भारत की विकास क्षमता में निवेशकों के विश्वास का संकेत है।
- **तकनीकी उन्नति:**
  - » भारत को सामरिक व्यापार प्राधिकरण टियर-1 का दर्जा दिए जाने से महत्वपूर्ण अमेरिकी प्रौद्योगिकियों तक लाइसेंस-मुक्त पहुंच की अनुमति मिल गई।
  - » स्वच्छ ऊर्जा, ब्लॉकचेन, साइबर विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ती तकनीकी साझेदारी को दर्शाता है।

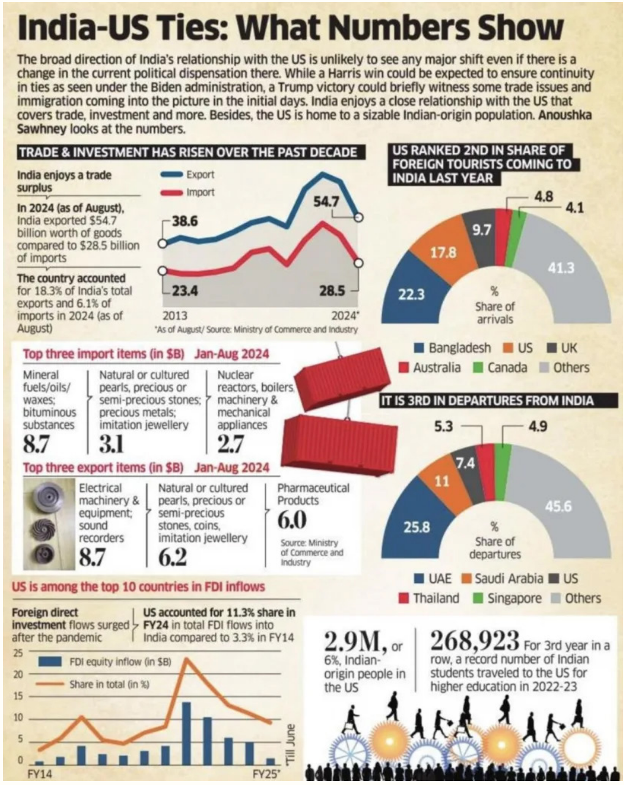

ट्रम्प 2.0: परिवर्तन के लिए एक दृष्टिकोण

दूसरे कार्यकाल के लिए अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक महत्वाकांक्षी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो वैश्विक संबंधों को प्रभावित करने वाले बदलावों का संकेत देता है:

- **आर्थिक पुनरुद्धार:** इसमें मुद्रास्फीति को कम करने, ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और घरेलू विनिर्माण का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - » अमेरिकी उद्योगों को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ, अमेरिका ने दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर टैक्स बढ़ाएगा ताकि अपने देश के सामानों को बढ़ावा मिले।
- **विदेश नीति में पुनःसंरेखण:** इसमें 'अमेरिका प्रथम' पर जोर दिया गया, विदेशी संघर्षों की तुलना में सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई।
  - » गठबंधनों के लिए लेन-देन संबंधी दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें आर्थिक और रणनीतिक लाभ पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन:** पारंपरिक अमेरिकी

मूल्यों को बहाल करने के उद्देश्य से मुक्त भाषण, पहचान की राजनीति और पर्यावरणीय जनादेश पर उदार नीतियों को उलटने का संकल्प लिया गया।

ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में भारत–अमेरिका संबंध: अवसर और चुनौतियां

ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के साथ भारत के संबंध संभावित लाभ और बाधाओं के साथ विकसित होने के लिए तैयार हैं:

अवसर

- **सामरिक सहयोग:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर निरंतर ध्यान देना भारत के सामरिक हितों के अनुरूप है, विशेष रूप से चीन के प्रभाव का मुकाबला करने में। क्वाड पहल के गति पकड़ने की संभावना है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग बढ़ेगा।
- **प्रौद्योगिकीय नवाचार:** स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत विनिर्माण जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में संयुक्त उद्यम भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण और स्वास्थ्य सुरक्षा में सहयोग से द्विपक्षीय संबंधों के नए रास्ते खुलेंगे।
- **आर्थिक लाभ:** ट्रम्प की संरक्षणवादी नीतियां चुनौतियां पेश करती हैं, भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के बदलाव से लाभान्वित हो सकता है, विशेष रूप से तब जब कंपनियां चीन से दूर विविधीकरण की तलाश कर रही हैं।

चुनौतियां:

- **व्यापार और टैरिफ नीतियां:** घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयात पर कर लगाने पर ट्रम्प का जोर, अमेरिका को भारत के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ट्रम्प की व्यापार नीतियों की लेन-देन संबंधी प्रकृति प्रतिकूल शर्तों से बचने के लिए सावधानीपूर्वक बातचीत की मांग करती है।
- **आव्रजन नीतियां:** प्रतिबंधात्मक वीजा व्यवस्था, विशेष रूप से एच-1बी धारकों के लिए, भारत के आईटी क्षेत्र और अमेरिका में काम करने वाले कुशल पेशेवरों को प्रभावित कर सकती है।
- **सामरिक स्वायत्तता:** भारत को विदेश नीति में स्वतंत्रता बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ अपनी बढ़ती साझेदारी को संतुलित करना होगा, विशेष रूप से रूस और अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ अपने संबंधों के संबंध में।
- **बाजार अनिश्चितता:** ट्रम्प की आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय बाजार सतर्क बने हुए हैं, क्योंकि इसका रुपया-डॉलर विनिमय दर और निवेश प्रवाह पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है।

परिवर्तनकारी विदेश नीति दृष्टिकोण:

ट्रम्प की दूसरे कार्यकाल की विदेश नीति एक मुखर और लेन-देन संबंधी रुख को दर्शाती है:

- **रणनीतिक हितों पर ध्यान केंद्रित करना:**
    - » दूरवर्ती संघर्षों की तुलना में अमेरिकी सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की रक्षा को प्राथमिकता देना।
    - » बहुपक्षवाद और उदार अंतर्राष्ट्रीयतावाद के स्थान पर निष्पक्ष व्यापार और पारस्परिकता पर जोर दिया जाना चाहिए।
- **वैश्विक निहितार्थ:**
    - » हिंद-प्रशांत, यूरेशिया और मैक्सिको की खाड़ी (जिसे अब 'अमेरिका की खाड़ी' नाम दिया गया है) पर ट्रम्प की नीतियां शक्ति गतिशीलता को पुन: परिभाषित कर सकती हैं।
    - » उनका 'शांति निर्माता' बनने पर जोर देना, विस्तारित संघर्षों में शामिल होने की अनिच्छा को दर्शाता है, जो भारत की रणनीतिक गणनाओं को प्रभावित कर सकता है।

भारत-अमेरिका सोनोबॉय सह-निर्माण साझेदारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने गहरे समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए अंडरसी डोमेन जागरूकता (UDA) के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक सोनोबॉय के सह-निर्माण के लिए एक ऐतिहासिक साझेदारी शुरू की है। यह कदम हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है।

सोनोबॉय के बारे में :

- सोनोबॉय ऐसे उपकरण हैं जोकि ध्वनिक संकेतों के माध्यम से पनडुब्बियों का पता लगाते हैं। वे अंडरसी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें निष्क्रिय करना संभव हो पाता है। इन उपकरणों को समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों या यूएवी जैसे विमानों से तैनात किया जाता है, जोकि नौसैनिक रक्षा कार्यों के लिए महत्वपूर्ण व्यापक क्षेत्र खोज का संचालन करते हैं।

शामिल हितधारक:

- सह-निर्माण पहल में अल्ट्रा मैरीटाइम (अंडरसी युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी अमेरिकी कंपनी) और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (एक राज्य-स्वामित्व वाली भारतीय रक्षा कंपनी) शामिल है। अल्ट्रा मैरीटाइम सोनोबॉय डिजाइन और उत्पादन में विशेषज्ञता प्रदान करेगा, जबकि बीडीएल भारत के भीतर विनिर्माण और वितरण को संभालेगा।

क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर पहल:

DHYEYA IAS most trusted since 2003 PERFECT 7

- यह सहयोग जनवरी 2023 में शुरू की गई अमेरिका-भारत क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (iCET) पहल के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल उन्नत प्रौद्योगिकियों में, विशेष रूप से अंडरसी डोमेन जागरूकता जैसे रक्षा क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

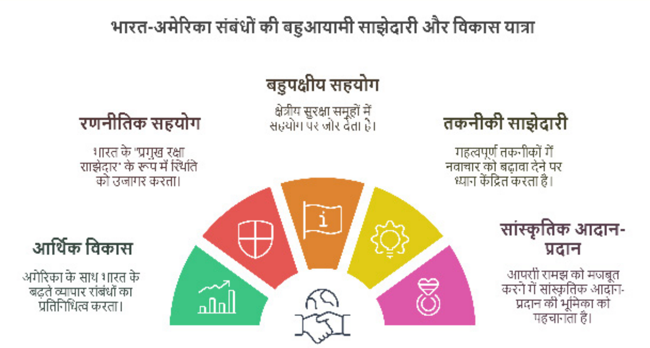

भारत के लिए महत्वः

- यह साझेदारी भारत की नौसेना क्षमताओं को मजबूत करती है, जिससे भारतीय नौसेना को तेजी से चुनौतीपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी निगरानी और पता लगाने की क्षमताओं को बढ़ाने की क्षमता मिलती है।
- भारत में उत्पादित सोनोबॉय भी अमेरिकी नौसेना प्लेटफार्मों और ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित सहयोगी बलों के प्लेटफार्मों के साथ इंटरऑपरेबल होंगे।
- यह इंटरऑपरेबिलिटी एक मजबूत रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देती है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करती है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

भारत-अमेरिका रक्षा संबंधः एक मजबूत आधार

भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक रक्षा संबंधों ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण विकास किया है:

- **2005:** भारत और अमेरिका ने रणनीतिक संवाद शुरू किए, जोकि गहन सबंधो की शुरुआत का प्रतीक है।
- **2016:** भारत को 'प्रमुख रक्षा साझेदार' नामित किया गया, जिससे उन्नत तकनीक तक पहुंच प्रदान की गई।
- **2018:** भारत को रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण स्तर 1 (एसटीए-1) का दर्जा प्राप्त हुआ, जिससे अमेरिकी सैन्य तकनीक तक आसान पहुंच की सुविधा मिली।
- **2018:** 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता की स्थापना ने रणनीतिक सहयोग को और मजबूत किया।
- **2019:** पहला त्रि-सेवा अभ्यास, 'टाइगर ट्राइंफ' हुआ, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भारत के रक्षा उत्पादन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध (आईएसए) पर हस्ताक्षर किए गए।
- **2021-2022:** भारत और अमेरिका ने प्रमुख रक्षा सौदों पर प्रगति की, जिसमें एमक्यू-9बी ड्रोन और एफ-414 फाइटर जेट इंजन का अधिग्रहण शामिल है।
- **2023:** भारत-अमेरिका रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र (आईएनडीयूएस-एक्स) को रक्षा कंपनियों, निवेशकों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था।

भारत-रूस

भारत का रूस और पश्चिम के बीच रणनीतिक संतुलनः एक व्यापक विश्लेषण

भारत की विदेश नीति रूस के साथ उसके लंबे समय से चले आ रहे संबंधों और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गहरी होती रणनीतिक साझेदारी के बीच एक जटिल संतुलन कार्य को दर्शाती है। यह सूक्ष्म दृष्टिकोण रणनीतिक स्वायत्तता के लिए भारत की आकांक्षा और वैश्विक भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में इसकी बढ़ती भूमिका को उजागर करता है। मॉस्को में सैन्य और सैन्य सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-एमएंडएमटीसी) के 21वें सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया टिप्पणियों ने बढ़ते पश्चिमी दबावों के बावजूद, रूस के साथ संबंधों को गहरा करने की नई दिल्ली की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

भारत–रूस संबंध का महत्वः

सहयोग के प्रमुख क्षेत्रः

- रूस आज भी भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार है, जो उच्च तकनीकी आपूर्ति करता है, जिनमें ड्यूल-यूज तकनीक शामिल है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाती है।
- पश्चिमी देशों, जैसे फ्रांस और अमेरिका, की ओर से अधिक खुलापन होने के बावजूद, रूस अब भी भारत की लंबी दूरी और समुद्र के नीचे की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है।

सह-विकास और रणनीतिक हितः

- ब्रह्मोस मिसाइल जैसे संयुक्त रक्षा परियोजनाएं, भारत और रूस के मजबूत रिश्तों का प्रतीक हैं।
- भारत, रूस की प्रौद्योगिकियों को फिलीपींस जैसे देशों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सके और दुनिया में 'नियम-आधारित व्यवस्था' बनी रह सके।

व्यापक निहितार्थः

भारत और रूस का यह रिश्ता सिर्फ दो देशों के बीच सहयोग नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- **वैश्विक बहुपक्षीयता के लिए सेतुः** भारत की बहुपक्षीयता के प्रति प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि रूस, पश्चिमी देशों के साथ अपनी तकरार के बावजूद, वैश्विक प्रणाली में बना रहे। भारत उन विभिन्न भू-राजनीतिक प्रणालियों के बीच पुल का काम करता है, जो अक्सर एक-दूसरे से अलग होती हैं।
- **रूस-चीन संबंधों को संतुलित करनाः** भारत और रूस की साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि रूस, चीन के साथ पूरी तरह से जुड़कर एक रूस-चीन गठजोड़ बनाने से बच सके, जो वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। भारत रूस को एक समान साझेदार के रूप में पेश करता है, जबकि चीन उसे एक अधीनस्थ साझेदार के रूप में देखता है। इससे यह रिश्ते भू-राजनीतिक संतुलन बनाए रखते हैं और वैश्विक व्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करते हैं।

भारत–रूस संबंध के परिणामः

- **रूस को वैश्विक बहुपक्षीयता से जोड़नाः** भारत का बहुपक्षीयता के प्रति मजबूत रुख यह सुनिश्चित करता है कि रूस वैश्विक प्रणाली से अलग न हो। इस प्रकार, भारत पृथक पड़े भू-राजनीतिक खिलाड़ियों को जोड़कर एक सहयोगी मंच प्रदान करता है, जिससे वैश्विक एकता बढ़ती है।
- **रूस-चीन संबंधों का संतुलन बनानाः** भारत और रूस का रिश्ता रूस को समान साझेदार की स्थिति प्रदान करता है, जिससे चीन की प्रमुखता को चुनौती मिलती है। भारत का यह संतुलन रूस और चीन के बीच पूर्ण साझेदारी को रोकता है, जिससे वैश्विक व्यवस्था स्थिर रहती है और पश्चिमी देशों को चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता। रूस की यह प्राथमिकता है कि वह चीन के अधीन न हो, और यह बात BRICS जैसे मंचों पर स्पष्ट रूप से देखी जाती है, जहां रूस भारत के संतुलित रुख को सराहता है।
- **ऊर्जा व्यापार और वैश्विक मूल्य स्थिरताः** भारत द्वारा रूस से जीवाश्म ईंधन की खरीद वैश्विक ऊर्जा कीमतों को स्थिर करने में मदद करती है और यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के अनुरूप होती है। यह ऊर्जा व्यापार वैश्विक मूल्य स्थिरता में योगदान करता है, जिससे यूरोप और पश्चिमी देशों को राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से बचने में मदद मिलती

है।

- **आर्कटिक क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति:** भारत और रूस का आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग चीन द्वारा नियंत्रित शासन व्यवस्था के लिए एक वैकल्पिक रास्ता प्रदान करता है। चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और शासन को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाते हैं। भारत की बढ़ती उपस्थिति आर्कटिक क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए पारिस्थितिकीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- **बहुपक्षीय समूहों का संतुलन बनाना:** भारत का BRICS और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे बहुपक्षीय समूहों में नेतृत्व यह सुनिश्चित करता है कि ये मंच पश्चिमी देशों के खिलाफ न बने। जैसा कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, 'भारत गैर-पश्चिमी है, लेकिन पश्चिम के खिलाफ नहीं है,' यह नीति एक संतुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। BRICS में UAE, मिस्र और वियतनाम जैसे मध्यम देशों का शामिल होना भारत की स्थिर करने वाली भूमिका को और मजबूत करता है।

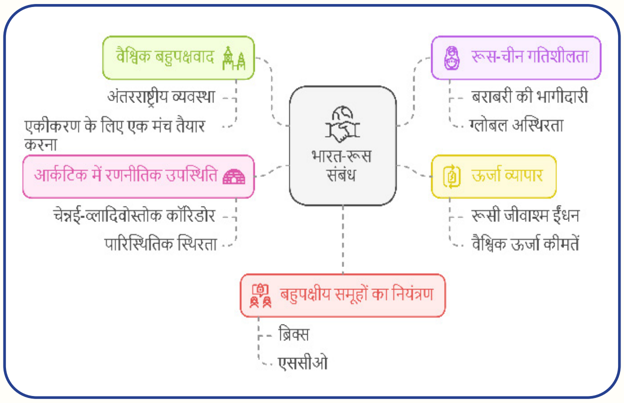

रूस से रक्षा आयात में गिरावट:

- दशकों तक रूस भारत का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता रहा है, क्योंकि यह लागत के मामले में फायदेमंद, विश्वसनीय और शीत युद्ध के दौरान भू-राजनीतिक रूप से उपयुक्त था।
- हाल के वर्षों में भारत ने रूस से रक्षा आयात पर अपनी निर्भरता को घटाया है:
  - » **2009-2013:** रूस ने भारत के 76% हथियार आयात की आपूर्ति की।
  - » **2014-2018:** यह घटकर 58% हो गया।
  - » **2019-2023:** यह और घटकर 34% हो गया।

गिरावट के कारण:

- **रूस की रक्षा उद्योग की चुनौतियाँ:** आर्थिक प्रतिबंधों और घरेलू समस्याओं ने रूस के वैश्विक रक्षा निर्यात बाजार को काफी कमजोर किया है। 2014-2018 और 2019-2023 के बीच रूस के निर्यात में 53% की गिरावट आई है।
- **भारत का आत्मनिर्भरता अभियान:** भारत ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अपनी रक्षा निर्माण क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत का उद्देश्य घरेलू रक्षा उपकरणों का उत्पादन बढ़ाना, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करना और अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना है।

रूस के साथ ऊर्जा साझेदारी:

- **युद्ध से पहले की स्थिति:** 2021 से पहले, रूस भारत के ऊर्जा आयातों में एक नगण्य साझेदार में था, क्योंकि रूस केवल भारत के कुल कच्चे तेल आयात का 2% ही प्रदान करता था।
- **युद्ध के बाद तेल आयात में वृद्धि:** इसके बाद 2023 तक रूस से भारत का कच्चे तेल आयात अचानक बढ़कर लगभग 40% तक पहुंच गया। इसके कारण थे:
  - » **भारी छूट:** रूस ने अपने तेल की कीमतों में 9-14% तक की छूट दी, जो भारत की किफायती ऊर्जा रणनीति के लिए आकर्षक था।
  - » **भू-राजनीतिक व्यावहारिकता:** पश्चिमी देशों की असहमति के बावजूद, भारत ने आर्थिक सुरक्षा को भू-राजनीतिक दबावों पर प्राथमिकता दी।

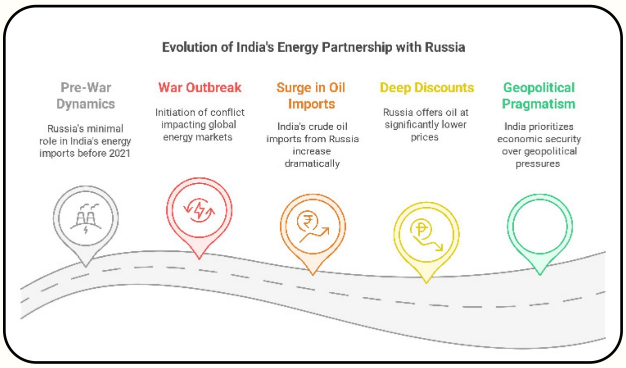

ऊर्जा रणनीति में हाल की बदलाव:

- **पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं की ओर वापसी:** जैसे-जैसे रूस की छूट कम हुई और परिवहन लागत बढ़ी, भारत ने अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति को फिर से खाड़ी देशों से विविधित किया।
- **अमेरिकी तेल आयात में वृद्धि:** 2024 तक, अमेरिका ने भारत के कच्चे तेल बाजार में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी कर दी। अगस्त 2024 में भारत ने एक अरब डॉलर से अधिक का

अमेरिकी तेल आयात किया।

पश्चिमी दबावों का सामना

अमेरिकी चिंताएँ और कार्रवाई: संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के साथ भारत के निकट संबंधों को लेकर खासकर रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में चिंताएँ जताई हैं:

- **रक्षा और ऊर्जा प्रतिबंध**
  - » CAATSA के तहत भारत के रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर प्रतिबंध लगाए गए।
  - » 19 भारतीय कंपनियों पर रूस के सैन्य आपूर्ति श्रृंखला में कथित रूप से शामिल होने के कारण प्रतिबंध लगाए गए।
- **तेल व्यापार की आलोचना:**
  - » अमेरिकी अधिकारियों ने भारत द्वारा रूस से भारी मात्रा में छूट पर तेल खरीदने की आलोचना की और 'परिणामों' की धमकी दी, हालांकि उन्होंने तेल आयात पर कोई कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए।

भारत का संप्रभु रुख:

- भारत ने लगातार अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और विदेश और ऊर्जा नीतियों को स्वतंत्र रूप से तय करने के अधिकार को कायम रखा है:
  - » **आर्थिक व्यावहारिकता:** भारत अपने बढ़ते घरेलू ऊर्जा मांगों और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सस्ते ऊर्जा आयात को प्राथमिकता देता है।
  - » **संप्रभु निर्णय:** भारत अपनी संप्रभुता पर जोर देता है और रूस से संबंध तोड़ने के दबाव का विरोध करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत संबंधों को मजबूत करना

भारत-रूस संबंधों की जटिलताओं को सही ढंग से संभालने के लिए, अमेरिका को एक संतुलित नीति अपनानी होगी:

- **संप्रभुता का सम्मान:** भारत पर रूस के साथ संबंध तोड़ने का दबाव डालने से अमेरिका-भारत संबंधों को नुकसान हो सकता है और दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग में कमी आ सकती है।
- **मध्यस्थता को बढ़ावा देना:** भारत का यूक्रेन संकट में मध्यस्थता करने का संभावित भूमिका अमेरिका और भारत के बीच सकारात्मक संवाद का अवसर प्रस्तुत करता है, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
- **सामान्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना:** अमेरिका और भारत दोनों के पास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने, और आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने में साझा हित हैं। इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना उनकी साझेदारी को मजबूत कर सकता है।

निष्कर्ष:

- भारत की विदेश नीति रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करने की एक सुनियोजित कोशिश को दर्शाती है। रूस से रक्षा आयात में गिरावट, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना यह दर्शाता है कि भारत एक आत्मनिर्भर और व्यावहारिक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में विकसित हो रहा है। दीर्घकालिक स्थिरता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अमेरिका भारत की अद्वितीय भू-राजनीतिक स्थिति का सम्मान करें और एक ऐसा संबंध स्थापित करे जो साझा रणनीतिक लक्ष्यों को मजबूत करे।
- यह रणनीतिक संतुलन वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और 2025 और उसके बाद भारत-रूस संबंधों की भविष्यवाणी वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नया पूर्वी मार्ग

चर्चा में क्यों?

चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग, जिसे पूर्वी समुद्री गलियारा भी कहा जाता है, ने भारत-रूस व्यापार संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, विशेष रूप से कच्चे तेल के व्यापार में। इस समुद्री गलियारे ने दोनों देशों के बीच की दूरी को संक्षिप्त करते हुए शिपिंग समय और लागत को काफी कम कर दिया है, जिससे भारत जुलाई 2024 में रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है।

चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा (VCMC) के बारे में:

- चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा (VCMC) एक समुद्री मार्ग है जो चेन्नई (भारत) को व्लादिवोस्तोक (रूस) से जोड़ता है और यह पूर्वी समुद्री गलियारे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।

मुख्य विवरण:

- **पृष्ठभूमि:** यह मार्ग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2019 में रूस यात्रा के दौरान औपचारिक रूप से शुरू किया गया था और जिसका उद्देश्य भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ाना है,

खासकर ऊर्जा, खनिजों और रक्षा क्षेत्रों में।

- **मार्ग:** यह मार्ग 5,600 समुद्री मील लंबा है और इसमें जापान सागर, दक्षिण चीन सागर, मलक्का जलडमरूमध्य, बंगाल की खाड़ी और अंडमान द्वीप समूह जैसी जगहों से गुजरता है।
- **बंदरगाह स्थान:** व्लादिवोस्तोक रूस का सबसे बड़ा प्रशांत बंदरगाह है, जो चीन-रूस सीमा के पास स्थित है। चेन्नई भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है।

लाभ:

- **परिवहन समय में कमी:** शिपिंग का समय 40+ दिनों से घटकर सिर्फ 16 दिन हो गया है।
- **लागत-कुशलता:** परिवहन लागत में कमी होने से यह व्यापारियों के लिए आकर्षक विकल्प बन गया है।
- **रणनीतिक महत्व:** यह भारत और रूस के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में।

भौगोलिक प्रभाव:

- यह मार्ग क्षेत्रीय गतिशीलता को बदल सकता है, जिससे भारत को प्रशांत क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव मिलेगा, जबकि चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित किया जा सकता है। हालांकि, इसका मार्ग दक्षिण चीन सागर से होकर जाता है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक लाभ:

- **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपभोक्ता है, अपनी ऊर्जा जरूरतों का 85% से ज्यादा आयात करता है। रूस से सस्ता तेल प्राप्त करना भारत की ऊर्जा रणनीति को सुदृढ़ करता है, खासकर वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि के बीच।
- **भौगोलिक लाभ:** भारत के बढ़ते संबंध रूस के साथ चीन के साथ रूस के बढ़ते संबंधों का संतुलन बनाने में मदद करते हैं। रूस भारत के रक्षा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, खासकर भारतीय सशस्त्र बलों और परमाणु क्षमताओं के लिए।
- **रणनीतिक प्रभाव:** यह साझेदारी भारत के भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाती है, जिससे रक्षा प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग बढ़ सकता है।

तेल के अलावा अन्य व्यापार पर प्रभाव:

- **व्यापार का विविधीकरण:** यह नया मार्ग सिर्फ कच्चे तेल के व्यापार को ही नहीं, बल्कि कोयला, उर्वरक, धातुएं और कंटेनरयुक्त माल के व्यापार को भी बढ़ावा देता है।
- **रूस को निर्यात में वृद्धि:** भारत से निर्यात होने वाले प्रसंस्कृत खनिज, लोहा और स्टील, चाय और समुद्री उत्पाद रूस को तेजी से और सस्ती शिपिंग के कारण बढ़ रहे हैं।
- **दीर्घकालिक व्यापार प्रतिबद्धताएँ:** नया समुद्री मार्ग भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक व्यापार समझौतों को बढ़ावा देता है, जो दोनों देशों के लिए लाभकारी हैं।

भारत और रूस के मध्य वायु रक्षा समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वायु रक्षा प्रौद्योगिकी पर केंद्रित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके भारत और रूस ने अपने रक्षा सहयोग में वृद्धि की है। यह समझौता भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) और रूस की रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के मध्य औपचारिक रूप से हुआ।

समझौते की मुख्य विशेषताएँ:

- **पैंटिर प्रणाली के सह-विकास के लिए समझौता ज्ञापन:**
  - » भारत की रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप पैंटिर-संस्करण वायु रक्षा प्रणाली के सह-विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  - » पैंटिर प्रणाली एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है, जोकि विभिन्न हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए मिसाइलों और तोपों का संयोजन करती है।
  - » यह प्रणाली 15 किलोमीटर तक की प्रभावी रेंज प्रदान करती है, जिससे यह मिसाइलों, विमानों, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।
- **भारत के लिए सामरिक महत्व:**
  - » यह समझौता भारत की रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाने, उन्नत खतरों का मुकाबला करने में आत्मनिर्भरता और क्षमता में

सुधार करने में मदद करेगा।

» यह समझौता ज्ञापन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता मे वृद्धि करता है, साथ ही प्रमुख रक्षा साझेदार रूस के साथ भारत के रिश्तों को भी मजबूत करता है।

भारत और रूस के बीच सामरिक रक्षा साझेदारीः

- यह कदम दीर्घकालिक रणनीतिक रक्षा साझेदारी का हिस्सा है, जोकि दशकों से चली आ रही है और इसमें मिसाइलों, नौसैनिक प्लेटफार्मों और वायु रक्षा प्रणालियों में संयुक्त परियोजनाएँ शामिल हैं।
- दोनों देश विभिन्न सैन्य प्रौद्योगिकियों पर आपसी विश्वास और सहयोग साझा करते हैं और रूस भारत के प्रमुख रक्षा साझेदारों में से एक रहा है।

आत्मनिर्भरता पर जोरः

- भारत 'मेक इन इंडिया' पहल के साथ जुड़कर रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- यह समझौता ज्ञापन, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ बनाए रखते हुए स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमताओं को आगे बढ़ाने के भारत के प्रयासों को रेखांकित करता है।

MIG-29 FIGHTER JETS

Inducted: 1987 onwards

Numbers: **60 jets**

The Indian Air Force is modernising its MiG-29s with long-range missiles, and Hindustan Aeronautics Ltd signed a contract in March to produce RD-33 aero engines for its MiG-29s with significant indigenisation

SU-30 MKI

Inducted: 2002 onwards

Numbers: **260 jets**

The multirole fighter is the frontline fighter jet of the IAF. They are being built under license by HAL

SINDHUGHOSH-CLASS ATTACK SUBMARINES

Inducted: 1989 onwards

Numbers: **7**

The Soviet Kilo-class diesel-electric submarines have upgraded and refitted from 2014 with Indian participation

हिंद–प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक स्थितिः

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच, भारत की सैन्य और रणनीतिक साझेदारियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में अपनी भूमिका बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में, भारत की मजबूत रक्षा क्षमताएँ वैश्विक सुरक्षा चर्चाओं में अधिक प्रभावी तरीके से भाग लेने में सक्षम बनाती हैं।

भारत-यूरोप

ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीपों की संप्रभुता मॉरीशस को लौटाने पर सहमति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्रिटेन ने मॉरीशस को चागोस द्वीपों की संप्रभुता लौटाने पर सहमति जताई है, जिससे ब्रिटेन की आखिरी अफ्रीकी कॉलोनी पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत हो गया है।

पृष्ठभूमिः

- 1960 के दशक से ही चागोस द्वीपों को लेकर ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच विवाद चल रहा है। उस समय, ब्रिटेन ने मॉरीशस को स्वतंत्रता देने से पहले इन द्वीपों को उससे अलग कर लिया था।
- मॉरीशस ने लगातार चागोस द्वीपसमूह को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताया है, जबकि ब्रिटेन ने इन द्वीपों पर अपनी संप्रभुता बनाए रखी है।

समझौते के बारे में:

- 2022 में शुरू हुई 13 दौर की वार्ताओं के बाद हुए इस समझौते के तहत ब्रिटेन, चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरीशस को लौटा देगा। हालाँकि, ब्रिटेन डिएगो गार्सिया द्वीप पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा, जहाँ अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है। यह व्यवस्था अमेरिका को इस क्षेत्र में अपने सैन्य अभियानों को जारी रखने की अनुमति देती है।

इस समझौते से पूर्व प्रमुख घटनाएँ:

- चागोस द्वीपों पर कानूनी विवाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) तक पहुंचा, जिसने 2019 में फैसला दिया कि ब्रिटेन का चागोस द्वीपसमूह पर शासन अवैध है और इसे मॉरीशस को लौटाना चाहिए।
- उसी साल, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें चागोस द्वीपसमूह को मॉरीशस का हिस्सा बताया गया और ब्रिटेन से अपनी उपनिवेश प्रशासन को समाप्त करने का आह्वान किया गया।
- 2022 में, मॉरीशस के राजदूत जगदीश कुञ्जुल ने चागोस द्वीपसमूह के पेरोस बानहोस द्वीप पर प्रतीकात्मक रूप से मॉरीशस का झंडा फहराया।

ऐतिहासिक संदर्भः

- ब्रिटेन साल 1814 से चागोस द्वीपों पर नियंत्रण रखता आया है। 1965 में, ब्रिटेन ने इन द्वीपों को मॉरीशस से अलग कर ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र बनाया था। इस कदम के तहत लगभग 2,000 निवासियों को जबरन वहां से हटाया गया था, जिसे मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में निंदा किया गया है।

चागोस द्वीपसमूह के बारे में:

- चागोस द्वीपसमूह हिंद महासागर में स्थित सात प्रवाल द्वीपों का समूह है, जिसमें 60 से अधिक द्वीप शामिल हैं। यह चागोस-लक्कादीव रिज का सबसे दक्षिणी द्वीपसमूह है, जिसमें समुद्र के चारों ओर कम ऊँचाई वाले द्वीप और लैगून हैं।

क्षेत्रफलः

- चागोस द्वीपसमूह का कुल भूमि क्षेत्रफल 56.13 वर्ग किमी है। सबसे बड़ा द्वीप, डिएगो गार्सिया, 32.5 वर्ग किमी में फैला है। अन्य प्रमुख द्वीपों में सोलोमन द्वीप, नेल्सन द्वीप, और पेरोस बानहोस शामिल हैं।

भारत और इटली द्वारा 5-वर्षीय रणनीतिक कार्य योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में जी20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 2025-29 के लिए व्यापक संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना का अनावरण किया।

मुख्य फोकस क्षेत्रः

- यह रणनीतिक योजना में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

रक्षा एवं सुरक्षा सहयोगः

- कार्ययोजना का मुख्य उद्देश्य भारत और इटली के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। दोनों नेताओं ने वार्षिक संयुक्त रक्षा परामर्श बैठकें और संयुक्त स्टाफ वार्ता आयोजित करने पर सहमति जताई, जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान, संयुक्त यात्राएं और प्रशिक्षण गतिविधियां सुगम होंगी।

आर्थिक और औद्योगिक सहयोगः

- कार्ययोजना में मजबूत आर्थिक सहयोग की परिकल्पना की गई है, विशेष तौर पर औद्योगिक भागीदारी के माध्यम से। इटली और भारत का लक्ष्य ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर, बुनियादी ढांचे और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है।

कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे का विकासः

- कार्ययोजना का एक प्रमुख घटक कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। दोनों देशों ने समुद्री और भूमि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई, जिसमें भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना पर विशेष ध्यान दिया गया।

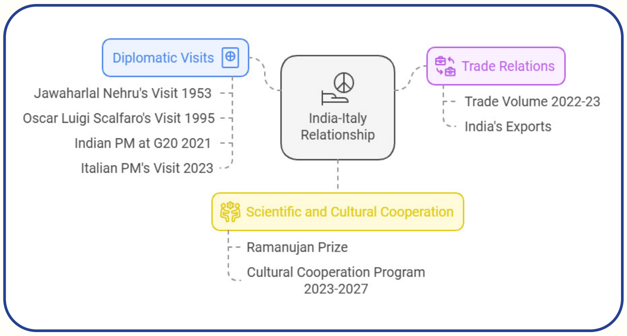

अंतरिक्ष और वैज्ञानिक सहयोगः

- योजना में सहयोग के सबसे आशाजनक क्षेत्रों में से एक अंतरिक्ष अन्वेषण है। भारत का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और इटली की इटैलियन स्पेस एजेंसी (एएसआई) पृथ्वी अवलोकन, हीलियोफिजिक्स और चंद्र विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए तैयार हैं

ऊर्जा संक्रमण और वैश्विक सहयोगः

- भारत और इटली ने वैश्विक स्थिरता पहलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने का भी संकल्प लिया। दोनों देश ऊर्जा संक्रमण प्रयासों पर मिलकर काम करेंगे, विशेष तौर पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से। इन साझेदारियों का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव को गति देना और वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है।

भारत और इटली संबंध के बारे में:

- भारत और इटली के बीच राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में इटली का दौरा किया।
- ऑस्कर लुइगी स्काल्फारो फरवरी 1995 में भारत आने वाले पहले इतालवी राष्ट्राध्यक्ष थे।
- भारतीय प्रधानमंत्री अक्टूबर 2021 में जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। मार्च 2023 में, इतालवी प्रधानमंत्री रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आए।
- मार्च 2023 में इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया गया।
- भारत-प्रशांत क्षेत्र, जिसमें भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भूमध्य सागर क्षेत्र के बीच संबंध स्थापित किया गया है। इटली भूमध्य सागर के केंद्र में स्थित है और यह भारत-प्रशांत क्षेत्र से जुड़ने का एक प्राकृतिक रास्ता है।
- जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड के बाद इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। द्विपक्षीय व्यापार 14.253 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, जिसमें भारत का इटली को निर्यात 8.691 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और ट्राइस्टे स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स (आईसीटीपी) ने विकासशील देशों के लिए गणित में डीएसटी-आईसीटीपी रामानुजन पुरस्कार की स्थापना की है। वर्ष 2022 का पुरस्कार प्रो. मोहम्मद मुस्तफा, सेनेगल को मिला।
- 2023-2027 की अवधि के लिए सांस्कृतिक सहयोग हेतु कार्यकारी कार्यक्रम पर 2023 में हस्ताक्षर किए गए, जिससे सांस्कृतिक कूटनीति को और अधिक मजबूती मिलेगी।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार वार्ता

सन्दर्भः

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार और आर्थिक सुरक्षा हेतु यूरोपीय आयुक्त मारोस सेफकोविच के साथ वार्ता की, जिसमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास, महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने और मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता को आगे बढ़ाने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान

केंद्रित किया गया। यह भारत-ईयू आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग:

- भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मोर्चों पर यूरोपीय संघ के साथ सहयोग करने की सहमति बनी है। प्राथमिक लक्ष्यों में शामिल हैं:
    - **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का विकास:** भारत और यूरोपीय संघ डिजिटल, विनिर्माण और नवाचार जैसे क्षेत्रों में आपसी विकास को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
    - **कच्चे माल की आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करना:** दोनों पक्ष ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसे उद्योगों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चे माल की स्थिर और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं, साथ ही गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता को कम करते हैं।
    - **मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए):** नेताओं ने दोनों क्षेत्रों के व्यवसायों के लिए व्यापार बाधाओं को दूर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- वार्ता ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएं संकट में हैं और देश कमियों को दूर करने और अधिक लचीली, विविध व्यापार नेटवर्क सुनिश्चित करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग के क्षेत्र:

- **आर्थिक सहयोग:**
    - **व्यापार:** यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है, 2021 में द्विपक्षीय व्यापार 88 बिलियन यूरो से अधिक था। भारत यूरोपीय संघ का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
    - **निवेश:** यूरोपीय संघ भारत में विदेशी निवेश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में यूरोपीय संघ की विदेशी निवेश हिस्सेदारी 2017 में 63.7 बिलियन यूरो से बढ़कर 2020 में 87.3 बिलियन यूरो हो गई। टाटा समूह जैसी भारतीय कंपनियों की यूरोपीय संघ में, विशेष रूप से फ्रांस और इटली जैसे देशों में मजबूत उपस्थिति है।
- **बुनियादी ढांचा विकास:** यूरोपीय संघ भारत के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, ऊर्जा और परिवहन जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है।

यूरोपीय संघ (ईयू) के बारे में:

- यूरोपीय संघ (ईयू) 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है, जोकि मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है।
- मास्ट्रिच संधि द्वारा स्थापित, जोकि 1 नवंबर, 1993 को लागू हुई। यूरोपीय संघ का उद्देश्य यूरोप में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता बढ़ाने के लिए अपने सदस्यों के बीच सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना है।
- यूरोपीय संघ अपनी सामान्य मुद्रा यूरो का उपयोग करता है, जिसे इसके 19 सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया है।
- यह एक एकल बाजार भी संचालित करता है, जोकि अपने सदस्य देशों में माल, सेवाओं और पूंजी के मुक्त आवागमन की अनुमति देता है।

भारत-फ्रांस होराइजन 2047 रोडमैप

चर्चा में क्यों?

भारत और फ्रांस ने भारत-फ्रांस होराइजन 2047 रोडमैप की समीक्षा करते हुए उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकियां रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, साइबर और डिजिटल प्रौद्योगिकियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी जटिल और औद्योगिक 4.0 प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करती हैं।

भारत–फ्रांस होराइजन 2047 रोडमैप के बारे में:

- 'होराइजन 2047' रोडमैप भारत की दीर्घकालिक रणनीति है जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में स्थापित करना है। यह योजना सुरक्षा, स्थिरता और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है।
- जुलाई 2023 में पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच एक बैठक के दौरान होराइजन 2047 रोडमैप का अनावरण किया गया था, जिसका उद्देश्य व्यापार और निवेश से लेकर रणनीतिक सहयोग तक विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है।

भारत और फ्रांस के संबंधों के बारे में:

- 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद भारत और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए, जिसने कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया।
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार, फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है, जोकि भारत के रक्षा आयातों का 33% हिस्सा है। प्रमुख परियोजनाओं में राफेल विमान की खरीद और पी-75 स्कॉर्पीन पनडुब्बी परियोजना शामिल है।
    - **राफेल विमान खरीद:** भारत ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हुए राफेल जेट खरीदे हैं।
    - **पी-75 स्कॉर्पीन परियोजना:** इसमें भारत की नौसेना के लिए उन्नत स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है।
    - **मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल (एमआरओ) सुविधाएं:** यह उन्नत विमान प्रणोदन (लीप) और राफेल इंजन रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

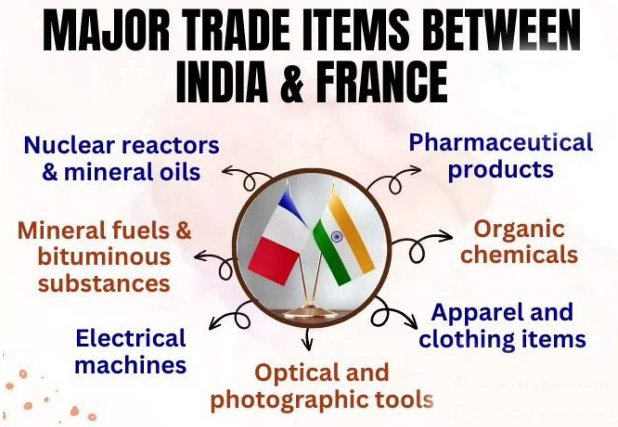

भारत और फ्रांस के बीच प्रमुख सैन्य अभ्यास:

- **द्विपक्षीय अभ्यास:** उल्लेखनीय अभ्यासों में वरुण (नौसैनिक अभ्यास) और फ्रिंजैक्स-23 (संयुक्त सैन्य अभ्यास) शामिल हैं।
- **बहुपक्षीय अभ्यास:** फ्रांस और भारत अन्य अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से ला पेरूज और ओरियन जैसे बहुपक्षीय अभ्यासों में भाग लेता है।

भारत-फ्रांस इंडो-पैसिफिक रोडमैप के बारे में:

- भारत-फ्रांस इंडो-पैसिफिक रोडमैप 2023 में जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय महासागर क्षेत्र से परे पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना है। यह रोडमैप क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत और फ्रांस का सहयोग:

- फ्रांस भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख घटक आपूर्तिकर्ता है। दोनों देश भविष्य के प्रक्षेपण वाहनों और त्रिशना पृथ्वी अवलोकन मिशन पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार हो रहा है।

भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक सहयोग:

- फ्रांस भारत में एक प्रमुख निवेशक है। वित्त वर्ष 2022-23 में फ्रांस का भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 659.77 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- उल्लेखनीय आर्थिक परियोजनाओं में टाटा ग्रुप और एयरबस द्वारा संयुक्त रूप से नागरिक हेलीकॉप्टरों का निर्माण और सीएफएम इंटरनेशनल द्वारा भारत के अकासा एयर को 300 से अधिक लीप-1बी इंजनों की बिक्री शामिल है।

भारत और फ्रांस के बीच डिजिटल सहयोग:

- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई):** फ्रांस ने एफिल टॉवर पर यूपीआई लॉन्च किया, जिससे भारतीय आगंतुकों और एनआरआई के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक लेनदेन सक्षम हुए।
- **सुपरकंप्यूटिंग:** फ्रांसीसी कंपनियों ने 14 सुपरकंप्यूटर विकसित किए हैं, जिनमें परम सिद्धि भी शामिल है, जो 4.6 पेटाफ्लॉप्स प्रति सेकंड की गति के साथ भारत का सबसे तेज सुपरकंप्यूटर है।

बहुपक्षीय सहयोग:

- फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और कश्मीर एवं आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत के रुख का लगातार समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त, फ्रांस ने भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर), वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यूए) और ऑस्ट्रेलिया समूह (एजी) जैसे महत्वपूर्ण बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण वार्ता में शामिल होने में सहायता प्रदान की है।

भारत-फ्रांस संबंधों में चुनौतियाँ:

- **द्विपक्षीय व्यापार:** दोनों देशों के मध्य व्यापार बढ़ रहा है, यह 2022 में 15.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर रहा, किन्तु अन्य वैश्विक साझेदारियों की तुलना में अभी भी कम है।
- **वीजा प्रतिबंध:** फ्रांस में भारतीय संवाददाताओं के लिए वीजा प्राप्त करना कठिन हो गया है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
- **परमाणु समझौता में विलंब:** जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना में तकनीकी, वित्तीय और परमाणु दायित्व मुद्दों के कारण देरी हो रही है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता में मतभेद:** भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति और फ्रांस की इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने की नीति में अंतर के कारण दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में चुनौतियां हैं, विशेषकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए।

भारत और यूरोपीय संघ: बहुध्रुवीय विश्व में साझेदारी का महत्व

संदर्भ:

हाल ही में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की भारत यात्रा ने भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच गठबंधन सहयोग को एक नई दिशा प्रदान की है। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के विकास में एक महत्वपूर्ण विकास है।

सहयोग की आवश्यकता:

- बदलते वैश्विक परिदृश्य, विशेष रूप से ट्रम्प प्रशासन के दौरान अमेरिका और यूरोप के बीच तनावपूर्ण संबंधों ने भारत और यूरोपीय संघ (EU) दोनों को अपनी वैश्विक स्थिति और रणनीतिक प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है।
- इन भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को प्राथमिकता देने पर सहमति व्यक्त की है।

- बढ़ती भू-राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए, दोनों पक्ष वैश्विक मामलों की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए अपनी साझेदारी को गहरा करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं।

मुक्त व्यापार समझौता:

- भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) एक प्रमुख केंद्रबिंदु है। इस समझौते पर बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन नौकरशाही अड़चनों और विवादित मुद्दों के कारण यह प्रक्रिया बार-बार बाधित होती रही। अब, दोनों पक्षों ने नए सिरे से प्रतिबद्धता दर्शाई है और इसे शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।
- वैश्विक व्यापार असंतुलन, चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और अमेरिकी व्यापार नीतियों की अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में, यह समझौता विशेष महत्व रखता है। FTA के सफल क्रियान्वयन से न केवल भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह दोनों को तेजी से उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी भू-राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर भी देगा।

INDIA-EU RELATIONS: A TIMELINE

- 1962 — Diplomatic ties established between India and the European Economic Community (EEC)
- 1981 — India and EEC sign Cooperation Agreement
- 1994 — India-EU Partnership and Development Agreement adopted
- 2000 — First India-EU Summit held
- 2004 — Relations elevated to 'Strategic Partnership'
- 2005 — India-EU Joint Action Plan (JAP) issued
- 2007 — Indfa-EU Free Trade Agreement (FTA) talks launched
- 2012 — Last regular India-EU Summit (11th) held
- 2016 — Revised India-EU Joint Action Plan adopted
- 2020 — COVID-19 era virtual 15th India-EU Summit
- 2024-2025 — FTA negotiattions resume India-EU Trade and Technology Council (TTC) cooperation

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ:

- भारत उन पहले देशों में से एक था, जिसने 1963 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) (जो बाद में यूरोपीय संघ (EU) बना) के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। हालांकि, शुरुआती दशकों में यह संबंध अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहा। शीत युद्ध के दौरान, भारत और सोवियत संघ के घनिष्ठ संबंध तथा भारत की आर्थिक नीतियों ने यूरोप के साथ गहरे आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग की संभावनाओं को सीमित कर दिया।
- 1990 के दशक की शुरुआत में, सोवियत संघ के विघटन और भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद दोनों पक्षों के बीच सहयोग में वृद्धि हुई। 2004 में, भारत और EU ने औपचारिक रूप से रणनीतिक साझेदारी स्थापित की और 2007 में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता शुरू हुई।
- हालांकि, व्यापारिक और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के इन प्रयासों को नौकरशाही अड़चनों, मानकों को लेकर मतभेदों और राजनीतिक प्राथमिकताओं के टकराव जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप, भारत-EU रणनीतिक साझेदारी व्यावहारिक होने के बजाय प्रतीकात्मक (Symbolic) बनकर रह गई।

भारत और आयरलैंड के मध्य संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना

संदर्भ:

हाल ही में भारत और आयरलैंड ने द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त आर्थिक आयोग (JEC) स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। यह निर्णय डबलिन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और आयरिश विदेश मंत्री साइमन हैरिस के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया है।

संयुक्त आर्थिक आयोग (JEC) के बारे में:

- संयुक्त आर्थिक आयोग (JEC) भारत और आयरलैंड के बीच आंतरिक सहयोग बढ़ाने, व्यापार में वृद्धि करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में काम करेगा।

उद्देश्य:

- संयुक्त आर्थिक आयोग (JEC) का उद्देश्य भारत और आयरलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ावा देना है।
- यह व्यापार, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना है।

फोकस क्षेत्र:

- **व्यापार संबंध:** संयुक्त आर्थिक आयोग दोनों देशों के बीच व्यापार में आपसी विकास और सहयोग के नए अवसरों की खोज

करेगा। इसमें फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स और मशीनरी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात और आयात बढ़ाना शामिल है।

- **निवेश प्रवाह में वृद्धि:** जेईसी दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें प्रौद्योगिकी, कृषि और स्वच्छ ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोनों देश आपसी निवेश प्रवाह को बढ़ाने के अवसरों की खोज करेंगे, जिससे रोजगार पैदा होंगे और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** सूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी), फिन-टेक और स्मार्ट सिटी पहल में सहयोग बढ़ाना एक प्रमुख उद्देश्य होगा। दोनों देश महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तकनीकी ताकत का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत-आयरलैंड संबंधों के बारे में:

- भारत और आयरलैंड के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित किए गए थे। भारत ने 1951 में डबलिन में अपना दूतावास खोला, जबकि आयरलैंड ने 1964 में नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला। मुंबई और बेंगलुरु में मानद वाणिज्य दूतावास क्रमशः 1976 और 2000 में स्थापित किए गए और 2010 और 2017 में चेन्नई और कोलकाता में इसका विस्तार किया गया।
- **द्विपक्षीय व्यापार:**
  - » 2023-2024 के लिए, भारत और आयरलैंड के बीच कुल व्यापार 6.37 बिलियन अमरीकी डॉलर है।
  - » भारत से प्रमुख निर्यात में कार्बनिक रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और विमान के पुर्जे शामिल हैं।
  - » आयरलैंड से भारत में आयात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में इलेक्ट्रिकल मशीनरी, प्लास्टिक के सामान शामिल हैं।
- **शिक्षा:**
  - » वर्तमान में लगभग 6,000 भारतीय छात्र आयरिश विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं।
  - » उल्लेखनीय सहयोगों में ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन और थापर विश्वविद्यालय के बीच संयुक्त डिग्री कार्यक्रम शामिल हैं।
- **आयरलैंड में भारतीय समुदाय:**
  - » आयरलैंड में भारतीय मूल के लगभग 80,000 लोग हैं, जिनमें से लगभग 40,000 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) हैं।
  - » भारतीय समुदाय के लोग विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, आईटी, इंजीनियरिंग और प्रबंधन क्षेत्रों में प्रमुख है।
  - » पूर्व आयरिश पीएम लियो वराडकर भारतीय मूल के हैं, जोकि आयरिश समाज में भारतीय समुदाय के एकीकरण का प्रतीक है।

भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि

सन्दर्भ:

स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन, जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के सदस्य हैं, भारत के साथ एक द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर बातचीत कर रहे हैं। यह संधि मार्च 2024 में भारत और EFTA के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद चर्चा में आई है, जिसका लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का निवेश करना है।

स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन भारत के साथ यह संधि क्यों चाहते हैं?

- **कर संबंधी समस्याएँ और नेस्ले मामला:**
  - » दिसंबर 2024 में स्विट्जरलैंड ने 1994 के कर समझौते (DTAA) में बदलाव किया, जिससे स्विस कंपनियों को भारत में ज्यादा कर चुकाना पड़ा।
  - » नेस्ले जैसे स्विस ब्रांडों को भी ज्यादा कर देना पड़ा, जिससे स्विस निवेशकों की चिंता बढ़ गई।
  - » इसलिए, स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन चाहते हैं कि BIT के जरिए उनके निवेश को सुरक्षा मिले।
- **भारत द्वारा पुराने निवेश समझौतों को रद्द करना:**
  - » भारत ने 1993 के बाद किए गए पुराने निवेश समझौतों को रद्द कर दिया, क्योंकि वह कई अंतरराष्ट्रीय कानूनी विवादों में फंस गया था।
  - » पहले के समझौते विदेशी निवेशकों को ज्यादा अधिकार देते थे, जिससे भारत के लिए नुकसान की संभावना बढ़ जाती थी।
  - » नए निवेशकों की सुरक्षा के लिए स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन अब एक नए BIT की मांग कर रहे हैं।
- **भारत के नए निवेश नियम:**
  - » 2016 में भारत ने एक नया BIT मॉडल बनाया, जिसमें विदेशी निवेशकों को पहले भारत में सभी कानूनी विकल्पों को आजमाने के बाद ही अंतरराष्ट्रीय अदालतों में जाने की अनुमति दी गई।
  - » पश्चिमी देशों को यह नियम बहुत सख्त लगा और उन्होंने भारत से ज्यादा निवेशक-अनुकूल नीतियाँ अपनाने का आग्रह किया।

भारत का नए BIT की ओर झुकाव:

- **बजट में सुधार:** सरकार ने अपनी नीतियों में विदेशी निवेशकों की चिंताओं को ध्यान में रखा है।
- **नए समझौते:** भारत ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ भी इसी तरह की निवेश संधि पर बातचीत कर रहा है।
- **संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से सीख:** भारत ने हाल ही में UAE के साथ BIT किया, जिसमें निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा उपाय शामिल थे।

स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन के साथ BIT से भारत को क्या लाभ होगा?

- **विदेशी निवेश बढ़ेगा:**
  - » BIT से विदेशी निवेशकों को भरोसा मिलेगा, जिससे वे भारत में लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे।
  - » इससे फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे सेक्टर मजबूत होंगे।
- **अंतरराष्ट्रीय व्यापार मानकों का पालन:**
  - » भारत निवेश नियमों को अपडेट करके वैश्विक स्तर पर खुद को मजबूत बनाएगा।
  - » इससे भारत निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक स्थान बन जाएगा।
- **आर्थिक और रणनीतिक फायदे:**
  - » एक मजबूत BIT, 'मेक इन इंडिया' और बुनियादी ढांचे के विकास को मदद करेगा।
  - » स्पष्ट और स्थिर नीतियाँ भारत को ज्यादा व्यापारिक सौदे और विदेशी भागीदार आकर्षित करने में मदद करेंगी।

भारत और यू.के. के बीच रक्षा सहयोग को मजबूती

संदर्भ:

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) ने अपने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एयरो इंडिया 2025 में डिफेंस पार्टनरशिप-इंडिया (DP-I) की औपचारिक शुरुआत की गई और कई अहम समझौतों की घोषणा हुई। ये समझौते मुख्य रूप से वायु रक्षा प्रणाली, मिसाइल उत्पादन और नौसेना से जुड़े नए विकास पर केंद्रित हैं, जिससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी।

डिफेंस पार्टनरशिप-इंडिया (DP-I) की शुरुआत:

- यू.के. के रक्षा मंत्रालय ने DP-I (डिफेंस पार्टनरशिप-इंडिया) नाम से एक विशेष सेल बनाई है, जिसका मकसद भारत के साथ रक्षा सहयोग को और गहरा करना है जिससे संयुक्त रक्षा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा, सहयोग को बेहतर बनाया जाएगा और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध मजबूत होंगे।

मुख्य रक्षा समझौते और नई पहलें:

- **MANPADS और लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइल (LMM) का उत्पादन**
  - » थेल्स यू.के. (Thales U.K.) व भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत लेजर बीम-राइडिंग मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (LBRMs) का उत्पादन किया जाएगा।
  - » इस समझौते में STARStreak हाई-वेलोसिटी मिसाइलों और लॉन्चरों की आपूर्ति शामिल है, जिससे भारत की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत होगी।
  - » इसके अलावा, थेल्स और बीडीएल मिलकर लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइल (LMMs) का उत्पादन करेंगे। इस साझेदारी से भारतीय उद्योगों को थेल्स की वैश्विक आपूर्ति शृंखला (Global Supply Chain) में जोड़ा जाएगा, जिससे दोनों देशों में नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे और सैन्य उपकरणों की अंतर-संगतता (Interoperability) भी बेहतर होगी।
- **ASRAAM असेंबली और टेस्ट सुविधा की स्थापना:**
  - » भारत में पहली बार हैदराबाद में एक ASRAAM (Advanced Short-Range Air-to-Air Missile) असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी।
  - » यह सुविधा जगुआर (Jaguar) और हल्के लड़ाकू विमान Mk1A (LCA-Mk1A) के लिए ASRAAM मिसाइलों का निर्माण करेगी। इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन और निर्यात दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
- **नौसेना सहयोग और समुद्री रक्षा प्रणाली में सुधार:**
  - » भारत की अगली पीढ़ी की लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक (LPD) बेड़े के लिए एकीकृत पूर्ण इलेक्ट्रिक प्रणोदन (IFEP) सिस्टम के डिजाइन और विकास को लेकर एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट (SoI) पर हस्ताक्षर किए गए।
  - » GE वर्नोवा (GE Vernova) और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के बीच समझौता हुआ है, जिसमें भारत की पहली समुद्री भूमि-आधारित परीक्षण सुविधा (Maritime Land-Based Testing Facility) विकसित करने की योजना है।
  - » इस तकनीक से भारतीय नौसेना को 2030 तक उन्नत LPDs (Landing Platform Docks) प्राप्त हो सकेंगे।

आत्मनिर्भरता भारत को बढ़ावा:

- ये सभी समझौते भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप हैं, जिससे भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को मजबूती मिलेगी और यू.के. के साथ तकनीकी व औद्योगिक साझेदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। इन समझौतों से आर्थिक विकास, सुरक्षा हितों और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग को बल मिलेगा।

भारत-पश्चिम एशिया

भारत-कतर सामरिक साझेदारी: भू-राजनीतिक बदलावों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती

17-18 फरवरी 2025 में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी की भारत की राजकीय यात्रा दोनों देशों के बीच विकसित होते संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई। इस यात्रा के दौरान भारत-कतर संयुक्त व्यापार मंच का आयोजन किया गया, जहां दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने वित्त, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के प्रमुख हितधारकों के साथ आर्थिक सहयोग के नए अवसरों पर विस्तृत चर्चा की। इस यात्रा के दौरान भारत और कतर ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा, निवेश और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना है। इस बैठक का एक प्रमुख परिणाम यह रहा कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त, कतर ने भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह रणनीतिक संरेखण ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुआ है, जब दोनों देश वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव और मध्य पूर्व में उभरती भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

यात्रा के मुख्य बिंदु :

- **रणनीतिक साझेदारी की ओर उन्नयन:** भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण राजनयिक संबंध रहे हैं। हाल ही में, इन संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' (Strategic Partnership) तक उन्नत करने का निर्णय लिया गया, जो दोनों देशों के बीच गहरे और बहुआयामी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सामान्यतः भारत अपनी कूटनीतिक शब्दावली में 'रणनीतिक साझेदारी' शब्द का उपयोग यूएई और सऊदी अरब जैसे प्रमुख सहयोगियों के लिए करता रहा है। ऐसे में भारत-कतर संबंधों में इसका समावेश प्रतिबद्धता के एक नए स्तर का संकेत देता है। भारत और कतर के बीच रणनीतिक साझेदारी मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी:
  - **ऊर्जा सुरक्षा:** दीर्घकालिक एलएनजी (LNG) और एलपीजी (LPG) आपूर्ति सुनिश्चित करना।
  - **निवेश और व्यापार:** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देना और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना।
  - **रक्षा और सुरक्षा:** समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी उपायों में सहयोग (जैसे 'जाइर-अल-बहर' संयुक्त अभ्यास)।
  - **प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचा:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), फिनटेक और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में निवेश।

- **आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबद्धताएँ:**
  - कतर के सॉवरेन वेल्थ फंड (Sovereign Wealth Fund) ने पहले ही भारत में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। अब कतर ने बुनियादी ढाँचे, नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में अतिरिक्त 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।
  - दोनों देशों ने अगले पाँच वर्षों में व्यापार को 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
  - व्यापारिक लेन-देन को सुगम बनाने के लिए दोहरा कराधान बचाव समझौते (DTAA) में संशोधन किया गया, जिससे व्यापार और निवेश के लिए अधिक अनुकूल माहौल तैयार होगा।
- **मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) की चर्चा:**
  - भारत और कतर ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की संभावनाओं पर भी विचार किया, जिससे व्यापार और

निवेश को नई गति मिल सकती है। यह वार्ता भारत की खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ व्यापक व्यापार वार्ता का हिस्सा है। यदि GCC के साथ FTA को अंतिम रूप दिया जाता है, तो इससे ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल और सेवा क्षेत्रों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा।

- **बुनियादी ढांचा और वित्तीय एकीकरण:**
  - » कतर में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) को लागू करने की योजना पर चर्चा हुई। इससे वित्तीय लेन-देन को सरल बनाया जा सकेगा, विशेष रूप से भारतीय प्रवासी समुदाय को इससे बड़ा लाभ मिलेगा।
  - » कतर नेशनल बैंक GIFT सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने पर विचार कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच वित्तीय सेवाओं को अधिक एकीकृत किया जा सके।
- **भू-राजनीतिक और क्षेत्रीय सहयोग:**
  - » भारत ने इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष में 'दो-राज्य समाधान' (Two-State Solution) के अपने समर्थन को दोहराया और कतर के मध्यस्थता प्रयासों के साथ तालमेल बनाए रखने पर सहमति जताई।
  - » कतर अफगानिस्तान और गाजा जैसे संघर्ष क्षेत्रों में मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह कूटनीतिक स्थिति भारत की मध्य पूर्व नीति को भी प्रभावित करती है और भारत-कतर संबंधों को और अधिक प्रासंगिक बनाती है।

कतर, भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- **ऊर्जा सहयोग:**
  - » कतर भारत का सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आपूर्तिकर्ता है, जो भारत के कुल एलएनजी आयात का 48% हिस्सा है।
  - » यह भारत का प्रमुख तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) आपूर्तिकर्ता भी है, जो कुल LPG आयात में 29% का योगदान देता है।
  - » यह स्थिर और निर्बाध ऊर्जा साझेदारी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है, जिससे कोयले पर निर्भरता कम करने और बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता मिलेगी।
  - » हालिया कतर एनर्जी ने भारत की पेट्रोनेट के साथ 78 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 20-वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

India-Qatar Ties Soar to New Heights

- **Strategic Leap** – Bilateral ties upgraded to a **strategic partnership.**
- **Trade Target** – Aim to **double trade** from $14 billion to $28 billion by 2030.
- **Investment Boost** – Qatar pledges **$10 billion investment** in India.
- **Cultural Ties** – Plans to celebrate **India-Qatar Year of Culture, Friendship & Sports.**
- **Digital Expansion** – **UPI to be accepted nationwide** in Qatar.
- **Ease of Travel**– **E-visa facility extended** to Qatari nationals.
- **Strengthening Bonds** – **5 MoUs signed** on trade, youth, sports, archives & business collaboration.

- **सामरिक और भू-राजनीतिक सहयोग:**
  - » कतर भारत की 'लिंक एंड एक्ट वेस्ट' नीति का एक प्रमुख केंद्र है, जो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत जैसे खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है।
  - » कतर की रणनीतिक स्थिति इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि यह भारत की कच्चे तेल की 55.3% से अधिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करने वाले क्षेत्र में स्थित है।
  - » मध्य पूर्व के विभिन्न संघर्षों, जैसे अफगानिस्तान और इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे में कतर की कूटनीतिक भूमिका, भारत को क्षेत्रीय मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाती है।
- **आतंकवाद निरोध और रक्षा सहयोग:**
  - » भारत और कतर आतंकवाद-रोधी अभियानों और समुद्री सुरक्षा में समान हित साझा करते हैं।
  - » 'जाइर-अल-बहर' नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास दोनों देशों के बीच नौसैनिक सहयोग को मजबूत करता है।
  - » नियमित नौसैनिक दौरों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और अधिक बढ़ाया जा रहा है।

भारत-कतर द्विपक्षीय संबंध:

- **व्यापारिक संबंध:**
  - » भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 14.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - » भारत, कतर के शीर्ष तीन निर्यात गंतव्यों (चीन और जापान के साथ) और कतर के शीर्ष तीन आयात स्रोतों (चीन और अमेरिका के साथ) में शामिल है।
  - » कतर द्वारा भारत को किए जाने वाले प्रमुख निर्यात

में एलपीजी, एलएनजी, पेट्रोकेमिकल्स, रसायन और एल्युमीनियम शामिल हैं।

» भारत द्वारा कतर को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में अनाज, वस्त्र, लोहा, इस्पात और मशीनरी शामिल हैं।

- **निवेश:**
  - » कतर में 15,000 से अधिक भारतीय कंपनियां कार्यरत हैं। भारतीय कंपनियों ने 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कतर में किया है।
  - » कतरी बिजनेस एसोसिएशन (QBA) और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के मध्य व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते (MoUs) किए गए हैं।
- **सांस्कृतिक और प्रवासी संबंध:**
  - » 2012 के सांस्कृतिक सहयोग समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया। 2019 को 'भारत-कतर संस्कृति वर्ष' के रूप में मनाया गया था।
  - » कतर में 8,00,000 से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है और कतर की कुल जनसंख्या का लगभग 27% हिस्सा हैं।

रणनीतिक निहितार्थ और भविष्य की संभावनाएं:

- भारत और कतर के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाना द्विपक्षीय सहयोग के एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। आर्थिक और ऊर्जा सहयोग के साथ-साथ रक्षा और आतंकवाद-निरोध प्रयासों का विस्तार, भविष्य की भागीदारी के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है।
- वार्ता के दौरान, भारत ने कतर के आर्थिक हितों को समायोजित करने के प्रति लचीला दृष्टिकोण अपनाया, जो 2024 में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ हुई द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के समान है। यह लचीलापन पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक संबंधों को दर्शाता है।
- इसके अतिरिक्त, पश्चिम एशिया में कतर का भू-रणनीतिक महत्व, क्षेत्रीय संघर्षों में इसकी मध्यस्थता की भूमिका तथा अमेरिका और क्षेत्रीय शक्तियों (जैसे सऊदी अरब और ईरान) के साथ इसके मजबूत संबंध, इसे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक साझेदार बनाते हैं।

निष्कर्ष:

भारत-कतर की रणनीतिक साझेदारी, खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत की गहरी होती भागीदारी को दर्शाती है। चूंकि दोनों देश व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और निवेश सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए द्विपक्षीय संबंधों का भविष्य अत्यधिक आशाजनक और गतिशील प्रतीत होता है। व्यापार को दोगुना करने, भारत में कतर के निवेश को बढ़ाने तथा रक्षा और वित्तीय एकीकरण को मजबूत करने की प्रतिबद्धता, इस संबंध को आने वाले वर्षों में अधिक लचीला और व्यापक बनाएगी।

भारत-कुवैत संबंध

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की कुवैत यात्रा भारत-कुवैत संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इस यात्रा में दोनों देशों ने अपने संबंधों को 'रणनीतिक' स्तर तक बढ़ाया। 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी, जो खाड़ी क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव और बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाती है। यह यात्रा व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सहयोग को मजबूत करने के साथ-साथ भविष्य में गहरे संबंधों की नींव रखती है।

भारत-कुवैत संबंधों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

- भारत और कुवैत के संबंध 1961 में कुवैत की स्वतंत्रता के बाद से ही गहरे और ऐतिहासिक रहे हैं। भारत कुवैत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।
- कुवैत के स्वतंत्रता से पहले, भारतीय रुपया कुवैत में कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। आज भी, कुवैत भारत का एक प्रमुख सहयोगी बना हुआ है।

मौजूदा संबंधों की स्थिति:

- **ऊर्जा सहयोग:** कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता है और भारत की ऊर्जा जरूरतों का लगभग 3% पूरा करता है।
- **द्विपक्षीय व्यापार:** दोनों देशों के बीच व्यापार $10 अरब से अधिक है। भारत का कुवैत को निर्यात पहली बार $2 अरब के पार पहुंचा।
- **भारतीय समुदाय:** कुवैत में भारतीय समुदाय 10 लाख से अधिक लोगों का है, जो कुवैत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **निवेश:** कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भारत में $10 अरब से अधिक का निवेश किया है, जो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है।

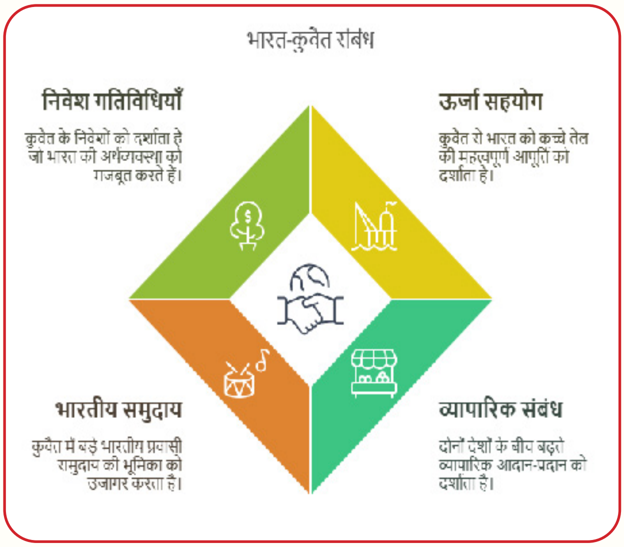

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का महत्व:

प्रधानमंत्री मोदी की 2024 की यह यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक थी।

- **43 साल बाद पहली प्रधानमंत्री यात्रा:** 1981 में इंदिरा गांधी की यात्रा के बाद यह पहली प्रधानमंत्री यात्रा थी।
- **सम्मान:** कुवैत ने मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'मुबारक अल-कबीर ऑर्डर' से सम्मानित किया, जो भारत-कुवैत संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका को मान्यता देता है।
- **प्रमुख नेताओं से मुलाकात:** मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा और क्राउन प्रिंस शेख सबा अल- खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबा से मुलाकात की, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों का नया अध्याय शुरू हुआ।

रणनीतिक सहयोग को मजबूत बनाना:

मोदी की यात्रा के दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें शामिल हैं:

- **रक्षा सहयोग:** एक व्यापक रक्षा समझौता हुआ, जिसमें सैन्य कर्मियों का आदान-प्रदान, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा तकनीक में सहयोग शामिल है।
- **मुख्य क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन (MoU):** खेल, संस्कृति और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में समझौते।
- **निवेश के अवसर:** मोदी ने कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को भारत के ऊर्जा, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर और खाद्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।

क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव:

- मोदी की यात्रा ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के बीच संबंधों को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त किया। कुवैत इस परिषद का एक महत्वपूर्ण सदस्य है।
- **क्षेत्रीय शांति और स्थिरता:** भारत और कुवैत ने पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए साझा लक्ष्यों पर चर्चा की।
- **आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता:** दोनों देशों ने आतंकवाद की निंदा की और आतंकवादी नेटवर्क को समाप्त करने का संकल्प लिया, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित हो सके।

भारत-ईरान-अर्मेनिया त्रिपक्षीय परामर्श

चर्चा में क्यों?

नई दिल्ली में आयोजित दूसरे भारत-ईरान-अर्मेनिया त्रिपक्षीय परामर्श का फोकस कनेक्टिविटी, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग बढ़ाने पर था। भारत के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान विभाग के संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में, इस परामर्श में ईरान और अर्मेनिया के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल थे।

चर्चा के प्रमुख क्षेत्र:

- **कनेक्टिविटी पहल:** चर्चाओं में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) और ईरान में चाबहार बंदरगाह के महत्व पर जोर दिया गया। इन पहलों का उद्देश्य तीनों देशों के बीच और उससे आगे, विशेष रूप से मध्य एशिया और यूरोप तक व्यापार मार्गों को बढ़ाना है। अर्मेनिया ने अपनी 'क्रॉसरोड्स ऑफ पीस' कनेक्टिविटी पहल का परिचय दिया, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और सुधारना है।
- **व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया। त्रिपक्षीय भागीदारों ने आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
- **भविष्य के परामर्श:** त्रिपक्षीय भागीदारों ने ईरान में एक सुविधाजनक तिथि पर अगले दौर के परामर्श आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।

भारत–ईरान द्विपक्षीय संबंध:

- **आर्थिक सहयोग:** भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2022-23 में $2.33 बिलियन तक पहुंच गया। भारत का ईरान को निर्यात $1.66 बिलियन था, जबकि आयात $672.12 मिलियन था।
- **ऊर्जा सहयोग:** ऊर्जा भारत-ईरान संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है, विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह के साथ जो एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान करता है। प्रतिबंधों के बावजूद, ईरान का कच्चा तेल उत्पादन मई 2024 में 3.4 मिलियन बैरल प्रति दिन तक पहुंच गया।

- **रणनीतिक कनेक्टिविटी परियोजनाएँ:** चाबहार बंदरगाह और चाबहार और जहेदान के बीच 700 किमी रेलवे लिंक का विकास, जिसमें अफगानिस्तान से जुड़ाव शामिल है, जो प्रमुख परियोजनाओं में से हैं।

भारत–अर्मेनिया द्विपक्षीय संबंध:

- **आर्थिक संबंध:** भारत और अर्मेनिया आईटी, फार्मास्युटिकल और कृषि जैसे क्षेत्रों में अप्रयुक्त व्यापार संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। 2020 में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $46.3 मिलियन था।
- **सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग:** भारतीय संस्कृति, सिनेमा, योग और आयुर्वेद सहित, अर्मेनिया में लोकप्रिय हैं। इसके अलावा, कई भारतीय छात्र अर्मेनिया में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिससे सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध मजबूत होते हैं।

भारत–ईरान रक्षा संबंध

- भारत और ईरान ने सुरक्षा और रणनीतिक चिंताओं को संबोधित करने के लिए कई परामर्शात्मक तंत्र स्थापित किए हैं। इनमें विदेश कार्यालय परामर्श, सुरक्षा परामर्श और संयुक्त वाणिज्यिक बैठकें शामिल हैं।

भारत–अर्मेनिया रक्षा संबंध

- **हथियार समझौते:** अर्मेनिया ने 2020 में भारत के साथ $40 मिलियन का हथियार समझौता किया, जिसमें हथियारों के स्थान का पता लगाने के लिए स्वाथी राडार की आपूर्ति शामिल थी।
- **मिसाइल और आयुध निर्यात:** भारत ने अर्मेनिया को पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर और मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM) का भी निर्यात किया है, जिससे दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं में सुधार हुआ है।

भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी

सन्दर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा भारत-सऊदी अरब द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण रही। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद (SPC) की दूसरी बैठक की सह-अध्यक्षता की और रणनीतिक व उभरते क्षेत्रों में कई समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि यह यात्रा जम्मू-कश्मीर में हुए एक आतंकी हमले के कारण संक्षिप्त हो गई।

2025 की द्विपक्षीय भागीदारी के प्रमुख परिणाम:

- दो नए मंत्री-स्तरीय समिति "एक रक्षा सहयोग पर और दूसरी पर्यटन व सांस्कृतिक सहयोग पर" गठित की गईं। इसके साथ ही अब SPC चार प्रमुख समितियों के माध्यम से कार्य करती है:
  - राजनीतिक, वाणिज्य दूतावास और सुरक्षा सहयोग
  - रक्षा सहयोग
  - अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, निवेश और प्रौद्योगिकी
  - पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग
- सऊदी अरब ने ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हाई-लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट (HLTF) ने कर सुधारों और भारत में दो प्रमुख रिफाइनरियों की स्थापना जैसी परियोजनाओं में सहयोग को बढ़ावा दिया है।

प्रमुख समझौते और एमओयू:

- **अंतरिक्ष सहयोग:** सऊदी स्पेस एजेंसी और भारत के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बीच शांतिपूर्ण अंतरिक्ष गतिविधियों पर समझौता।

- **स्वास्थ्य सहयोग:** दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने हेतु समझौता।
- **एंटी-डोपिंग:** SAADC और NADA के बीच शिक्षा और रोकथाम हेतु समझौता।
- **डाक सेवाएं सहयोग:** सऊदी पोस्ट और भारत के डाक विभाग के बीच सतही पार्सल सेवाओं पर समझौता।

भारत और सऊदी अरब की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकसित होती साझेदारी:

- भारत-सऊदी संबंध कूटनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में निरंतर मजबूत हुए हैं। भारत, सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, वहीं सऊदी अरब, भारत के लिए पांचवां सबसे बड़ा भागीदार है।
- **अर्थव्यवस्था:** वित्तीय वर्ष 2023–24 में, द्विपक्षीय व्यापार 42.98 अरब डॉलर रहा, जिसमें भारतीय निर्यात 11.56 अरब डॉलर और आयात 31.42 अरब डॉलर रहा। भारतीय निवेश सऊदी अरब में 3 अरब डॉलर है, जबकि सऊदी निवेश, विशेषकर पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF) के माध्यम से, भारत में 10 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।
    - सऊदी अरब भारत में 20वां सबसे बड़ा एफडीआई योगदानकर्ता है, जिसने 2000 से 2024 के बीच कुल 3.22 अरब डॉलर का निवेश किया है।
- **ऊर्जा:** 2023–24 में सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता (14.3%) और एलपीजी आपूर्तिकर्ता (18.2%) रहा।
- **रक्षा:** रक्षा सहयोग संयुक्त अभ्यासों जैसे EX-SADA TANSEEQ (स्थल) और Al Mohed Al Hindi (नौसेना) के माध्यम से बढ़ा है।
- **सांस्कृतिक संबंध:** द्विपक्षीय हज समझौते 2024 के तहत 1.75 लाख भारतीय तीर्थयात्रियों को अनुमति दी गई, जिसमें बिना मेहरम महिलाओं का भी समर्थन शामिल है। सऊदी अरब में योग को मान्यता और 2018 में नौफ अल-मारवाई को पद्म श्री सम्मान दिए जाने से सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। सऊदी अरब में 26 लाख भारतीयों की संख्या इसे वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समूह बनाती है।

मुख्य चुनौतियाँ:

- श्रमिक कल्याण अभी भी चिंता का विषय है, क्योंकि कई भारतीय कामगार “कफाला” जैसे कठोर सिस्टम के तहत शोषण का सामना करते हैं। भारत के सऊदी अरब से व्यापार घाटा लगभग 20 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसका कारण मुख्य रूप से तेल पर निर्भरता और वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव है।
- इसके अतिरिक्त, यमन में सऊदी की कार्रवाई, कतर नाकाबंदी और ईरान के साथ प्रतिद्वंद्विता जैसे क्षेत्रीय कदम भारत के लिए कूटनीतिक चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं, विशेषकर जब सऊदी के चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं।

भारत-दक्षिण पूर्व एशिया

छठी भारत-सिंगापुर रक्षा मंत्री वार्ता

चर्चा में क्यों?

भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा मंत्रियों की छठी वार्ता का आयोजन हुआ, जिसकी सह-अध्यक्षता भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉ. एनजी इंग हेन ने की।

बैठक के मुख्य बिंदु:

- **रक्षा सहयोग में वृद्धि:** भारत और सिंगापुर ने रक्षा उपकरणों के सह-विकास और सह-उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने रक्षा संबंधों को और गहरा करने का संकल्प लिया है। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण न केवल सैन्य संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि तकनीकी नवाचार को भी प्रोत्साहित करेगा।
- **संयुक्त सैन्य प्रशिक्षणों का विस्तार:** बैठक में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षणों के विस्तार पर चर्चा हुई। प्रशिक्षण क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में अंतर-संचालन और तैयारी को महत्वपूर्ण बनाते है। नियमित संयुक्त अभ्यास इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता:** वार्ता में क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। भू-राजनीतिक तनावों से भरे इस दौर में, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित और स्थिर माहौल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के सहयोग अत्यावश्यक हैं।
- **राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने का जश्न:** भविष्य में, भारत और सिंगापुर 2025 में अपने राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने की योजना बना रहे हैं। यह उपलब्धियों का मूल्यांकन करने तथा रक्षा क्षेत्र में भविष्य के सहयोग के लिए नवीन लक्ष्यों का निर्धारण करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है।

भारत–सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता के बारे में:

- **स्थापना:** 2016 में आरंभ हुआ भारत-सिंगापुर रक्षा मंत्रियों का संवाद द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।
- **उद्देश्य:** इस वार्ता का उद्देश्य सिंगापुर और भारत के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत और गहरा करना है, जो उनके पारस्परिक रणनीतिक हितों और प्रतिबद्धताओं को प्रतिबिंबित करता है।

भारत–सिंगापुर संबंध के बारे में:

ऐतिहासिक संबंध:

- **संबंधो का आधार:** 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स के द्वारा सिंगापुर ने भारत के साथ ऐतिहासिक व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित किया।
- **मान्यता:** भारत 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, फिर दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत हुई।

व्यापार और आर्थिक सहयोग:

- **द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि:** व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) के कारण, द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 35.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें भारत शुद्ध आयातक होगा।
- **कर समझौते:** 2016 में हस्ताक्षरित प्रत्यक्ष कर बचाव समझौते (डीटीएए) का उद्देश्य कर चोरी को रोकना और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाना है।

रक्षा संबंध:

- **सामरिक समुद्री क्षमता में वृद्धि:** भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा सहयोग भारत की क्षेत्रीय सामरिक समुद्री क्षमताओं को बढ़ाता है और हिंद महासागर में सुरक्षा साझेदार के रूप में सिंगापुर की भूमिका को सुदृढ़ करता है।
- **संयुक्त अभ्यास:** प्रमुख सैन्य अभ्यासों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - » अभ्यास अग्नि वारियर (सेना)
  - » अभ्यास सिम्बेक्स (नौसेना)
  - » वायु सेना अभ्यास संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण (जेएमटी)

फिनटेक और बहुपक्षीय सहयोग:

- **फिनटेक का विकास:** सीमा पार फिनटेक में महत्वपूर्ण प्रगति, जैसे रुपे कार्ड और यूपीआई-पेनाउ लिंकेज, दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और सशक्त बनाते हैं।

सिंगापुर में भारतीय समुदाय:

- **जनसंख्या आँकड़े:** सिंगापुर की निवासी जनसंख्या में जातीय भारतीय लोगों की संख्या 9.1% है तथा तमिल चार आधिकारिक भाषाओं में से एक है।
- **भारतीय नागरिक:** सिंगापुर में 1.6 मिलियन विदेशियों में से लगभग एक-पांचवां हिस्सा भारतीय नागरिक हैं, जो वहां की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

भारत-थाईलैंड संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 12 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें भारत-थाईलैंड रक्षा संवाद ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक

संबंधों को रेखांकित किया। भारत और थाईलैंड का संबंध सदियों पुराना है जो व्यापार, संस्कृति और धर्म में निहित है। यह साझेदारी वर्षों में व्यापार, निवेश, रक्षा और पर्यटन सहित बहु-क्षेत्रीय सहयोग में विकसित हुई है।

हाल के विकास:

- भारत के संयुक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) और थाईलैंड के उप स्थायी रक्षा सचिव द्वारा सह-अध्यक्षता की गई, इस संवाद में निम्नलिखित पहलुओं की खोज की गई:
  - » रक्षा उद्योग सहयोग की निगरानी के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना।
  - » सशस्त्र बलों के बीच विषय विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करना।
  - » रक्षा उद्योगों में सह-डिजाइन, सह-उत्पादन और सह-विकास की संभावनाओं की खोज।
- यह संवाद थाईलैंड की भारत की एक्ट ईस्ट नीति में रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है और थाईलैंड की लुक वेस्ट नीति को पूरा करता है, जिससे द्विपक्षीय संबंध बढ़ते हैं।

व्यापार और निवेश:

- भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है:
  - » 2020: $9.76 बिलियन
  - » 2021: $15 बिलियन
  - » 2022-23: $16.89 बिलियन
- **थाईलैंड को भारत के प्रमुख निर्यात:**
  - » **मोती, बहुमूल्य पत्थर और आभूषण:** $1.02 बिलियन (2022-23)
  - » **मैकेनिकल मशीनरी और पार्ट:** $570 मिलियन (अप्रैल-नवंबर 2023-24)
  - » **समुद्री उत्पाद:** $219 मिलियन (अप्रैल-नवंबर 2023-24)
- **भारत के थाईलैंड से प्रमुख आयात:**
  - » **प्लास्टिक कच्चे माल:** $915 मिलियन
  - » **इलेक्ट्रॉनिक घटक:** $895 मिलियन
  - » **वनस्पति तेल:** $523 मिलियन
- थाईलैंड भारत का 27वां सबसे बड़ा निवेशक है, जिसमें कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) $1.39 बिलियन (अप्रैल 2022-सितंबर 2023) है। भारतीय कंपनियाँ जैसे टाटा स्टील और टीसीएस ने थाईलैंड में मजबूत उपस्थिति स्थापित की है, जबकि थाई कंपनियाँ भारत के कृषि-प्रसंस्करण, निर्माण और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में निवेश करती हैं।

संयोजकता परियोजनाएँ:

- **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग:** दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार और पर्यटन को बढ़ाता है।
- **दावेई परियोजना:** म्यांमार में दावेई डीप-सी पोर्ट को चेन्नई से जोड़ता है, जिससे भीड़भाड़ वाले मलक्का जलडमरूमध्य का विकल्प प्रदान करता है।

रक्षा सहयोग:

- संवाद में थाईलैंड की रक्षा अधिग्रहण योजनाओं का समर्थन करने में भारत के घरेलू रक्षा उद्योग की संभावनाओं पर जोर दिया। थाईलैंड के प्रतिनिधिमंडल ने डीआरडीओ मुख्यालय का भी दौरा किया ताकि रक्षा अनुसंधान और संयुक्त उत्पादन में सहयोगी अवसरों की खोज की जा सके।

द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियाँ:

- **व्यापार असंतुलन:** भारत के निर्यात ($5.71 बिलियन) थाईलैंड से इसके आयात ($11.19 बिलियन) से कम हैं (2022-23)।
- **तकनीकी बाधाएँ:** कठोर मानक और प्रमाणन प्रक्रियाएँ विशेष रूप से समुद्री और पोल्ट्री उत्पादों के लिए व्यापार में बाधा डालती हैं।
- **बुनियादी ढांचे की कमी:** अपर्याप्त लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग बुनियादी ढांचा दक्षता में बाधा डालता है।

आसियान और क्षेत्रीय सहयोग:

- आसियान में थाईलैंड की रणनीतिक भूमिका इसे भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। आसियान, $10.2 ट्रिलियन की संयुक्त जीडीपी के साथ, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है। एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) जैसी पहल के माध्यम से सहयोग भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आसियान के लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है।

भारत-इंडोनेशिया संबंध: ऐतिहासिक और रणनीतिक अवलोकन

भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधों ने ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों को एक मजबूत द्विपक्षीय संबंध विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि, सहयोग की संभावनाओं के बावजूद, यह संबंध समय के साथ बदलते भू-राजनीतिक संदर्भों और नेतृत्व प्राथमिकताओं से प्रभावित होकर उतार-चढ़ाव वाला रहा है। जनवरी 2025 में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिंतो की भारत यात्रा, दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक नया अध्याय है।

भारत-इंडोनेशिया संबंधों की ऐतिहासिक नींव:

- **औपनिवेशिक विरोधी समर्थन:** प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने डच औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। भारत ने डच एयरलाइनों को भारतीय हवाई क्षेत्र से प्रतिबंधित करने और डच शिपिंग का बहिष्कार करने जैसे उपाय किए, और इंडोनेशियाई नेताओं सुतान शाहरीर और मोहम्मद हट्टा को निकालने में भी मदद की।
- **औपचारिक राजनयिक संबंध:** 1950 में, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो की भारत यात्रा के साथ दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए। 1951 की मैत्री संधि ने भारत और इंडोनेशिया के बीच शाश्वत शांति और मित्रता के संबंधों को मजबूत किया। दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख सदस्य थे और 1955 के बांडुंग सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिसने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच एकता को मजबूत किया था।

सबंधो में तनाव (1960–1970 दशक):

- **भू-राजनीतिक तनाव:** 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भारत की चीन के प्रति बढ़ती सतर्कता और 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में इंडोनेशिया द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण भारत-इंडोनेशिया संबंधों में तनाव बढ़ गया था।
- **राजनीतिक तनाव:** सुकर्णो की कट्टरपंथी विदेश नीति और जवाहरलाल नेहरू के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में इस तनाव को कम करने के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ी। इंडोनेशिया में राजनीतिक परिवर्तन और जनरल सुहार्तो के सत्ता में आने के बाद, इंडोनेशिया की विदेश नीति में बदलाव आया और भारत के साथ संबंधों में सुधार हुआ।

1990 का दशक: जुड़ाव का एक नया युग

- **भारत की 'लुक ईस्ट' नीति:** 1990 के दशक में भारत के आर्थिक उदारीकरण और सोवियत संघ के पतन के बाद, भारत ने अपनी 'लुक ईस्ट' नीति को अपनाया जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना था। आसियान का एक प्रमुख सदस्य, इंडोनेशिया इस नीति का एक महत्वपूर्ण भागीदार बना।
- **'एक्ट ईस्ट' नीति:** 21वीं सदी की शुरुआत में, भारत ने अपनी लुक ईस्ट नीति का विस्तार करते हुए एक्ट ईस्ट नीति को अपनाया। इस नीति के तहत भारत ने इंडोनेशिया के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत किया।

समकालीन संबंध: एक व्यापक साझेदारी

- **व्यापार और आर्थिक सहयोग:** भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। 2005 में 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में यह 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। हालांकि, 2023-24 में व्यापार घाटे को संतुलित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए व्यापार का अनुमान लगभग 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगाया गया है।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और एक नियम-आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। बढ़ते चीनी प्रभाव के बीच, दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास और रक्षा समझौते हुए हैं।
- **सांस्कृतिक और जन-संपर्क:** भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में लगभग 700,000 भारतीय पर्यटक इंडोनेशिया गए। दोनों देश 2025 को इंडो-आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की योजना बना रहे हैं। भारत इंडोनेशिया के प्रसिद्ध मंदिरों, प्रम्बनन और बोरोबुदुर के संरक्षण में भी मदद कर रहा है।

2025 की राजकीय यात्रा व बैठक के मुख्य बिंदु:

- जनवरी 2025 में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिंतो की राजकीय यात्रा, जहां वे भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर उच्च स्तरीय चर्चाएं हुई और पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता भी शामिल है।
- **साझेदारी को मजबूत करना:** राष्ट्रपति सुबिंतो ने भारतीय नेतृत्व की प्रशंसा की और विशेष रूप से आर्थिक संबंधों और रक्षा सहयोग को गहरा करने पर जोर दिया।

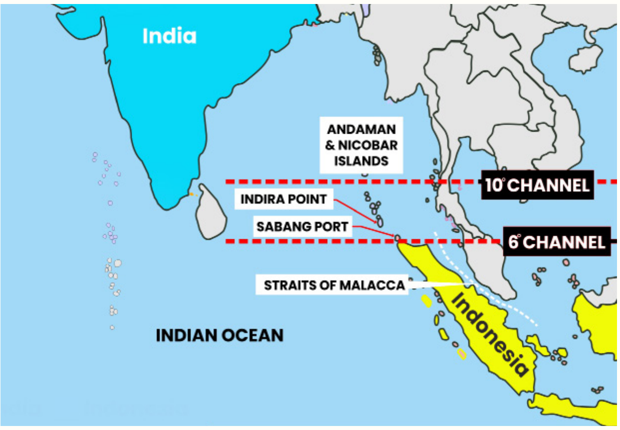

भारत–इंडोनेशिया के मुख्य सहयोग क्षेत्र:

- **रक्षा और सुरक्षा:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र दोनों देशों के लिए रणनीतिक महत्व रखता है, जिसके कारण समुद्री सुरक्षा सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है। भारत और इंडोनेशिया ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं और अपने रक्षा उद्योग सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि, यात्रा के दौरान ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री पर कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन दोनों देशों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं और तकनीकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा सहयोग पर चर्चा जारी रखने की इच्छा व्यक्त की।
- **आर्थिक सहयोग:** भारत और इंडोनेशिया के बीच आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, दोनों देश व्यापार को सुगम बनाने के लिए नौकरशाही बाधाओं को कम करने और नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए काम कर रहे हैं। जहां भारत का लक्ष्य इंडोनेशिया को निर्यात बढ़ाना है, वहीं इंडोनेशिया ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भारतीय निवेश में रुचि दिखाई है।
- **सांस्कृतिक और जन-संपर्क:** भारत-इंडोनेशिया संबंधों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2023 में लगभग 700,000 भारतीय पर्यटक इंडोनेशिया गए, अनुमानों से पता चलता है कि यह संख्या एक मिलियन तक पहुंच सकती है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2025 को इंडो-आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा, भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हिंदू प्रम्बनन मंदिर के संरक्षण में इंडोनेशिया की सहायता कर रहा है, साथ ही बौद्ध बोरोबुदुर मंदिर में भी काम जारी है।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** दोनों देश जी-20, आसियान और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों के महत्व को मान्यता देते हैं, जहां वे साझी भू-राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। इस यात्रा ने भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते त्रिपक्षीय सहयोग को भी रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है।

भारत–इंडोनेशिया संबंधों का भविष्य:

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक परिवर्तनों के मद्देनजर भारत-इंडोनेशिया साझेदारी और मजबूत होती जा रही है। दोनों देश क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रपति सुबिंतो की यात्रा के दौरान स्थापित ट्रैक 1.5 संवाद तंत्र दोनों देशों के राजनीतिक, व्यावसायिक और अकादमिक नेताओं के बीच गहन बातचीत का एक मंच प्रदान करेगा।
- इस रणनीतिक साझेदारी का भविष्य निरंतर संवाद पर निर्भर करेगा, विशेषकर रक्षा, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में। दोनों देशों को अपने रक्षा उद्योग सहयोग की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जो उनके संबंधों में एक अप्रयुक्त संभावना है।

पहली भारत-मलेशिया सुरक्षा वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मलेशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महानिदेशक राजा डाटो नुशीरवान बिन जैनल आबिदीन ने संयुक्त रूप से पहली भारत-मलेशिया सुरक्षा वार्ता की सह-अध्यक्षता की। यह वार्ता द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण विकास है, जिसमें आतंकवाद पर सहयोग, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों सहित साझी वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान पर चर्चा की गयी।

वार्ता के फोकस क्षेत्र:

- वार्ता के केंद्रबिंदु क्षेत्र में आतंकवाद के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद का मुकाबला और उग्रवाद का निवारण करना था।
- दोनों देशों ने इस खतरे से निपटने के लिए सहयोगात्मक उपायों के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना और समुद्री सुरक्षा बढ़ाना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया गया।
- इस सुरक्षा वार्ता से रक्षा, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जोकि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

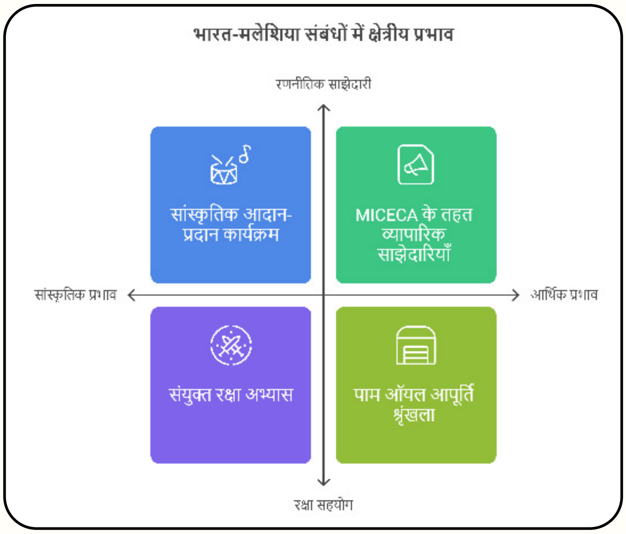

भारत–मलेशिया संबंधों के बारे में:

- भारत और मलेशिया के बीच राजनयिक संबंध 1957 में स्थापित हुए थे। विगत वर्षों में, व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में संबंध मजबूत हुए हैं।
- **आर्थिक संबंध:** वित्त वर्ष 2023-24 में, द्विपक्षीय व्यापार 20.01 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिससे मलेशिया भारत का 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। मलेशिया-भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (एमआईसीईसीए), स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और केंद्रीय बैंक साझेदारी जैसी प्रमुख पहलों ने इन संबंधों को बढ़ावा दिया है।
- **पाम ऑयल राजनीति:** मलेशिया भारत को प्रतिवर्ष लगभग तीन मिलियन मीट्रिक टन ताड़ के तेल का निर्यात करके भारत के खाद्य तेल बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही, मलेशिया अनुसंधान एवं विकास तथा बीज आपूर्ति के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को सहायता प्रदान करता है।
- **रक्षा सहयोग:** संयुक्त उद्यम, हथियारों की खरीद और सैन्य प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग से भारत और मलेशिया के बीच रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। मलेशिया-भारत रक्षा सहयोग समिति (एमआईडीसीओएम) की वार्षिक बैठकें इस सहयोग को और गहरा बनाती हैं। 2023 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने कुआलालंपुर में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करके इस संबंध को और मजबूत किया है।
- **जन-से-जन संपर्क:** मलेशिया दो मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का घर है, जिससे सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंधो को बढ़ावा मिलता है।

भारत–मलेशिया संबंधों में चुनौतियाँ:

- **कमजोर आर्थिक सहयोग:** द्विपक्षीय व्यापार मलेशिया-चीन व्यापार संबंधों की तुलना में मामूली है, जबकि भारत के निर्यात प्रतिबंधों ने मलेशिया की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किया है।
- **रक्षा भू-राजनीति:** मलेशिया द्वारा भारत के तेजस के बजाय दक्षिण कोरिया के एफए-50 जेट का चयन करने से रक्षा सौदों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **राजनीतिक तनाव:** कश्मीर और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे मुद्दों पर असहमति के कारण तनाव पैदा हुआ है।
- **प्रत्यर्पण मुद्दे:** जाकिर नाइक को प्रत्यर्पित करने से इनकार करने से मलेशिया में तनाव संबंधो में तनाव रहता है।
- **चीन संबंध:** दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ मलेशिया की मौन कूटनीति भारत के लिए चुनौतियां पैदा करती है।
- **श्रम शोषण:** मलेशिया में भारतीय प्रवासी श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार की चिंताएं बनी हुई हैं।

भारत द्वारा संबंधों को मजबूत करने के लिए पहल:

- **तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी):** भारत मलेशियाई नागरिकों के लिए 100 वार्षिक सीटें आवंटित करता है, जिससे शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलता है।
- **एमआईसीईसीए:** मंच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करता है।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** कुआलालंपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सांस्कृतिक केंद्र भारतीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।
- **वित्तीय संपर्क:** भारत का यूपीआई भुगतान सिस्टम मलेशिया ने भी अपनाया है जिससे वित्तीय लेनदेन का आधुनिकीकरण होता है।

आठवां हिंद महासागर सम्मेलन

सन्दर्भ:

हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मस्कट, ओमान में आयोजित आठवें हिंद महासागर सम्मेलन (IOC) को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती भू-राजनीतिक चुनौतियों और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की। यह सम्मेलन भारत, सिंगापुर और ओमान की साझेदारी में आयोजित किया गया, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

संबोधित मुद्दे:

- **भू-राजनीतिक अस्थिरता:** विदेश मंत्री ने पश्चिम एशिया और हिंद-प्रशांत दोनों में अस्थिरता पर प्रकाश डाला। पश्चिम एशिया में संघर्षों और हिंद-प्रशांत में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक शिपिंग में व्यवधान पर जोर दिया गया, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने और यथास्थिति में एकतरफा बदलाव से बचने का आह्वान किया गया।
- **समझौतों का पालन:** उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए राष्ट्रों द्वारा समझौतों का पालन करने और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया।
- **तटीय राज्यों के लिए चुनौतियाँ:** हिंद महासागर में द्वीप राष्ट्रों

द्वारा सामना की जाने वाली संसाधन बाधाओं, ऋण बोझ और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की चुनौतियों का मुद्दा उठाया गया। ये जटिलताएँ अनन्य आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) की निगरानी और अवैध गतिविधियों को रोकने के प्रयासों को प्रभावित करती हैं।

- **कनेक्टिविटी का पुनर्निर्माण:** औपनिवेशिक व्यवधानों के बाद पुनर्निर्माण और क्षेत्र के सभी देशों के लिए समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी और समावेशी कनेक्टिविटी पहलों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** अवैध तस्करी, आतंकवाद और हिंद महासागर में मछली पकड़ने के हितों की सुरक्षा के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गईं। इन महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग का आह्वान किया गया।

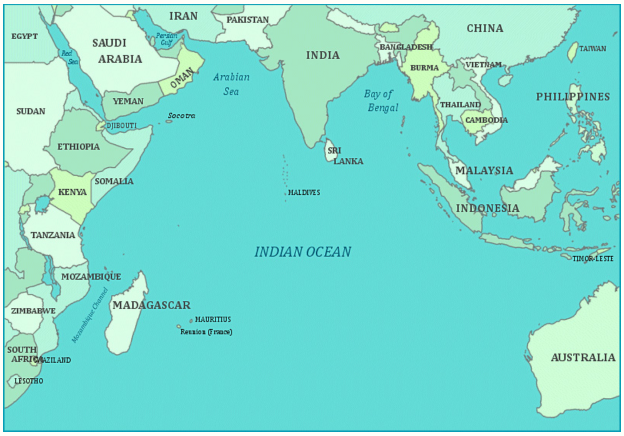

हिंद महासागर का महत्व:

- **सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत जुड़ाव:** भू-राजनीतिक 'इंडो-पैसिफिक' के विपरीत, हिंद महासागर एक अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं। यह 26 देशों के तटों तक फैला हुआ है और नेपाल व भूटान जैसे भूमिबद्ध (landlocked) देशों के लिए जीवनरेखा का कार्य करता है, जिससे वे वैश्विक व्यापार से जुड़े रहते हैं।
- **आर्थिक महत्व:** हिंद महासागर एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है, जो दुनिया के 70% कंटेनर यातायात को संभालता है। यह भारत के 80% बाहरी व्यापार और 90% ऊर्जा व्यापार को सुगम बनाता है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक केंद्र बन जाता है।
- **सामरिक महत्व:** हिंद महासागर का सामरिक महत्व भी है, क्योंकि यहां सैन्य और वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी वैश्विक शक्तियां इस क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति बनाए हुए हैं, और चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से निवेश कर रहा है।
- **भारत द्वारा समुद्री प्रभाव को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम:** 2015 में, भारत ने अपने समुद्री प्रभाव को बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) पहल शुरू की।

प्रमुख चिंताएँ:

- भारत को इस क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें समुद्री डकैती, आतंकवाद, अवैध मछली पकड़ना और मानव तस्करी शामिल हैं। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर में वृद्धि और समुद्री संचार नेटवर्क में हुवावे जैसी चीनी कंपनियों के प्रभाव जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय समुद्री नेतृत्व का आह्वान:

- अल्फ्रेड सिद्धांत के अनुसार, हिंद महासागर पर नियंत्रण सीधे वैश्विक प्रभाव के बराबर है। आईओसी (Indian Ocean Conference) क्षेत्रीय नेताओं के लिए इस 'शांति के क्षेत्र' के हितों की रक्षा करने के लिए एक आवश्यक मंच के रूप में कार्य करता है।

भारत और अन्य

भारत-जमैका संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जमैका के प्रधानमंत्री डॉ. एंड्रयू होल्नेस ने 30 सितंबर से 3 अक्टूबर, 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे।

यात्रा के प्रमुख निष्कर्षः

- भारत ने नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम 'जमैका मार्ग' रखा, जो दोनों देशों की गहरी होती मित्रता का प्रतीक है।
- डॉ. होल्नेस की यात्रा की मुख्य उपलब्धियों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर शामिल थे।

महत्वपूर्ण समझौतेः

- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर समझौताः** दोनों देशों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहलों को साझा करने पर सहमति व्यक्त की।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर समझौताः** 2024-2029 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान का समझौता किया गया, जो दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगा।
- **खेल सहयोग पर समझौताः** खेल के क्षेत्र में, विशेषकर क्रिकेट में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता किया गया।
- **यूपीआई प्रणाली पर समझौताः** भारत की एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और जमैका की ईगव के बीच यूपीआई प्रणाली के एकीकरण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समझौता किया गया।

भारत–जमैका संबंधों का संक्षिप्त विवरणः

- दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 12 अगस्त 1962 को स्थापित हुए थे और 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की यात्रा के बाद 1976 में किंग्स्टन में भारत का स्थायी मिशन खोला गया।
- **व्यापारः** भारत, जमैका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2020-21 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 82.40 मिलियन डॉलर था।
- **शिक्षाः** भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के माध्यम से भारत, जमैकन छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
- **स्वास्थ्य सेवाः** भारत ने जमैका के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्षमता निर्माण और मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधः

- भारत और जमैका के सांस्कृतिक संबंध उनके उपनिवेशी इतिहास और लोकतांत्रिक मूल्यों की साझा प्रतिबद्धता से जुड़े है। क्रिकेट के प्रति दोनों देशों की गहरी रुचि भी उनके संबंधों में एक विशेष तत्व जोड़ती है, जिससे आपसी सौहार्द और मैत्री का माहौल बनता है।

प्रवासी समुदायः

- जमैका में लगभग 70,000 भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो दोनों देशों मध्य व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करते हैं और आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देते हैं।

भारत-नाइजीरिया सामरिक साझेदारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया की यात्रा पूरी की, जोकि 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नाइजीरिया यात्रा थी। यह यात्रा प्रधानमंत्री की तीन देशों की यात्रा का हिस्सा थी, जिसमें 17 से 21 नवंबर, 2024 तक ब्राजील और गुयाना का दौरा भी शामिल था।

नाइजीरिया यात्रा से मुख्य बिंदुः

- **सामरिक साझेदारीः** भारत और नाइजीरिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया है, जिसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। यह कदम दोनों देशों के बीच सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए उठाया गया है।

- **मानवीय सहायता:** नाइजीरिया में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान, भारत ने 20 टन मानवीय सहायता की घोषणा की। यह सहायता नाइजीरिया में राहत प्रयासों को मजबूत करने के लिए थी और संकट के समय भारत की सहायता की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** दोनों देशों ने सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख समझौतों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिनमें:
  - » सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
  - » सीमा शुल्क सहयोग
  - » सर्वेक्षण सहयोग इन समझौतों से दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की स्थापना होगी।
- **वैश्विक दक्षिण सहयोग:** प्रधानमंत्री मोदी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति टीनूबू ने वैश्विक दक्षिण की विकास आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने हेतु सहयोग की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने साझा वैश्विक चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए एक समावेशी वैश्विक व्यवस्था बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।

प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान:

- प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए नाइजीरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर (GCON) से सम्मानित किया गया।

भारत–नाइजीरिया संबंधों के बारे में:

- **ऐतिहासिक संबंध:** भारत ने अफ्रीकी देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने 1958 में अफ्रीका में अपना राजनयिक मिशन स्थापित किया था, जोकि 1960 में नाइजीरिया के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने से दो साल पहले था।
- **सैन्य और क्षमता निर्माण:** स्वतंत्रता के बाद, भारत ने नाइजीरिया को नाइजीरियाई रक्षा अकादमी (NDA) और पोर्ट हरकोर्ट में नौसेना कॉलेज जैसे सैन्य संस्थानों की स्थापना में सहायता की। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) पहल के तहत भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 1964 से नाइजीरिया की रक्षा और नागरिक क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण रहे हैं।
- **वाणिज्यिक संबंध:** भारतीय व्यवसायों ने नाइजीरिया में लगभग 15 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, जिससे भारत नाइजीरिया का अग्रणी निवेशक बन गया है, जिसका कुल निवेश आधार लगभग 20 बिलियन डॉलर है।
- **तेल व्यापार:** नाइजीरिया भारत को कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है, हालाँकि हाल के वर्षों में इसकी हिस्सेदारी कम हो गई है। 2020 में, नाइजीरिया भारत को कच्चे तेल का पाँचवाँ सबसे बड़ा विक्रेता था।
- **अफ्रीका में भारत की भूमिका:** चीन और अमेरिका के बाद भारत अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अफ्रीका के कुल व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 6.4% है।

भारत-कैरिकॉम संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जटाउन, गुयाना में आयोजित दूसरे भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और कैरेबियाई समुदाय (कैरिकॉम) के बीच साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए सात प्रमुख स्तंभों का प्रस्ताव रखा। यह शिखर सम्मेलन, जो 50 वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की गुयाना की पहली यात्रा थी, व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित था।

भारत–कैरिकॉम साझेदारी के बारे में:

- कैरिकॉम 15 कैरेबियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जो विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देता है।
- पहला भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 2003 में हुआ था, जिसने सहयोग के लिए मंच तैयार किया और 2024 में दूसरा शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय जुड़ाव में एक उन्नत चरण को चिह्नित करता है।

प्रधानमंत्री मोदी के सात प्रमुख स्तंभ:

- **व्यापार:** मोदी ने भारत और कैरिबियन के बीच व्यापार संबंधों को गहरा करने और एक मजबूत व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने, बाधाओं को कम करने और नए व्यापार मार्ग खोलने पर जोर दिया।
- **प्रौद्योगिकी:** आईसीटी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचे में भारत के नेतृत्व का लाभ उठाते हुए, मोदी ने कैरिकॉम देशों में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारत के तकनीकी संसाधनों का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा।
- **पर्यटन:** कैरिबियन के लिए पर्यटन एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र

है, मोदी ने भारत के बढ़ते यात्रा बाजार को बढ़ावा देने और कनेक्टिविटी में सुधार करने सहित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तालमेल को बढ़ावा देने का सुझाव दिया।

- **प्रतिभा:** मोदी ने दोनों क्षेत्रों के बीच कौशल और प्रतिभा के आदान-प्रदान का प्रस्ताव रखा, जिससे शैक्षिक आदान-प्रदान, व्यावसायिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की सुविधा मिल सके।
- **परंपरा:** कैरिबियन में भारतीयों के प्रवास के कारण गहरे सांस्कृतिक संबंधों को पहचानते हुए, मोदी ने पारंपरिक बंधनों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ाने का आह्वान किया।
- **लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई):** मोदी ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पिछली भारत-कैरिकॉम बैठक से मिले 1 मिलियन डॉलर के अनुदान के आधार पर एसएमई सहयोग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का प्रस्ताव रखा।
- **कृषि और खाद्य सुरक्षा:** कृषि में भारत की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, मोदी ने ज्ञान के आदान-प्रदान और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैरिबियन में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग पर जोर दिया।

भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन का महत्व:

इस शिखर सम्मेलन ने कैरिबियन के रणनीतिक महत्व के प्रति भारत की बढ़ती मान्यता को प्रदर्शित किया। प्रमुख लाभों में शामिल हैं:

- **आर्थिक सहयोग:** व्यापार, प्रौद्योगिकी और एसएमई संबंधों को मजबूत करने से भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार खुलते हैं और निवेश को बढ़ावा मिलता है।
- **स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स:** किफायती स्वास्थ्य सेवा और टीकों में भारत की विशेषज्ञता कैरिबियन की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।
- **अक्षय ऊर्जा:** भारत की 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन के माध्यम से सतत ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग जारी रहेगा।
- **आपदा प्रबंधन:** मानवीय सहायता और आपदा राहत में भारत की विशेषज्ञता कैरिकॉम देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया है।
- **सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदान:** आदान-प्रदान बढ़ने से लोगों के बीच संबंध मजबूत होंगे तथा आपसी समझ को बढ़ावा मिलेगा।

क्षेत्रीय समूह

कजान शिखर सम्मेलन और ब्रिक्सः बहुपक्षवाद का एक नया युग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रूस के कजान में विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु बहुपक्षीय सहयोग पर केंद्रित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य परिणाम 'कजान घोषणा' रही, जोकि एक व्यापक दस्तावेज के रूप में उभरी। यह घोषणा सदस्य देशों के बीच सहयोग के महत्व को रेखांकित करती है और वैश्विक मामलों में एकीकृत दृष्टिकोण को व्यक्त करती है।

- घोषणा में 'न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना' विषय पर विशेष बल दिया गया है। इसमें शांति के संवर्धन, एक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना तथा सतत विकास पहलों को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धताओं को प्रमुखता दी गई है।
- रूस ने 2022 से रूसी बैंकों पर लागू प्रतिबंधों के संदर्भ में स्विफ्ट नेटवर्क के विकल्प के रूप में ब्रिक्स के नेतृत्व वाली भुगतान प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसके अतिरिक्त सम्मलेन में पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष पर भी चर्चा की गयी।
- शिखर सम्मेलन के दौरान, ब्रिक्स राष्ट्रों ने ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज और ब्रिक्स (पुनः) बीमा कंपनी की स्थापना जैसी अभिनव पहलों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इसके अतिरिक्त, शिखर सम्मेलन में एक नई 'ब्रिक्स भागीदार देश' श्रेणी की शुरुआत की गई, जिससे अन्य राष्ट्र ब्रिक्स के साथ सहयोगी परियोजनाओं में शामिल हो सकें।
- वैक्सीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ब्रिक्स आरएंडडी वैक्सीन केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस के लिए भारत के प्रस्ताव को भी एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में स्वीकार किया गया।

ब्रिक्सः

- ब्रिक्स, जिसका अर्थ है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का गठबंधन है। 'ब्रिक' शब्द को पहली बार 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओशनील ने इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए पेश किया।
- 2009 में औपचारिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत के बाद, 2010 में दक्षिण अफ्रीका का शामिल होना ब्रिक्स के विस्तार को दर्शाता है। हाल ही में, गठबंधन का विस्तार करते हुए अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को शामिल किया गया है।
- ब्रिक्स वैश्विक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण इकाई है, जोकि दुनिया की लगभग 41% आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 16% प्रतिनिधित्व करती है।

भारत के लिए ब्रिक्स का महत्वः

- ब्रिक्स, विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है, जिससे वे वैश्विक संस्थाओं में अपने विषय रख सकते हैं। यह भारत के लिए एक समानांतर विकल्प के रूप में कार्य करता है, जिससे पश्चिमी शक्तियों पर निर्भरता कम होती है।
- ब्रिक्स आर्थिक सहयोग और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देता है, जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के माध्यम से भारत के विकास लक्ष्यों के अनुरूप बुनियादी ढाँचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन मुहैया कराया जाता है।

चुनौतियाँः

- ब्रिक्स को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें विभिन्न राष्ट्रीय एजेंडों का समावेश शामिल है। आतंकवाद और सीमा सुरक्षा के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण हमेशा अन्य सदस्यों, विशेष रूप से चीन और रूस की प्राथमिकताओं के साथ मेल नहीं पाता, क्योंकि ये देश अपने भू-राजनीतिक हितों पर केन्द्रित रहते हैं।
- ब्रिक्स के भीतर चीन का बढ़ता प्रभाव, विशेष रूप से ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों के शामिल होने से, संभावित रूप से चीन समर्थक रुख की ओर झुकाव की चिंताएँ उत्पन्न कर रहा है।
- मध्य पूर्वी देशों का समावेश भारत के कूटनीतिक संबंधों को जटिल बना सकता है। अंतर-ब्रिक्स व्यापार भी टैरिफ, विनियामक विसंगतियों और मुद्रा संबंधी मुद्दों के कारण बाधित है, जिससे भारत को इस समूह के भीतर व्यापार के अवसरों का पूर्ण लाभ उठाने में कठिनाई होती है।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इस्लामाबाद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और सहयोग को बढ़ावा देने और सामूहिक विकास से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस शिखर सम्मेलन में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस सहित अन्य देशों ने भाग लिया।

एससीओ 2024 बैठक की मुख्य बिंदु:

क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग पर विमर्श:

- **क्षेत्रीय विश्वास और सहयोग:** शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच विश्वास और सहयोग के महत्व को रेखांकित किया गया। सीमा पार आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियों और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसी क्षेत्रीय पहलों पर चर्चा हुई, जिसे भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन मानता है।
- **प्रमुख चुनौतियाँ:** शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए एससीओ की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई, जो क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापार और कनेक्टिविटी में बाधा डालती हैं।
- **बहुपक्षीय सुधार का आह्वान:** भारत ने विकासशील देशों का अधिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ाने के लिए वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाओं, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

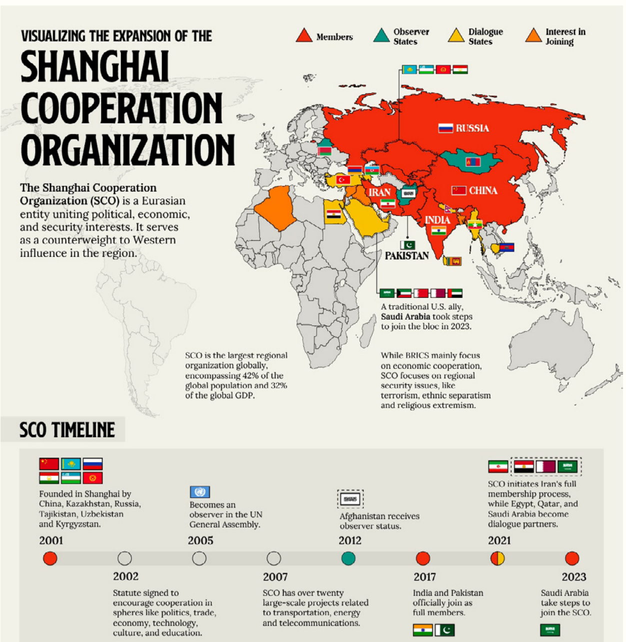

क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क:

- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। इस बात पर जोर दिया गया कि आपसी सम्मान और संप्रभुता पर आधारित वास्तविक साझेदारी, एससीओ क्षेत्र के भीतर व्यापार, ऊर्जा प्रवाह और कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है।

भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंध

- **वार्ता की बहाली:** शिखर सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी वार्ता की बहाली थी। इन वार्ताओं में दोनों देशों के बीच विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
- इसमें सांस्कृतिक और खेल आदान-प्रदान को पुनर्जीवित करने की संभावना पर भी चर्चा की गई। विशेष रूप से, आगामी क्षेत्रीय आयोजनों में सहयोगी भागीदारी की संभावना पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें पाकिस्तान द्वारा फरवरी 2025 में आयोजित की जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी शामिल है।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के बारे में:

- जून 2001 में शंघाई, चीन में स्थापित एससीओ एक प्रमुख अंतर-सरकारी संगठन है जिसके 10 सदस्य देश हैं: चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस।
- प्रारंभ में पांच देशों 'कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान' द्वारा गठित एससीओ का ध्यान क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और सीमा पर सैनिकों की संख्या में कटौती पर केंद्रित था।
- संगठन ने समय के साथ अपनी सदस्यता का विस्तार किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2017 में, ईरान 2023 में और बेलारूस 2024 में शामिल हुए। एससीओ के उद्देश्यों में क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है।

19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लाओस के विएंतियाने में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस शिखर सम्मेलन ने भारत को अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताओं को सशक्त रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, जिसमें शांतिपूर्ण संघर्षों का समाधान, आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन और क्षेत्रीय साझेदारी को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत की भागीदारी की मुख्य बातें

- **विकासोन्मुख हिंद-प्रशांत:** भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए विकास-केंद्रित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया, जिसमें क्षेत्रीय विकास और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर जोर दिया गया।

- **नालंदा विश्वविद्यालय के लिए समर्थनः** भारत ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की और ईएएस सदस्य देशों को उच्च शिक्षा प्रमुखों के सम्मेलन में आमंत्रित किया। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है।
- **वैश्विक चुनौतियांः** भारत ने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा खतरों और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की तथा संवाद-आधारित संघर्ष समाधान के महत्व पर बल दिया।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) क्या है?

- 2005 में स्थापित, ईएएस एक क्षेत्रीय मंच है जोकि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 18 देशों को एक मंच प्रदान करता है।
- यह समावेशिता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान और आसियान केंद्रीयता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके सदस्य 10 आसियान देश और आठ संवाद साझेदार (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका) हैं।

ईएएस का महत्वः

- **आर्थिक प्रभावः** ईएएस सदस्य विश्व की 53% आबादी और वैश्विक जीडीपी के 60% का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत आसियान का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और भारत-आसियान व्यापार 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है।
- **सामरिक सहयोगः** ईएएस भारत की एक्ट ईस्ट नीति का समर्थन करता है, जिससे भारत-म्यांमार-थाईलैंड राजमार्ग और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट जैसी परियोजनाओं के माध्यम से दक्षिण-पूर्व एशिया में कनेक्टिविटी बढ़ती है।
- **सांस्कृतिक संबंधः** भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच बौद्ध धर्म के माध्यम से सांस्कृतिक संबंध मजबूत हुए हैं, जिससे क्षेत्रीय सद्भाव को बल मिलता है।

वैश्विक शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता :

- **संघर्ष समाधानः** भारत ने इस बात पर बल दिया कि यूरेशिया और पश्चिम एशिया सहित वैश्विक संघर्षों का समाधान युद्ध से नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए।
- **समुद्री सुरक्षाः** भारत ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत की आवश्यकता पर जोर दिया और समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) के तहत समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की
- **क्षेत्रीय सहयोगः** ईएएस में भारत की भागीदारी हिंद-प्रशांत में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

आसियान-भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की छठी बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आसियान-भारत माल व्यापार समझौता (AIFTA) संयुक्त समिति की छठी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करना है।

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते के बारे में :

- आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए) भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया एक महत्त्वपूर्ण समझौता है।

पृष्ठभूमिः

- आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र (एआईएफटीए) की शुरुआत अक्टूबर 2003 में हस्ताक्षरित रूपरेखा समझौते के साथ हुई। इस समझौते ने वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के व्यापार को सम्मिलित किया। एआईटीआईजीए 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ।
- **प्रमुख प्रावधानः** समझौते का उद्देश्य आसियान और भारत के बीच व्यापार होने वाले 76.4% वस्तुओं पर शुल्क कम करना या समाप्त करना है।

समीक्षा प्रक्रियाः

- सितंबर 2022 में दोनों पक्षों ने इस समझौते की समीक्षा शुरू की।
- समीक्षा का उद्देश्य व्यापार को अधिक सुविधाजनक बनाना है, जिसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

उप-समितियाँः

- आठ उप-समितियाँ गठित की गई हैं, जोकि बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियम और व्यापार उपचार जैसे क्षेत्रों पर कार्य कर रही हैं।
- **द्विपक्षीय व्यापारः** आसियान-भारत व्यापार 2023-24 में 122.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारतीय निर्यात में 9.96% और आयात में 34.30% की वृद्धि दर्ज की गई।

आसियानः

- **स्थापनाः** इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में

इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा की गई थी।

- **वर्तमान सदस्य देश:** वर्तमान में 'इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम' इस संगठन के सदस्य हैं। नवंबर 2022 में, आसियान ने पूर्वी तिमोर (तिमोर-लेस्ते) को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की और उच्च स्तरीय बैठकों में इसे पर्यवेक्षक का दर्जा दिया।

आसियान शिखर सम्मेलन:

- यह संगठन का सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय है। प्रथम शिखर सम्मेलन फरवरी 1976 में बाली, इंडोनेशिया में हुआ।
- वर्तमान में यह प्रतिवर्ष दो बार बैठक करता है।
- **महत्व:** आसियान एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है। इसके वार्ता साझेदारों में भारत, अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

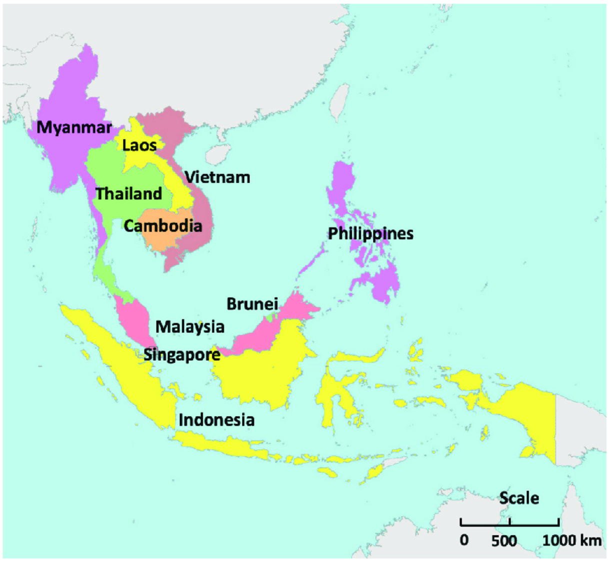

भारत–आसियान संबंध:

- **'एक्ट ईस्ट' नीति:** आसियान भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का केंद्रीय अंग है और विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ है। यह नीति क्षेत्रीय आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।
- **संबंधों का विकास:** 1992 में भारत-आसियान संबंध क्षेत्रीय वार्ता साझेदारी के रूप में शुरू हुए। 1995 में इन्हें पूर्ण वार्ता साझेदारी का दर्जा मिला। 2012 में इसे और सुदृढ़ कर रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत किया गया। 2022 में, इस साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) के रूप में उन्नत किया गया।
- **आर्थिक सहयोग और व्यापार लक्ष्य:** भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य 2025 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना है। वर्तमान में, आसियान भारत का पाँचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लाओस के वियनतियाने में 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) आयोजित की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लिया। एडीएमएम-प्लस आसियान देशों और उनके वार्ता साझेदारों के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।

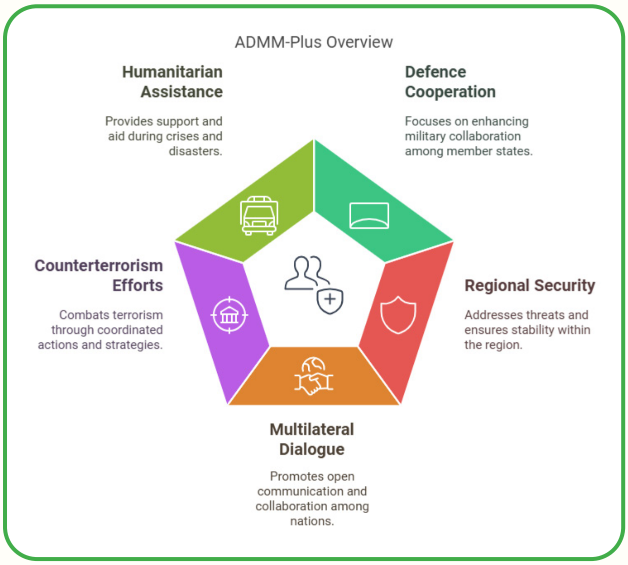

एडीएमएम–प्लस: क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग का एक प्रमुख मंच

- एडीएमएम-प्लस की स्थापना 2010 में आसियान सदस्य देशों और उनके आठ प्रमुख साझेदार देशों 'भारत, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड' के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी।
- यह मंच क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ आतंकवाद-निरोध, मानवीय सहायता, शांति स्थापना और समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- एडीएमएम-प्लस, भारत-प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीय संवाद, सहयोग और क्षेत्रीय साझेदारी के प्रति आसियान की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है और जटिल सुरक्षा चुनौतियों के समाधान में एक अहम भूमिका निभाता है।

एडीएमएम–प्लस में भारत के लिए फोकस के

प्रमुख क्षेत्रः

- **समुद्री सुरक्षाः** हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में अपनी रणनीतिक स्थिति को देखते हुए, भारत समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान देता है। प्रमुख क्षेत्रों में नौवहन की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन और समुद्री डकैती विरोधी उपाय शामिल हैं। भारत इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आसियान और उसके साझेदारों के साथ सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है।
- **आतंकवाद-विरोधीः** भारत लंबे समय से इस क्षेत्र में आतंकवाद-रोधी सहयोग को मजबूत करने का आह्वान करता रहा है। विशेष रूप से आतंकवाद के वित्तपोषण, कट्टरपंथ और सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है।
- **मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर):** भारत इस क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत में एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभरा है। आपदा प्रबंधन अभ्यासों और मानवीय मिशनों में भागीदारी, क्षेत्रीय मानव सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह सहयोग क्षेत्रीय देशों के बीच आपसी विश्वास और सहायता नेटवर्क को सुदृढ़ करता है।
- **साइबर सुरक्षाः** साइबर हमलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए, भारत एडीएमएम-प्लस के अंतर्गत साइबर सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने का समर्थन करता है। इसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में साइबर लचीलापन विकसित करना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

ए.डी.एम.एम.-प्लस का महत्वः

- क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करता है तथा इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है।
- यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और आपदा प्रतिक्रिया जैसी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- 11वें ADMM-प्लस में भारत की भागीदारी क्षेत्रीय और वैश्विक रक्षा सहयोग में एक प्रमुख देश के रूप में इसके बढ़ते महत्व को दर्शाती है। भारत, मलेशिया के साथ मिलकर आतंकवाद-निरोध पर ADMM-प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की सह-अध्यक्षता कर रहा है।

भारत और मनीला के बीच समुद्री सहयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और फिलीपींस के मध्य 14 दिसंबर 2024 को मनीला में पहली समुद्री वार्ता आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय समुद्री चुनौतियों का समाधान करना था। इस वार्ता का केंद्रीय विषय नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना था, जिसमें समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) का पालन सुनिश्चित करना शामिल है। यह वार्ता भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुई, जो एक लंबे और मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों ने समुद्रों के शांतिपूर्ण, सतत और समान उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

सहयोग के क्षेत्रः

- वार्ता में समुद्री उद्योग विकास, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान, महासागर अर्थव्यवस्था और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई।
- भारत और फिलीपींस ने नौसेना और तटरक्षक बल के बीच सहयोग बढ़ाने, समुद्री कानून प्रवर्तन, और क्षमता निर्माण पहलों पर चर्चा की।
- दोनों देशों ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों में साझा समुद्री उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग की इच्छा व्यक्त की, जिससे आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

भारत-फिलीपींस संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भः

- **राजनयिक संबंधः** भारत और फिलीपींस ने साल 1949 से राजनयिक संबंध बनाए रखे हैं और हाल के वर्षों में यह संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
- **द्विपक्षीय व्यापार वृद्धिः** द्विपक्षीय व्यापार 2015-16 में 1.89 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 2.84 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत फिलीपींस को दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
- **रक्षा सहयोगः** दोनों देश RIMPAC और ASEAN-India Maritime Exercise जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भाग लेते हैं। 2022 में, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें आपूर्ति कीं, जिससे रक्षा संबंध और मजबूत हुए।

सांस्कृतिक और तकनीकी संबंधः

- भारत और फिलीपींस के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान फल-फूल रहे हैं, जिसमें भारत के तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम का फिलीपींस को लाभ मिला है। दोनों देशों का अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) जैसे संस्थानों के माध्यम से निकट संबंध है।

हाल के विकास और चुनौतियां:

- **नए उभरते क्षेत्रों में सहयोग:**
  - » फिनटेक, अंतरिक्ष (फिलीपींस स्पेस एजेंसी और इसरो के बीच सहयोग) और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है।
- **साझा समुद्री सुरक्षा हित:**
  - » हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक राष्ट्रों के रूप में, भारत और फिलीपींस ने समुद्री सुरक्षा बनाए रखने में अपने हितों को संरेखित किया है।
  - » भारत की एक्ट ईस्ट नीति, जिसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया में जुड़ाव बढ़ाना है, ने फिलीपींस के साथ संबंध मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - » भारत ने दक्षिण चीन सागर पर फिलीपींस की स्थिति का समर्थन किया है और क्षेत्रीय समुद्री व्यवस्था में किसी भी एकतरफा बदलाव का विरोध किया है।

क्षेत्रीय चुनौतियां:

- बदलते शक्ति संतुलन के कारण हिंद-प्रशांत क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक भूमिका के कारण। इसी सन्दर्भ में भारत और फिलीपींस दोनों के लिए विवादित जल क्षेत्रों में संप्रभुता और नौवहन की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।

ब्रिक्स ब्लॉक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नाइजीरिया को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स ब्लॉक का 'सहयोगी देश' बनाया गया, जिसमें अब पूर्णकालिक सदस्यों के साथ नौ सहयोगी देश शामिल हैं।

ब्रिक्स ब्लॉक के बारे में:

- **स्थापना:** ब्रिक्स की औपचारिक स्थापना 2009 में हुई थी, शुरुआत में इसे ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) के रूप में जाना जाता था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, जिससे इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। यह समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था का 25% से अधिक और विश्व की लगभग 45% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।
- **मुख्यालय:** ब्रिक्स का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है और यह एक घूर्णन(रोटेशन) अध्यक्षता के आधार पर संचालित होता है।
- **पूर्णकालिक सदस्य:** इस ब्लॉक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं।
  - » 2023 में, ब्रिक्स का विस्तार हुआ जिसमें ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए। सऊदी अरब को भी आमंत्रित किया गया है लेकिन वह अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ है।
  - » 2025 में इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ।
- **सहयोगी देश:** सहयोगी देशों में नाइजीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

विकास:

- **2006:** जी8 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स का गठन हुआ।
- **2009:** रूस के येकातेरिनबर्ग में पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।
- **2010:** दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक्स का विस्तार हुआ।
- **2014:** ब्राजील के फोर्टालेजा में न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की स्थापना की गई।

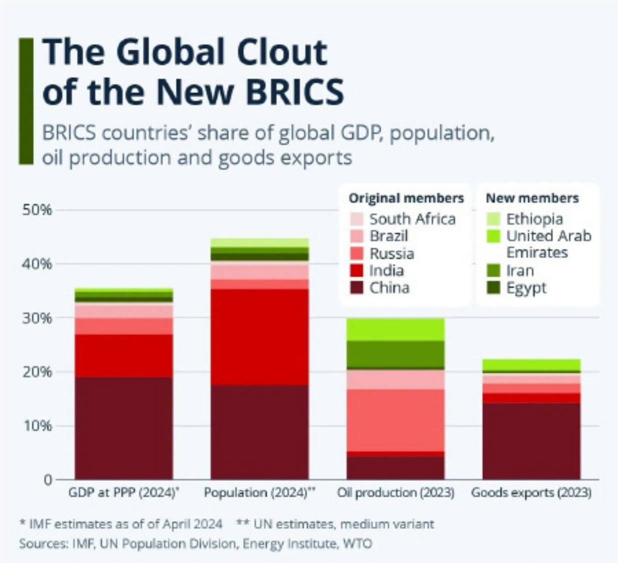

कार्य:

- **आर्थिक सहयोग:** सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना।
- **वैश्विक शासन सुधार:** संयुक्त राष्ट्र और आईएमएफ जैसे वैश्विक संस्थानों में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व का समर्थन करना।
- **विकास परियोजनाएं:** एनडीबी के माध्यम से बुनियादी ढांचे और सतत विकास पहलों के लिए धन जुटाना।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग:** वैश्विक चुनौतियों से सामूहिक रूप से निपटने के लिए विकासशील देशों के बीच गठबंधन को मजबूत करना।

ब्रिक्स की पहल:

- **आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए):** भुगतान संतुलन कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्य देशों को तरलता सहायता प्रदान करने के लिए $100 बिलियन तक की राशि का एक वित्तीय तंत्र।
- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी):** उभरते बाजारों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास के लिए संसाधन जुटाता है, जिसमें 96 परियोजनाओं के लिए $32.8 बिलियन की प्रतिबद्धता है।
- **ब्रिक्स भुगतान प्रणाली:** डॉलर आधारित भुगतान प्रणाली पर निर्भरता को कम करने के लिए विकल्प विकसित करना।

भारत के लिए ब्रिक्स का महत्वः

- **भू-राजनीतिः** ब्रिक्स भारत को अमेरिका और रूस-चीन धुरी के बीच अपने रणनीतिक हितों को संतुलित करने का एक मंच प्रदान करता है, जोकि वैश्विक भू-राजनीतिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **वैश्विक आर्थिक व्यवस्थाः** ब्रिक्स देश एक अधिक न्यायसंगत और संतुलित वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की वकालत करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधार के लिए एक सामान्य उद्देश्य साझा करते हैं, जोकि भारत को वैश्विक नीतियों को आकार देने में मदद करता है।
- **विकासशील देशों की आवाजः** ब्रिक्स वैश्विक दक्षिण की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, जोकि भारत को व्यापार और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर पश्चिमी नीतियों की चुनौतियों के बीच विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा करने का अवसर प्रदान करता है।
- **आतंकवाद विरोधी सहयोगः** ब्रिक्स भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है और मजबूत वैश्विक कार्रवाइयों की दिशा में काम करता है।
- **वैश्विक समूह और राजनयिक जुड़ावः** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) जैसी वैश्विक संस्थाओं में स्थायी सदस्यता हासिल करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ब्रिक्स मंच का उपयोग कर रहा है। यह मंच भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारने, द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने और अन्य सदस्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह में शामिल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंडोनेशिया ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स समूह में शामिल होने की घोषणा की है, जिससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं के इस गठ. बंधन का विस्तार हुआ है जिसमें रूस, चीन, ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। इंडोनेशिया अब आधिकारिक रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स (BRICS) का पूर्ण सदस्य (11वां) बन गया है। इस कदम को वैश्विक राजनीति में एक प्रवृत्ति के रूप में देखा जा रहा है जहां देश पश्चिमी वर्चस्व, विशेषकर आर्थिक मामलों में, का मुकाबला करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

इस समूह में शामिल होने के पीछे के कारणः

- **वैश्विक शासन को मजबूत करनाः** इंडोनेशिया वैश्विक शासन में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए ब्रिक्स में शामिल हो रहा है, क्योंकि यह समूह विश्व की वृहद् आबादी और आर्थिक शक्ति के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
- **आर्थिक विकास और व्यापार के अवसरः** ब्रिक्स इंडोनेशिया को व्यापक व्यापार संबंधों और बाजारों, निवेशों और बुनियादी ढांचे के विकास तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है, जिससे समूह के भीतर आर्थिक सहयोग बढ़ता है।
- **डॉलर-विमुद्रीकरण प्रयासः** ब्रिक्स के हिस्से के रूप में, इंडोनेशिया को अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक व्यापार तंत्रों और मुद्राओं का पता लगाने के प्रयासों से लाभ होता है, जिससे इसकी आर्थिक संप्रभुता मजबूत होती है।
- **वैश्विक संस्थानों में सुधारः** इंडोनेशिया आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार की वकालत करने में ब्रिक्स के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य अधिक समावेशी और निष्पक्ष वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है।
- **ग्लोबल साउथ सहयोगः** इंडोनेशिया की सदस्यता ग्लोबल साउथ में अन्य विकासशील देशों के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देती है, जिससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतों के लिए सामूहिक आवाज में योगदान होता है।
- **बहुपक्षवाद और कूटनीतिः** ब्रिक्स सदस्यता इंडोनेशिया की विदेश नीति के अनुरूप है, जोकि जलवायु परिवर्तन, गरीबी और सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर बहुपक्षवाद और सहयोग का समर्थन करती है।

ब्रिक्स का महत्वः

- ब्रिक्स के पास महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति है, जो दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में 35% का योगदान देता है और वैश्विक आबादी का 46% हिस्सा है, जो विकासशील देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है। यह पश्चिमी प्रभाव के विकल्प के रूप में कार्य करता है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अमेरिका और यूरोप पर निर्भरता कम करने और अधिक संतुलित वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- एक प्रमुख लक्ष्य व्यापार में स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देकर, सदस्य अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करके और वित्तीय कमजोरियों को कम करके अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना है। ब्रिक्स निष्पक्ष वैश्विक नीतियों की भी वकालत करता है, जो संयुक्त राष्ट्र और आईएमएफ जैसे वैश्विक संगठनों में विकासशील देशों के मजबूत प्रतिनिधित्व पर जोर देता है।
- सहयोग प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण तक फैला हुआ है, जिसमें सदस्य जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य सेवा चुनौतियों पर सहयोग करते हैं। ऊर्जा सुरक्षा एक और प्राथमिकता

है, क्योंकि ब्रिक्स देश ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता हैं, जो स्थिर और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। वैश्विक सहयोग पर जोर देकर, ब्रिक्स एकतरफा कार्रवाई के बजाय सामूहिक समस्या-समाधान को बढ़ावा देता है।

ब्रिक्स के सामने चुनौतियाँ:

- विविध आर्थिक हितों के कारण परस्पर विरोधी प्राथमिकताएँ बनती हैं, जहाँ चीन और भारत विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि ब्राजील और रूस प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। चीन-भारत सीमा तनाव और रूस के पश्चिम के साथ विवाद सहित राजनीतिक मतभेदों के कारण एकीकृत रुख बनाए रखना मुश्किल हो जाता है।
- भू-राजनीतिक संघर्ष निर्णय लेने को और जटिल बनाते हैं, क्योंकि ब्रिक्स के भीतर प्रतिद्वंद्विता और बाहरी गठबंधन, जैसे कि भारत के अमेरिका के साथ संबंध, सामंजस्य को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएँ वैश्विक व्यापार पर निर्भर रहती हैं, जिससे पश्चिमी बाजारों पर निर्भरता कम करना और अमेरिकी डॉलर से दूर जाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- इन चुनौतियों के बावजूद, ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देना जारी रखता है, और अधिक समावेशी और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए दबाव डालता है

फाइव आईज संकट और भारत के लिए निहितार्थ

संदर्भ:

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गठित "फाइव आईज" (Five Eyes) गठबंधन, जो विश्व की सबसे शक्तिशाली खुफिया साझेदारी में से एक है, वर्तमान में एक अभूतपूर्व आंतरिक संकट का सामना कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड का यह गठबंधन अमेरिका की विदेश नीति में हुए व्यापक बदलावों के कारण गंभीर उथल-पुथल में है। विशेष रूप से, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अपनाई गई नीतियों ने इस गठबंधन की स्थिरता को चुनौती दी है। यह संकट केवल फाइव आईज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी देशों की सामूहिक सुरक्षा संरचना को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह इस स्थिति का आकलन करे और अपनी खुफिया कूटनीति को नए वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप ढाले।

फाइव आईज: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास:

- फाइव आईज गठबंधन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते के रूप में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य दुश्मन संचार को इंटरसेप्ट करना और उसे डिकोड करना था। 1946 में इस द्विपक्षीय समझौते को औपचारिक रूप दिया गया और बाद में 1948 में इसमें कनाडा तथा 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड को शामिल किया गया। शीत युद्ध के दौरान इस गठबंधन ने सोवियत संघ और वारसा संधि के तहत आने वाले देशों की गतिविधियों पर नज़र रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 9/11 के बाद, इसका दायरा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा तक विस्तारित हो गया। हाल के वर्षों में फाइव आईज गठबंधन ने चीन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, विशेष रूप से हुआवेई जैसी कंपनियों के माध्यम से साइबर सुरक्षा को लेकर चिंताओं को उठाया गया है।

हाल के घटनाक्रम और चुनौतियाँ:

फ़ाइव आईज़ गठबंधन वर्तमान में अमेरिकी विदेश नीति में बदलावों के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में, अमेरिका के अपने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ जुड़ने के तरीके में बदलाव हुए हैं। कुछ प्रमुख घटनाक्रमों में शामिल हैं:

- **अमेरिका-कनाडा व्यापार विवाद:** ट्रंप प्रशासन की आक्रामक व्यापार नीतियों ने कनाडा को झटका दिया है। उन्होंने कनाडा को "अमेरिका का 51वां राज्य" बनाने की बात कहकर विवाद को और बढ़ा दिया।
- **ग्रीनलैंड विवाद:** ट्रंप द्वारा डेनमार्क से ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की कोशिश यूरोपीय सहयोगियों के लिए अस्वीकार्य रही।
- **ब्रिटेन के प्रति कटु रुख:** ट्रंप समर्थकों ने ब्रिटेन की "वोक राजनीति" और लेबर सरकार की नीतियों की आलोचना की है। वाशिंगटन में आयोजित एक बैठक में अमेरिकी सीनेटर जे.डी. वांस ने ब्रिटेन को "पहला इस्लामिक परमाणु शक्ति संपन्न देश" करार देकर नया विवाद खड़ा कर दिया।
- **ट्रंप प्रशासन के नए नियुक्त अधिकारी:** तुलसी गैबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक और कश पटेल को FBI निदेशक बनाए जाने से पारंपरिक सहयोगी देशों की चिंता बढ़ गई है। उनका मानना है कि ट्रंप का खुफिया साझेदारी को लेकर अनिश्चित दृष्टिकोण फाइव आईज की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
- **अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव-** अमेरिकी सरकार ने रूस और यूक्रेन जैसे देशों के साथ अपने संबंधों के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया है। नाटो और यूरोपीय संघ जैसे गठबंधनों की भूमिका के बारे में भी चर्चा हुई है। इन बदलावों के कारण फाइव आईज के सदस्यों के बीच मतभेद पैदा हुए हैं।
- **व्यापार और आर्थिक संबंध:** व्यापार नीतियाँ तनाव का स्रोत बन गई हैं। अमेरिका और कनाडा, जो लंबे समय से व्यापार भागीदार हैं, को व्यापार नियमों पर असहमति का सामना करना पड़ा है। सीमा सुरक्षा और व्यापार नीतियों के बारे में चर्चाओं ने गठबंधन में कनाडा की भूमिका के बारे में अटकलों को जन्म दिया है, हालाँकि

अधिकारियों ने किसी भी बड़े बदलाव से इनकार किया है।

- **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग:** चुनौतियों के बावजूद, फाइव आईज राष्ट्र इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सुरक्षा उपस्थिति का विस्तार करना जारी रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, यू.के. और यू.एस. के बीच एक नई सुरक्षा साझेदारी AUKUS इसका एक उदाहरण है। यह समझौता सैन्य सहयोग पर केंद्रित है, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के विकास में। जापान ने हाल के वर्षों में फाइव आईज देशों के साथ अपने खुफिया सहयोग को भी बढ़ाया है।

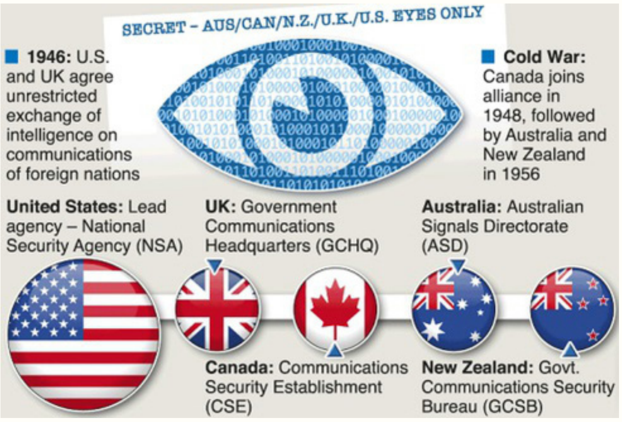

फाइव आईज का भविष्य और संभावित विभाजन

- फाइव आईज में अमेरिका की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है, लेकिन मौजूदा परिदृश्य में यह गठबंधन गहरे विभाजन की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप के सलाहकारों द्वारा कनाडा को फाइव आईज से निकालने की अटकलें, ब्रिटेन के प्रति कड़ा रवैया, और अमेरिकी दक्षिणपंथियों द्वारा फाइव आईज के उदारवादी घटकों की आलोचना इस गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठा रही है। यदि ट्रंप प्रशासन फाइव आईज को पुनर्गठित करने की दिशा में बढ़ता है, तो यह संभव है कि यूरोपीय संघ और NATO इस स्थिति का लाभ उठाकर एक अलग खुफिया नेटवर्क विकसित करें।

भारत के लिए रणनीतिक अवसर

फाइव आईज में उत्पन्न संकट भारत के लिए कई संभावनाएं प्रस्तुत करता है:

- **इंटेलिजेंस साझेदारी का विस्तार:** फाइव आईज के भीतर अस्थिरता भारत को अपनी खुफिया क्षमताओं को मजबूत करने और अन्य मित्र देशों के साथ गहन सहयोग के अवसर प्रदान कर सकती है।
- **इंडो-पैसिफिक में भूमिका:** AUKUS (अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य गठबंधन) के विस्तार की चर्चाओं के बीच भारत अपनी रणनीतिक स्थिति को बेहतर बना सकता है।
- **तकनीकी सुरक्षा:** हुआवेई और 5G जैसी सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत को पश्चिमी देशों के साथ साइबर सुरक्षा और तकनीकी खुफिया साझेदारी को मजबूत करना चाहिए।
- **नए गठबंधन की संभावना:** यदि फाइव आईज में विभाजन गहरा होता है, तो भारत नए बहुपक्षीय खुफिया साझेदारी के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- **डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग:** भारत को अपने तकनीकी कौशल का लाभ उठाकर डिजिटल निगरानी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित खुफिया विश्लेषण के क्षेत्र में फाइव आईज और अन्य मित्र देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
- **साइबर सुरक्षा सहयोग:** बढ़ते साइबर हमलों और डिजिटल युद्धों के बीच भारत को फाइव आईज देशों के साथ साइबर सुरक्षा उपायों को साझा करने की पहल करनी चाहिए।

फाइव आईज गठबंधन में मौजूदा संकट अमेरिका की बदलती नीतियों का परिणाम है। यदि यह संकट और गहराता है, तो यह वैश्विक सुरक्षा ढांचे में व्यापक परिवर्तन ला सकता है। भारत के लिए यह एक अवसर है कि वह इस स्थिति का लाभ उठाए और अपनी खुफिया कूटनीति को पुनर्गठित करे। भारत को अपने पारंपरिक साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए और नए रणनीतिक गठबंधनों की संभावनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। वैश्विक भू-राजनीति में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्क्वाड समूह में भारत को शामिल करने की योजना

संदर्भ:

हाल ही में फिलीपींस, भारत और दक्षिण कोरिया को शामिल करके अपने अनौपचारिक सुरक्षा समूह स्क्वाड का विस्तार करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना करना है।

स्क्वाड समूह के विषय में:

- स्क्वाड एक अनौपचारिक सुरक्षा गठबंधन है, जिसमें वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल हैं। यह समूह दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर संयुक्त समुद्री अभ्यास और संचालन कर रहा है।
- इन गतिविधियों का उद्देश्य चीन की आक्रामक नीतियों के कारण क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना

और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।

- समूह के विस्तार से इसकी रक्षा क्षमता और मजबूती बढ़ेगी, जिससे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का बेहतर तरीके से सामना किया जा सकेगा। भारत और दक्षिण कोरिया को शामिल करने से आपसी रक्षा सहयोग मजबूत होगा और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

भारत और दक्षिण कोरिया क्यों?

- भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ने विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर चिंता व्यक्त की है। भारत की चीन के साथ सीमा विवादों के चलते लंबे समय से तनाव बना हुआ है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा समुद्री हितों के कारण वह स्क्वाड (Squad) का एक रणनीतिक साझेदार बन सकता है।
- इसके अतिरिक्त, भारत और फिलीपींस के बीच बढ़ते रक्षा और सैन्य संबंध इस समूह के भीतर गहरे सहयोग की संभावनाओं को मजबूत करते हैं। इसी तरह, दक्षिण कोरिया भी चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंतित है। स्क्वाड में शामिल होने से उसे अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देने का एक प्रभावी मंच मिलेगा।

चीन की प्रतिक्रिया:

- चीन ने विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की कार्रवाइयों पर आपत्ति जताई है। वह लगातार इस क्षेत्र के लगभग पूरे हिस्से पर दावा करता रहा है, जबकि फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया सहित कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की संप्रभुता के दावों को अनदेखा करता है।
- फिलीपींस ने इन दावों का विरोध किया है, विशेष रूप से 2016 में आए एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले के बाद, जिसने चीन के क्षेत्रीय दावों को अमान्य करार दिया था।
- इसके बावजूद, चीन इस क्षेत्र पर अपने नियंत्रण का दावा जारी रखे हुए है, जिससे विवादित जलक्षेत्र में चीनी और फिलीपीन जहाजों के बीच टकराव की घटनाएँ बढ़ रही हैं।

क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए निहितार्थ:

- भारत और दक्षिण कोरिया को शामिल करने से स्क्वाड का विस्तार इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। यह गठबंधन चीन के बढ़ते प्रभाव का एक मजबूत प्रतिसंतुलन प्रदान करेगा, विशेष रूप से उन समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जो वैश्विक व्यापार के लिए अहम हैं।
- रक्षा सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने से स्क्वाड और अधिक प्रभावशाली बन सकता है, जिससे दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

छठा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन

संदर्भः

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड का दौरा किया, जो 2018 काठमांडू शिखर सम्मेलन के बाद बिम्सटेक नेताओं की पहली व्यक्तिगत बैठक थी। कोलंबो (2022) में वर्चुअल रूप से आयोजित पिछले शिखर सम्मेलन में चार्टर को अपनाने के साथ बिम्सटेक की संस्थागत संरचना को औपचारिक रूप दिया गया था। छठे शिखर सम्मेलन की थीम "समृद्ध, लचीला और खुला बिम्सटेक (प्रो बिम्सटेक)" (Prosperous, Resilient, and Open BIMSTEC (PRO BIMSTEC)) है, जो आर्थिक एकीकरण, सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर क्षेत्र के फोकस को दर्शाता है।

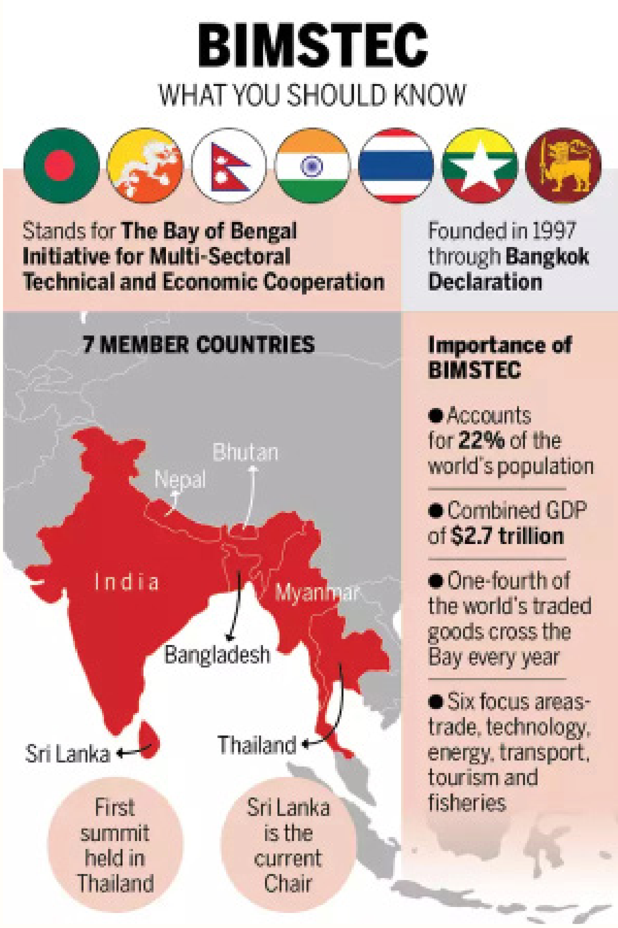

बिम्सटेक का महत्वः

- बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल) एक क्षेत्रीय समूह है जो बंगाल की खाड़ी से लगे देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देता है।

- यह समूह शुरुआत में 1997 में BIST-EC (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग) के रूप में बना था। बाद में म्यांमार (1997), नेपाल और भूटान (2004) इसके सदस्य बने और इसे बिम्सटेक नाम मिला।
- बिम्सटेक, जो 1.8 अरब लोगों (दुनिया की 22% आबादी) का घर है और जिसकी सम्मिलित GDP $3.6 ट्रिलियन है, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है।
- जहां एक ओर सार्क भारत-पाक तनावों के कारण निष्क्रिय हो गया है, वहीं बिम्सटेक व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग का एक अधिक व्यावहारिक मंच प्रदान करता है।

भारत की भूमिका और रणनीतिक हित:

- भारत बिम्सटेक को अपनी पड़ोसी प्रथम (Neighbourhood First) और एक्ट ईस्ट (Act East) नीतियों के तहत प्राथमिकता देता है। 2016 में सार्क में गतिरोध के बाद, भारत ने बिम्सटेक पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रिक्स सम्मेलन (गोवा, 2016) के साथ एक विशेष बिम्सटेक आउटरिच शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की।
- भारत बिम्सटेक में 4S दृष्टिकोण को अपनाता है:
  - सम्मान
  - संवाद
  - शांति
  - समृद्धि

छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन (2024) में भारत के प्रमुख प्रस्ताव

- **आर्थिक और डिजिटल कनेक्टिविटी:**
  - बिम्सटेक चैंबर ऑफ कॉमर्स और वार्षिक बिजनेस समिट की स्थापना।
  - भारत के UPI को बिम्सटेक भुगतान प्रणालियों से जोड़ना।
  - स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना ताकि बाहरी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता कम हो।
- **समुद्री और परिवहन सहयोग:**
  - नीतिगत समन्वय के लिए सतत समुद्री परिवहन केंद्र की स्थापना।
  - ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड इंटरकनेक्शन को मजबूत करना।
- **आपदा प्रबंधन और जलवायु सहनशीलता:**
  - भारत में बिम्सटेक आपदा प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।
  - 2024 में चौथा संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यास आयोजित करना।
- **शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास:**
  - BODHI (BIMSTEC for Organised Development of Human Resource Infrastructure) पहल शुरू करना, जिसके तहत बिम्सटेक देशों के 300 युवाओं को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  - नालंदा विश्वविद्यालय और वन अनुसंधान संस्थान में छात्रवृत्तियों का विस्तार।
  - कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और कैंसर देखभाल में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना।
- **अंतरिक्ष और तकनीकी सहयोग:**
  - उपग्रह आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए बिम्सटेक ग्राउंड स्टेशन की स्थापना।
  - नैनो-सेटेलाइट विकास और रिमोट सेंसिंग सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- **सांस्कृतिक और खेल आदान-प्रदान:**
  - बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव और युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित करना।
  - बिम्सटेक एथलेटिक्स मीट (2024) और पहले बिम्सटेक गेम्स (2027) का आयोजन।

विकसित और विकासशील देशों की नीतियाँ

मुसानेद प्लेटफार्म

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सऊदी अरब ने विदेशी श्रमिकों, विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, मुसानेद, प्रस्तुत किया है। यह पहल सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य श्रम स्थितियों में सुधार लाना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और अवैध आव्रजन को कम करना है।

मुसनद की मुख्य विशेषताएं:

- **वेतन संरक्षण प्रणाली:** इस प्लेटफॉर्म में एक वेतन संरक्षण प्रणाली शामिल है, जोकि नियोक्ताओं और विदेशी श्रमिकों के बीच भुगतान की निगरानी करके नियोक्ताओं द्वारा अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की पुष्टि करती है। इसका उद्देश्य वेतन शोषण और देरी को रोकना है।
- **रोजगार अनुबंध और अपडेट:** मुसानेद विदेशी श्रमिकों को अपने रोजगार अनुबंधों तक पहुंचने और उन्हें ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है, साथ ही किसी भी बदलाव के बारे में अद्यतन भी करता है। यह विवादों को सुलझाने में सहायक है, क्योंकि दूतावासों के पास नियोक्ता के नाम और अनुबंध की स्थिति जैसे कर्मचारी विवरणों तक 'पहुंच देखने' (View Access) की सुविधा होती है।
- **बीमा और स्वास्थ्य लाभ से लिंक:** मुसानेद श्रमिकों के बीमा और स्वास्थ्य लाभ से संबंधित है, जो विदेशी श्रमिकों के लिए व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करता है और सऊदी अरब में उनके समग्र कल्याण में सुधार लाता है।
- **कुशल विवाद समाधान:** यह प्लेटफॉर्म श्रमिकों के रोजगार रिकॉर्ड और नियोक्ता की पृष्ठभूमि (जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं) तक डिजिटल पहुँच की अनुमति देता है, जिससे श्रम विवादों के त्वरित समाधान की सुविधा मिलती है। इससे विवाद निपटान में नियोक्ता की ईमानदारी और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

प्रभावः

- **भौगोलिक प्रभाव:** मुसानेद 10 अफ्रीकी देशों (जैसे सूडान, इथियोपिया और केन्या) और 9 एशियाई देशों (जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका) के श्रमिकों को लाभ पहुंचाता है। लगभग 1.4 मिलियन भारतीय श्रमिक सऊदी श्रम बाजार में सबसे बड़े समूहों में से एक हैं, जबकि बांग्लादेश 2.7 मिलियन श्रमिकों के साथ अग्रणी है।
- **श्रम मुकदमा प्रबंधन:** इस प्लेटफॉर्म से श्रम मुकदमों के समाधान को सुव्यवस्थित करने की संभावना है। 2021 से 2024 तक, घरेलू क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों से जुड़े 12,600 से अधिक श्रम मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुसानेद पारदर्शिता और डिजिटल रिकॉर्ड एक्सेस की पेशकश करके इस प्रक्रिया में सुधार करेगा, जिससे विवादों का समाधान अधिक कुशलता से हो सकेगा।
- **अवैध आव्रजन पर अंकुश लगाना:** मुसानेद का उद्देश्य सऊदी सरकार को नियोक्ताओं की अधिक प्रभावी ढंग से जांच करने की अनुमति देकर अवैध आव्रजन को कम करना है। यह प्रणाली नियोक्ताओं के आपराधिक रिकॉर्ड की निगरानी करती है और यह सुनिश्चित करती है कि केवल अधिकृत श्रमिकों को ही काम पर रखा जाए, जिससे तस्करी या शोषण का जोखिम न्यूनतम हो।

चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से ब्राजील बाहर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) में शामिल न होने के घोषणा की, जिससे वह भारत के बाद ब्रिक्स ब्लॉक का दूसरा सदस्य बन गया, जिसने इस बहु-अरब डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजना में भागीदारी से इनकार कर दिया। इस निर्णय से ब्राजील ने चीन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बजाय अपनी स्वयं की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए चीनी निवेशकों के साथ तालमेल तलाशने को प्राथमिकता दी है।

बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) के बारे में:

- BRI, जिसे शुरू में 2013 में 'वन बेल्ट वन रोड' के रूप में लॉन्च किया गया था, का उद्देश्य भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना है। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार, व्यापार में वृद्धि और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना शामिल है। इस पहल में शामिल हैं:
  - » सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट: एक ट्रांस-महाद्वीपीय मार्ग।
  - » समुद्री सिल्क रोड: एक समुद्री मार्ग।
- बीआरआई में बंदरगाहों और परिवहन नेटवर्क सहित विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण निवेश शामिल है।

बीआरआई के संबंध में भारत की प्रमुख चिंताएँ:

- **संप्रभुता:** बीआरआई की प्रमुख परियोजना, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान को पार करती है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है।
- **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** बीआरआई के वित्तीय प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कम ब्याज वाले ऋण दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं।
- **ऋण स्थिरता:** चीनी ऋण के कारण भागीदार देशों पर पड़ने वाले अस्थिर ऋण बोझ के बारे में चिंताएं ऋण जाल की धारणा को जन्म देती हैं, जिससे वे चीन के प्रभाव के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
- **सुरक्षा संबंधी खतरे:** हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को भारत सुरक्षा चिंता के रूप में देखता है, विशेष रूप से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत।

बीआरआई का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम:

- जी7 समूह द्वारा वैश्विक अवसंरचना और निवेश (पीजीआईआई) और बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (बी3डब्ल्यू) साझेदारी।
- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC), जिसे भारत की G-20 अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC), जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है।

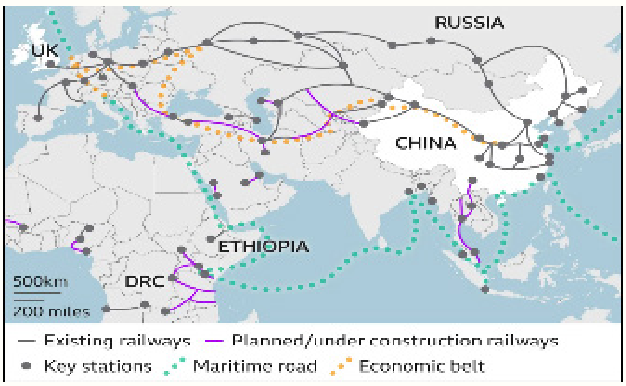

भू-राजनीतिक निहितार्थ:

- ब्राजील, इटली और फिलीपींस सहित उन देशों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से खुद को अलग कर लिया है। हालाँकि ब्राजील और चीन के बीच व्यापार संबंध बहुत अच्छे हैं (लगभग $180 बिलियन प्रति वर्ष) लेकिन चीनी निवेश पर निर्भरता के बारे में ब्राजील के भीतर सतर्कता बढ़ रही है।
- वर्तमान में, ब्राजील को हर साल लगभग $3 बिलियन का चीनी निवेश मिलता है, जिससे इसकी आर्थिक रणनीति और क्षेत्रीय साझेदारी का महत्वपूर्ण पुनर्मूल्यांकन हो रहा है।
- बीआरआई की यह अस्वीकृति भारत के पहले के विरोध से मेल खाती है, जिसने संप्रभुता, संभावित ऋण जाल और बीआरआई परियोजनाओं में पारदर्शिता की कमी के बारे में चिंताएँ जताई थीं। भारत का रुख खास तौर पर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से प्रभावित था, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है और संप्रभुता के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता है।
- ब्राजील जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, यह निर्णय उसके कूटनीतिक दृष्टिकोण में बदलाव को रेखांकित करता है, जो व्यापक बाहरी प्रभाव पर राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देता है।

स्पेन राष्ट्रपति की भारत यात्रा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने भारत की आधिकारिक यात्रा की, जोकि द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह यात्रा न केवल राष्ट्रपति सांचेज की भारत की पहली यात्रा है, बल्कि 18 वर्षों में स्पेन के किसी शासनाध्यक्ष द्वारा की गई पहली यात्रा भी है।

भारत-स्पेन आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध:

- भारत-स्पेन व्यापारिक संबंधों में निरंतर वृद्धि देखी गई है तथा स्पेन यूरोपीय संघ में भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- **कुल व्यापार (2023):** 8.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2022 से 4.2% की वृद्धि)।
- **भारत का स्पेन को निर्यात:** खनिज ईंधन, रसायन, लोहा और इस्पात, विद्युत मशीनरी, परिधान और समुद्री उत्पादों में 6.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर (5.2% की वृद्धि)।
- **स्पेन से भारत का आयात:** 1.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर (1.05% की वृद्धि), मुख्य रूप से मशीनरी और विनिर्मित वस्तुओं में।
- भारत-स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग (जेसीईसी) और भारत-स्पेन सीईओ फोरम (2015) इन आर्थिक संबंधों को समर्थन देने वाले प्रमुख मंच हैं। ये निकाय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देते हैं, जिससे आर्थिक सहयोग पर नियमित बातचीत संभव होती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई):

एफडीआई भारत-स्पेन आर्थिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है:

- **भारत में स्पेन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश:** 3.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल 2000-दिसंबर 2023), स्पेन को भारत का 16वां सबसे बड़ा निवेशक माना गया। भारत में 280 से ज्यादा स्पेनिश कंपनियाँ धातुकर्म, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोटिव और बुनियादी ढाँचे सहित कई क्षेत्रों में काम करती हैं, जिनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात प्रमुख निवेश केंद्र हैं।

- **स्पेन में भारतीय एफडीआई:** स्पेन में लगभग 80 भारतीय कंपनियाँ (900 मिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई) हैं, जिनमें से अधिकांश आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में हैं। इससे भारत स्पेन के शीर्ष 30 वैश्विक निवेशकों में से एक और एशिया के शीर्ष 5 निवेशकों में से एक बन गया है।

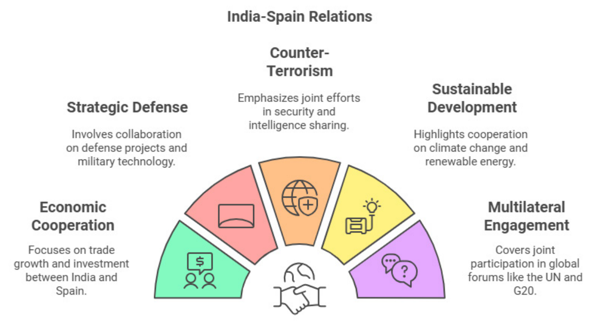

सामरिक एवं रक्षा सहयोग:

- रक्षा सहयोग भारत-स्पेन संबंधों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है।
- फाइनल असेंबली लाइन (FAL) प्लांट भारत की पहली निजी सैन्य परिवहन विमान सुविधा है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ साझेदारी में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) द्वारा विकसित इस परियोजना के तहत 2.5 बिलियन डॉलर के अनुबंध में 56 C295 विमानों में से 40 को भारत में असेंबल किया जाएगा।
- यह सुविधा 2026 तक अपना पहला 'मेड-इन-इंडिया' C295 विमान वितरित करेगी, जबकि सभी डिलीवरी 2031 तक पूरी हो जाएंगी। यह परियोजना भारत में एक पूर्ण एयरोस्पेस विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रही है, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और कई निजी एमएसएमई का योगदान शामिल है।

आतंकवाद निरोध और साइबर सुरक्षा:

- भारत और स्पेन के बीच आतंकवाद निरोध तथा खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग जारी है, जिससे वैश्विक सुरक्षा संबंधी आपसी चिंताओं का समाधान हो सके।

सतत विकास और जलवायु कार्रवाई:

- भारत और स्पेन दोनों ही पेरिस समझौते का समर्थन करते हैं और जलवायु परिवर्तन पहलों पर मिलकर काम करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में स्पेन की विशेषज्ञता भारत के हरित ऊर्जा स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के विस्तार के लक्ष्यों को पूरा करती है।
- दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के तहत सहयोग करते हैं, जिसमें स्पेन सतत विकास पर भारत के फोकस के साथ जुड़ता है।

बहुपक्षीय सहयोग:

- भारत और स्पेन बहुपक्षीय जुड़ाव के लिए साझा मंचों का उपयोग करते हैं:
  - » **संयुक्त राष्ट्र (यूएन):** दोनों देश वैश्विक शांति, सतत विकास और मानवीय प्रयासों पर सहयोग करते हैं।
  - » **जी-20:** जी-20 के सदस्य के रूप में भारत और स्पेन वैश्विक आर्थिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन और व्यापार सुधारों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  - » **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए):** स्पेन की आईएसए सदस्यता सौर ऊर्जा और टिकाऊ पहलों पर सहयोग को मजबूत करती है।

स्पेन में भारतीय प्रवासी:

- स्पेन में भारतीय समुदाय, हालांकि अपेक्षाकृत छोटा है, फिर भी यह तेजी से विस्तारित हो रहा है। 2023 तक, लगभग 55,000 भारतीय नागरिक स्पेन में निवास करते हैं। ये नागरिक आतिथ्य, खुदरा, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं, जिससे स्पेनिश समाज का समृद्धिकरण हो रहा है।

फेवा संवाद

चर्चा में क्यों?

नेपाल और चीन ने हाल ही में 'फेवा संवाद' नाम की एक नई कूटनीतिक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय समृद्धि, शांति और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। इस संवाद का नाम पोखरा घाटी की प्रसिद्ध फेवा झील के नाम पर रखा गया है, जो सहयोग और साझेदारी का प्रतीक है। यह झील अपने पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है। इस पहल का लक्ष्य न केवल नेपाल और चीन के बीच सहयोग को मजबूत करना है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में साझेदारी को बढ़ावा देना है।

फेवा संवाद का महत्व

- **क्षेत्रीय सहयोग:** फेवा संवाद का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। दक्षिण एशिया को गरीबी, पर्यावरणीय समस्याओं और सुरक्षा चिंताओं जैसी कई साझा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह संवाद इन समस्याओं का मिलकर समाधान खोजने और शांति व समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **आर्थिक एकीकरण:** यह संवाद आर्थिक एकीकरण पर भी जोर देता है। इसमें व्यापार बाधाओं, बुनियादी ढांचे की कमी और राजनीतिक तनाव जैसे मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जाएगा। अगर आर्थिक सहयोग मजबूत हुआ, तो यह क्षेत्र में व्यापार, निवेश और विकास के नए अवसर पैदा कर सकता है,

जिससे सभी भाग लेने वाले देशों को लाभ होगा।

- **मुख्य मुद्दों पर चर्चा:** फेवा संवाद एक ऐसा मंच है जहां औद्योगिक बदलाव, नई तकनीकों और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ये चर्चाएं दक्षिण एशिया को वैश्विक परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बिठाने और दीर्घकालिक स्थिरता व आधुनिकीकरण के समाधान खोजने में मदद करती हैं।
- **ट्रैक-II कूटनीति:** फेवा संवाद की एक खासियत यह है कि इसमें ट्रैक-II कूटनीति (गैर-सरकारी स्तर पर बातचीत) का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शैक्षणिक संस्थान जैसे चीन का सिचुआन विश्वविद्यालय और नेपाल का त्रिभुवन विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये संस्थान नीतियों के निर्माण और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।

चीन और नेपाल के बीच हाल के कूटनीतिक विक. ास

- **आर्थिक संबंध:** चीन 2014 से नेपाल का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) साझेदार बन गया है। ये निवेश जलविद्युत (जैसे बुढी गंडकी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट) सहित कई क्षेत्रों में हैं। इसके अलावा, चीन ने नेपाल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़ी वित्तीय सहायता दी है।
- **रणनीतिक साझेदारी:** 2019 में नेपाल और चीन ने अपने संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नेपाल यात्रा के दौरान इस साझेदारी को औपचारिक रूप से मजबूत किया गया। इसके तहत रक्षा, सुरक्षा और व्यापार में सहयोग बढ़ा है, जिसमें चीन ने नेपाल को सैन्य सहायता भी प्रदान की है।

फेवा संवाद का भारत पर प्रभाव:

- **क्षेत्रीय संतुलन में बदलाव:** यह संवाद दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को मजबूत कर सकता है, जिससे नेपाल में भारत की पारंपरिक पकड़ कमजोर हो सकती है। नेपाल की चीन पर आर्थिक और रणनीतिक निर्भरता बढ़ने से भारत को चिंता हो सकती है।
- **व्यापार और निवेश में प्रतिस्पर्धा:** चीन के नेपाल के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते निवेश से भारत को व्यापार और निवेश के क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।
- **सुरक्षा चिंताएं:** नेपाल और चीन के बीच मजबूत रक्षा और सुरक्षा संबंध भारत के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं, खासकर दोनों देशों की साझा सीमा को लेकर। इससे भारत को क्षेत्र में अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

अमेरिका-चीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका और चीन ने अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (STA) को पांच साल के लिए नवीनीकृत किया है। यह समझौता 27 अगस्त 2024 से प्रभावी हुआ। नवीनीकरण से यह साफ होता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और तकनीकी जैसे क्षेत्रों में तनाव के बावजूद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग जारी रहेगा।

- इसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उभरते मुद्दों को भी शामिल किया गया है। 1979 में पहली बार हस्ताक्षरित यह समझौता अमेरिका और चीन के बीच विभिन्न वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।
- शुरुआत में कृषि अनुसंधान पर केंद्रित इस समझौते का दायरा अब बढ़कर कई अनुसंधान क्षेत्रों तक पहुंच गया है, जिससे दोनों देशों के शोधकर्ताओं, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन मिला है।

नए समझौते में किए गए मुख्य बदलाव:

- **मूलभूत अनुसंधान तक सीमित:**
  - » अब सहयोग केवल मूलभूत अनुसंधान तक सीमित रहेगा।
  - » संवेदनशील तकनीकों को सैन्य या रणनीतिक उद्देश्यों में उपयोग से बचाने के लिए उभरती और महत्वपूर्ण तकनीकों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
- **शोधकर्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान:**
  - » सहयोगी परियोजनाओं में जुड़े शोधकर्ताओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं।
- **डेटा पारदर्शिता और आदान-प्रदान:**
  - » दोनों देशों के बीच डेटा के निष्पक्ष और पारदर्शी आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
- **विवाद समाधान तंत्र:**
  - » समझौते में असहमति या उल्लंघन को हल करने के लिए एक तंत्र शामिल किया गया है।

- **समाप्ति प्रावधान:**
  - » यदि किसी पक्ष ने 'खराब नीयत' से कार्य किया, तो परियोजनाओं को रद्द करने का प्रावधान शामिल किया गया है।

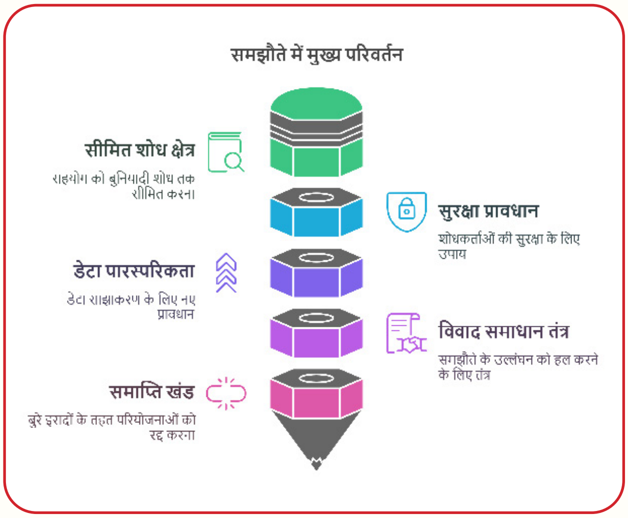

यह समझौता अमेरिका और चीन दोनों के लिए कैसे लाभकारी रहा है?

- **अमेरिका के लिए:**
  - » चीन के तेजी से विकसित हो रहे अनुसंधान क्षेत्र तक पहुंच मिली।
  - » कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण विज्ञान जैसे क्षेत्रों में संयुक्त शोध को बढ़ावा मिला।
- **चीन के लिए:**
  - » अमेरिकी तकनीक तक पहुंच मिली, जिससे वह वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक अग्रणी शक्ति बना।
  - » शैक्षिक आदान-प्रदान और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं ने चीन की वैश्विक वैज्ञानिक पहुंच को विस्तारित किया।

भारत के लिए प्रभाव:

- **अनुसंधान और विकास में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा:**
  - » विज्ञान और प्रौद्योगिकी में चीन की बढ़ती ताकत भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है।
  - » भारत को प्रतिस्पर्धी बने रहने और तकनीकी प्रगति बनाए रखने के लिए अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश करना होगा।
- **भू-राजनीतिक लाभ:**
  - » अमेरिका और चीन के बीच संबंधों के चलते भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों में बदलाव आ सकता है।
  - » इसका असर भारत की वैश्विक राजनीति और साझेदारियों पर पड़ सकता है।
- **रणनीतिक सहयोग का अवसर:**
  - » भारत के मजबूत अनुसंधान और अन्य देशों के साथ समझौतों के चलते, वह अमेरिका और उन देशों के लिए एक अच्छा भागीदार बन सकता है, जो चीन के बजाय भारत के साथ काम करना चाहते हैं।
  - » इससे भारत की वैज्ञानिक साख में सुधार होगा और नई तकनीकों और अनुसंधान अवसरों तक पहुंच मिलेगी।

ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा बांध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जलविद्युत बांध के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसे यारलुंग त्सांगपो बांध (Yarlung Tsangpo Dam) के नाम से जाना जायेगा। तिब्बत में जांगबो नदी पर स्थित यह परियोजना चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना (2021-2025) का हिस्सा है। यह परियोजना भारतीय सीमा के पास स्थित है और इसमें कुल 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है।

बांध की क्षमता और विशेषताएं:

- इस बांध से प्रतिवर्ष 300 बिलियन किलोवाट घंटे से अधिक बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है, जोकि 300 मिलियन से अधिक लोगों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।
- यह जलविद्युत परियोजना चीन की कार्बन पीकिंग (carbon peaking) और कार्बन तटस्थता (carbon neutrality) रणनीति का हिस्सा है इसलिए इसे 'हरित परियोजना' (green project) माना जा रहा है, जोकि कार्बन उत्सर्जन में कमी करने में सहायक होगी।
- जलविद्युत के अतिरिक्त, यह परियोजना आसपास के क्षेत्रों में सौर (solar) और पवन ऊर्जा (wind energy) संसाधनों के विकास को प्रोत्साहित करेगी, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में योगदान मिलेगा।

भारत और बांग्लादेश के लिए मुख्य चिंता:

- बांध के निर्माण ने भारत और बांग्लादेश में चिंता पैदा कर दी है क्योंकि यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जोकि इन दोनों देशों से होकर बहती है। ऐसी आशंका है कि चीन पानी के प्रवाह में हेरफेर कर सकता है, जिससे बाढ़ या पानी की कमी जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, विशेषकर संघर्ष के समय। इसके अतिरिक्त, बांध का आकार और पैमाना जल संसाधनों पर चीन के नियंत्रण को बढ़ा सकता है।
- यह बांध भूकंपीय (seismically) रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, जिससे परियोजना की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएँ उठी हैं। हालांकि, चीन ने दावा किया है कि परियोजना पारिस्थितिकीय सुरक्षा (ecological safety) को प्राथमिकता देती है और इसके सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए हैं, जिनका उद्देश्य भूकंपीय और पर्यावरणीय क्षति के प्रभाव

को कम करना है।

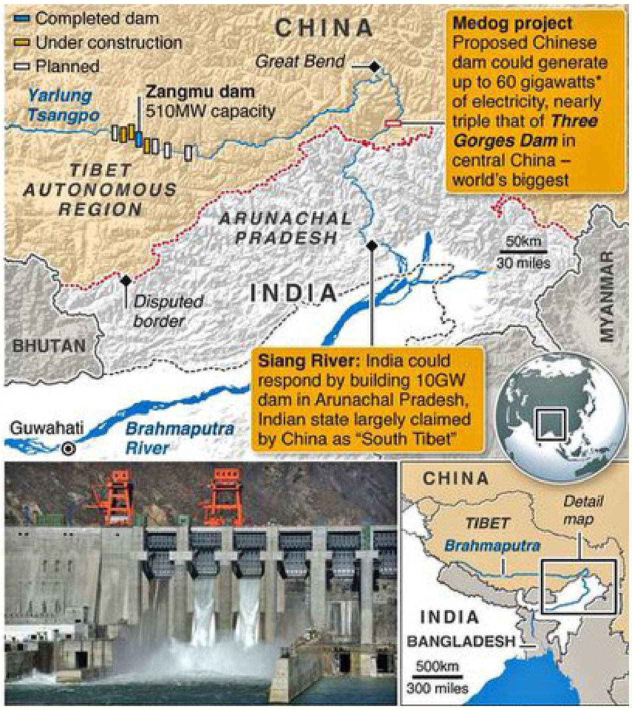

बांध का प्रभाव:

- इस परियोजना से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है, जिससे तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (Tibet Autonomous Region) के लिए सालाना 20 बिलियन युआन (3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की आय उत्पन्न होगी। यह परियोजना इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, व्यापार सेवाओं जैसे उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा देगी और क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
- बांध के निर्माण के बाद तिब्बत में बिजली, जल संरक्षण और परिवहन बुनियादी ढांचे (infrastructure) के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे तिब्बत और चीन के अन्य क्षेत्रों के बीच आर्थिक तालमेल भी मजबूत होगा और तिब्बत की अर्थव्यवस्था का विकास होगा।
- यह परियोजना चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें जल संसाधन प्रबंधन भी शामिल है। इसे दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के एक उपाय के रूप में देखा जा रहा है, विशेषकर ऊर्जा सहयोग (Energy Cooperation) के संदर्भ में। यह जलविद्युत स्टेशन तिब्बत में चीन के बुनियादी ढांचे के विकास में भी रणनीतिक भूमिका निभाएगा।

ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में:

- कैलाश पर्वतमाला (Kailash Range) से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह नदी अपने मार्ग में आने वाले लाखों लोगों के परिदृश्य (landscape) और आजीविका को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

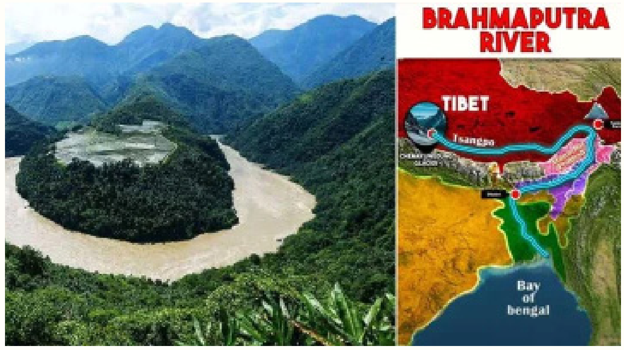

बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र:

- **बेसिन:** अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में फैला हुआ है।
- **जलग्रहण क्षेत्र (Catchment Area):**
  - » तिब्बत (2,93,000 वर्ग किमी)
  - » भारत और भूटान (2,40,000 वर्ग किमी)
  - » बांग्लादेश (47,000 वर्ग किमी)
  - » कुल बेसिन क्षेत्र: 5,80,000 वर्ग किमी
- **डेल्टा:** यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है।

जन्मसिद्ध नागरिकता पर बहस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) पर बहस राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश के कारण फिर से शुरू हो गई है, जिसमें इस अधिकार को रोकने का प्रयास किया गया है। 14वें संशोधन के उल्लंघन का हवाला देते हुए, जो अमेरिकी धरती पर पैदा हुए सभी व्यक्तियों को नागरिकता की गारंटी देता है, एक संघीय न्यायाधीश ने आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया।

अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता का इतिहास:

- स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में, नागरिकता का निर्धारण मुख्य रूप से व्यक्तिगत राज्यों के कानूनों पर निर्भर था। हालांकि, एक व्यापक समझ थी कि अमेरिकी क्षेत्र में जन्मे बच्चे अमेरिकी नागरिक होते हैं।
- वर्ष 1788 में अपनाए गए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने 'प्राकृतिक रूप से पैदा हुए नागरिकों' की अवधारणा को मान्यता दी। हालांकि, संविधान ने इस शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया, जिससे नागरिकता के दायरे के बारे में अस्पष्टता बनी रही।
- 1866 में पारित 14वां संशोधन ने अमेरिकी नागरिकता के दायरे में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इस संशोधन ने स्पष्ट रूप से घोषित

किया कि 'संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिकीकृत सभी व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और जिस राज्य में वे निवास करते हैं, के नागरिक हैं।'

- इस संशोधन ने ड्रेड स्कॉट बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट दिया, जिसमें दासों और उनके वंशजों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया था।
- **अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की भूमिका:** 14वें संशोधन ने विशेष रूप से 'अमेरिका के अधिकार क्षेत्र के अधीन' वाक्यांश के संबंध में बहस छेड़ दी। 1898 के सुप्रीम कोर्ट के मामले (यूनाइटेड स्टेट्स बनाम वोंग किम अर्क) ने स्पष्ट किया कि चीनी प्रवासियों के बच्चे भी नागरिकता के हकदार हैं, इस बात की पुष्टि करते हुए कि अमेरिकी धरती पर पैदा होना नागरिकता के लिए पर्याप्त है।
- **प्लिलर बनाम डो (1982):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अवैध अप्रवासियों के बच्चों को भी अमेरिकी सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह फैसला 14वें संशोधन के तहत बच्चों के नागरिकता अधिकारों पर आधारित था, भले ही उनके माता-पिता की कानूनी स्थिति कुछ भी हो।

भारत में जन्मसिद्ध नागरिकता:

- भारत की स्वतंत्रता के समय से ही जन्मसिद्ध नागरिकता एक बहस का विषय रहा है। बी.आर. अंबेडकर और सरदार पटेल जैसे देश के प्रमुख नेताओं ने जन्मसिद्ध नागरिकता का समर्थन किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया और बाद में नागरिकता अधिनियम, 1955 के माध्यम से इसे कानूनी रूप दिया गया।
- हालांकि, 1986 में, संसद ने 'बांग्लादेश, श्रीलंका और कुछ अफ्रीकी देशों' से प्रवासियों के प्रवेश को संबोधित करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया। संशोधन लागू होने के बाद पैदा हुए सभी बच्चे केवल तभी नागरिक बनेंगे जब माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, जो भारत में जन्मसिद्ध नागरिकता का अंत करता है।
- 2003 में, अधिनियम में एक और संशोधन किया गया जिसके अनुसार, यदि किसी बच्चे के माता-पिता में से कोई एक अवैध अप्रवासी था, तो वह बच्चा जन्म के समय भारतीय नागरिक नहीं होगा। इस संशोधन ने जन्मसिद्ध नागरिकता की अवधारणा को और अधिक सीमित कर दिया।

रूस और ईरान ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने एक ऐतिहासिक समझौते-ईरानी-रूसी व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि 20 वर्षीय साझेदारी की रूपरेखा तैयार करती है, जिसका उद्देश्य रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद का मुकाबला करने सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।

संधि के प्रमुख प्रावधान:

- **आर्थिक सहयोग:** संधि व्यापार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जोकि पहले ही 2024 में 15.5% बढ़कर 3.77 बिलियन डॉलर हो गया है। दोनों देश ऊर्जा, वित्त और प्रौद्योगिकी में व्यापार का विस्तार करने और अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का लक्ष्य रखते हैं।
- **रक्षा और सैन्य सहयोग:** रूस और ईरान संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों, खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान सहित सैन्य संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं।
- **साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी:** दोनों देश सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के विकास में बढ़ते सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- **क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग:** संधि व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों को शामिल करती है, जिसमें आतंकवाद का मुकाबला करने और संगठित अपराध और धन शोधन जैसी चुनौतियों का समाधान करने पर जोर दिया गया है।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान और कूटनीति:** संधि के एक भाग में रूस और ईरान के बीच सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों के विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, विभिन्न गैर-राजनीतिक क्षेत्रों में आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा दिया गया है।

वैश्विक प्रभाव:

- **अमेरिकी प्रतिबंधों पर प्रभाव:** इस संधि के प्रमुख प्रेरक कारकों में से एक रूस और ईरान दोनों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों को कम करना है। संधि दोनों देशों को प्रतिबंधों को दरकिनार करने और व्यापार और ऊर्जा विनिमय को बढ़ावा देकर अपनी आर्थिक लचीलापन बढ़ाने की अनुमति देती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां दोनों देश बाहरी सहयोग पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
- **मध्य पूर्व में गठबंधनों में बदलाव:** यह संधि मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता रखती है। चूंकि दोनों देश इस क्षेत्र में, विशेषकर सीरिया में प्रमुख देश हैं, इसलिए यह समझौता पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगियों के प्रभाव को कम करने और क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के उनके प्रयासों को बढ़ावा दे सकता है।
- **ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र:** ईरान और रूस दोनों ऊर्जा संपन्न राष्ट्र हैं। तेल और गैस में उनका बढ़ता सहयोग वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बाधित कर सकता है।
- इसके अलावा, प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा में सहयोग दोनों देशों को अधिक उन्नत तकनीकी ढांचे विकसित करने की

अनुमति देगा, संभावित रूप से उन्हें पश्चिमी प्रौद्योगिकियों पर कम निर्भर बनाएगा और वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में उनके प्रभाव को बढ़ाएगा।

- **क्षेत्रीय सुरक्षा गतिकी:** यह संधि क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य को काफी प्रभावित कर सकती है, विशेषकर सीरिया जैसे संघर्ष क्षेत्रों में रूस और ईरान के संयुक्त प्रयासों के मद्देनजर। दोनों देशों का आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता के खिलाफ एकजुट मोर्चा पड़ोसी देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।
- **वैश्विक शक्ति संतुलन:** यह रणनीतिक साझेदारी एक नए वैश्विक ध्रुवीकरण की शुरुआत का संकेत दे सकती है, जिसमें रूस और ईरान प्रमुख देश के रूप में उभर रहे हैं। यह संधि अन्य गैर-पश्चिमी शक्तियों, विशेषकर चीन के साथ सहयोग को बढ़ावा दे सकती है, जिससे वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में बदलाव आ सकता है और शक्ति संतुलन में एक नया समीकरण स्थापित हो सकता है।

अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से वापसी

संदर्भः

हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय इस एजेंसी में 'अमेरिका विरोधी पूर्वाग्रह' को लेकर उठाई गई चिंताओं के आधार पर लिया गया था।

संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी के प्रभावः

- **प्रभाव में कमी:** संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी से परिषद में मानवाधिकारों पर होने वाली चर्चाओं और निर्णयों पर इसका प्रभाव कम हो जाएगा, जिससे इसकी प्रभावशीलता में कमी आएगी।
- **सख्त निगरानी में कमी:** सक्रिय अमेरिकी भागीदारी के बिना, अन्य सदस्य देशों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों पर निगरानी में कमी हो सकती है।
- **प्रथ्थककरण प्रवृत्तियाँ:** यह कदम प्रथ्थककरण की ओर संकेत करता है, जो वैश्विक शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अमेरिका की भूमिका को सीमित कर सकता है।
- **मित्र देशों पर प्रभाव:** इस वापसी को सहयोगी देशों द्वारा बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने के रूप में देखा जा सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सामूहिक प्रयासों पर नकारात्मक असर डाल सकता है।
- **वैश्विक मानदंडों पर प्रभाव:** संयुक्त राज्य अमेरिका का इन संगठनों से बाहर जाना अन्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर प्रश्न उठाने या उनसे पीछे हटने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे वैश्विक मानदंडों और मानकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में:

- **स्थापना:** संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) की स्थापना 15 मार्च 2006 को की गई थी, जिसने मानवाधिकार आयोग की जगह ली।
- **सदस्यता:** इसमें 47 सदस्य होते हैं, जिन्हें तीन वर्षों के लिए क्षेत्रीय समूहों के आधार पर चुना जाता है। सदस्य एक कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः चुनाव के लिए योग्य नहीं होते।
- **कार्य:** UN सदस्य देशों में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करना।
- **महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देना, जिनमें शामिल हैं:**
  - » **व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सभा का अधिकार:** व्यक्तियों के अपने विचार व्यक्त करने और शांतिपूर्वक सभा करने के अधिकार की रक्षा करना।
  - » **महिलाओं और LGBTI अधिकार:** महिलाओं और LGBTI व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना।
  - » **जातीय और नस्लीय अल्पसंख्यकों के अधिकार:** जातीय और नस्लीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना।